RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22 प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित, कुल पन्ने: 92 (कवर सहित)

OC

राज कुंद्रा प्रकरणः डर्टी पिक्चर

देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय

विपक्षः चलेगा ममता फॉर्मूला?

11 अगस्त, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

भारत-चीन

संयम की सीमा रेखा

विवादित उत्तरी सीमा पर दोनों देशों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस हरावल दस्तों की लगातार तैनाती के साथ बढ़ रहा है सैन्य संघर्ष का अंदेशा

www.indiatodayhindi.in

VISIT…

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं.'' यह बात करीब दो दशक पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कही थी. वे पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे. यह चीन पर भी लागू हो सकता था. 1950-51 में तिब्बत पर चीन के आक्रमण और कब्जे ने दोनों देशों को अपने उत्तर-औपनिवेशिक इतिहास में पहली बार पड़ोसियों में बदल दिया. उन्हें औपनिवेशिक ब्रिटिश और साम्राज्यिक चीन से विरासत में अनसुलझी सरहदें मिलीं, जो तिब्बत को वैसल स्टेट या कठपुतली देश मानते थे. भारत पूरे अक्साई चिन पर दावा करता है, जो चीनी प्रांत शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है. चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता और उसे 'दक्षिण तिब्बत' कहता है. सात से ज्यादा दशकों से समाधान दोनों ही पक्षों के हाथ नहीं लगा.

सरहद की इन भिन्न-भिन्न धारणाओं ने 1962 में सीमाई टकराव पैदा किया. मगर 1967 और 1975 की दो झड़पों के अलावा सरहद 45 सालों से खामोश थी. मई 2020 में यह बदल गया, जब चीन ने पीछे से जबरदस्त सैन्य लामबंदी के सहारे एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) की कई जगहों पर अचानक और अबूझ घुसपैठ कर ली. नतीजा पिछले साल 15 जुलाई को गलवान घाटी में हिंसक टकराव में हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और चीनी सेना के मुताबिक उसके कम से कम चार कर्मी मारे गए.

भारत को श्रेय देना होगा कि वह चीनी सेना की जोर-जबरदस्ती के आगे झुका नहीं और उसने सरहद पर सैन्यबल और साजो-सामान ले जाकर दिलेरी से जवाब दिया. जता दिया गया है कि एलएसी पर मई 2020 से पहले की स्थिति पूरी तरह बहाल किए बगैर रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते.

नौ महीनों के गतिरोध के बाद फरवरी में दोनों सेनाएं पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हट गईं. अलबत्ता रिश्ते ठंडे पड़ गए. विदेश मंत्री स्तर की वार्ताएं हुई हैं और कोर कमांडर स्तर की बातचीत का 12वां दौर जल्द होने की उम्मीद है. मगर यह शांति छलावा है. जमीन पर दोनों सेनाओं के रुख सख्त हो गए हैं. भारतीय सेना 50,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तानी सीमा से हटाकर चीन से सटे उत्तरी सीमांत पर ले आई है. चीन ने तिब्बती पठार पर सैन्य विमानन का बुनियादी ढांचा बढ़ाया है. वह मौजूदा हवाई क्षेत्रों का विस्तार और नयों का निर्माण कर रहा है. सबसे बड़ा नुक्सान है भरोसे का टूटना—चीन के एक सैन्य कदम ने 30 साल की बातचीत से विकसित सरहदी नियमों की धज्जियां उड़ा दीं.

19 जुलाई, 2017 का आवरण

1 जुलाई, 2020 का अवरण

बीते तीन दशकों के ज्यादातर वक्त चीन ने देंग शियाओ पिंग के 'अपनी ताकत छिपाओ और अपने वक्त का इंतजार करो' फलसफे का पालन किया. इसका मतलब था आर्थिक बाहुबल विकसित करने तक भूभागीय विवादों को टालते रहो. इस साल चीन का 140 खरब डॉलर जीडीपी अमेरिका से बस जरा ही कम है और असल में यह दशक खत्म होने से पहले वह उसे पीछे छोड़ सकता है. माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग मानते हैं कि उनके देश के लिए विश्व व्यवस्था में अपनी जगह हथियाने और तमाम भूभागीय विवाद निपटाने का वक्त आ गया है. एलएसी पर दावे के अलावा, उनका प्रमुख विवाद ताइवान के साथ है, जिसे बीजिंग बिगड़ैल प्रांत कहता है, और दक्षिण चीन सागर का वह समुद्री दालान, जिसे चीन पूरा का पूरा अपना भूभागीय समुद्र बताकर दावा करता है.

चीन ने शीत युद्ध के बाद किसी भी देश का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार शुरू किया और जता दिया है कि भूभागीय विवादों को निपटाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से उसे गुरेज नहीं है. यह भारत के लिए बुरी खबर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच अब तज दी गई अनौपचारिक बैठकें, जो 2018 में वुहान से शुरू हुई थीं, शायद भारत का वक्त हासिल करने का अपना तरीका थीं, ताकि हमारी उपेक्षित सरहदी रक्षा तैयारियों को मजबूत और हमारी सेना को आधुनिक बना सकें. उस प्रक्रिया को अब तेज करना होगा. अनसुलझा सीमांत बजट की मुश्किलों के वक्त न केवल और ज्यादा सैन्य संसाधनों की मांग करेगा बल्कि राजनैतिक नेतृत्व का ध्यान भी बंटाएगा. सैन्य टकराव की छाया तले कोई अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती.

आक्रामक चीन से निपटना राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है और चीन पर भारत की लगातार निर्भरता आर्थिक चिंता का सबब है. भारत-चीन का दोतरफा व्यापार पिछले साल 87.6 अरब डॉलर था और चीनी आयातों के पक्ष में बुरी तरह झुका था. वह निर्भरता इस साल और बढ़ गई, जब दोतरफा व्यापार पहले छह महीनों में ही 62.7 फीसद की छलांग लगाकर 57.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारत चीनी आयातों पर निर्भर है, पर चीन भारतीय आयातों पर नहीं. चीन के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी महज 2 फीसद है.

सरहद पर हालात सामान्य नहीं हैं. भारतीय और चीनी सैनिक इस फरवरी में केवल एक जगह से पीछे हटे. कम से तीन दूसरी जगहों पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले डटे हैं. सरहद पर दावा करने के लिए दोनों पक्ष एक बार हल्के हथियारबंद गश्ती दल भी भेज चुके हैं. अब उन्होंने बैटल टैंकों, तोपों, लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टर गनशिप के साथ भारी हथियारबंद व्यूहरचनाएं कर ली हैं. भरोसे का टूटना और गलतफहमियों से निबटने के लिए नए सैन्य नियम-कायदे नहीं होने का मतलब यह है कि एक भी गलती बढ़कर कहीं टकराव में न बदल जाए. बदतर यह कि हम पाकिस्तान और चीन से सटी दो सरहदों से दोचार हो सकते हैं, जो सामरिक गठबंधन से बंधे हैं. यह स्थिति कोई देश गवारा नहीं कर सकता. यही वजह है कि भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चारपक्षीय सुरक्षा संवाद में उत्साह से शामिल है. चीन के युद्धपिपासु रवैये के प्रति परस्पर घृणा, खासकर दक्षिण चीन सागर में, इन चारों लोकतांत्रिक देशों में साझा है.

हमारी पाकिस्तान के साथ एलओसी (नियंत्रण रेखा) और चीन के एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) है, लेकिन अपनी कूटनीतिक शब्दावली में हम एक और छोटा नाम जोड़ना गवारा नहीं कर सकते और वह है—एलओएनसी (अनियंत्रण रेखा). यही हमारी आवरण कथा है जो मैनेजिंग एडिटर संदीप उन्नीथन ने लिखी है. यह सरहद पर इस खतरनाक खेल का जायजा लेती है. भले ही यह सरहद तक सिमटा हो, लेकिन युद्ध साफ तौर पर भारत और चीन के बीच विकल्प नहीं है. दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देशों को अपने लोगों की भलाई का जतन करना है, तो एलएसी को शांत और तय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाना ही होगा. यही इस खेल की आखिरी अकेली पायदान है, जिसकी दिशा में दोनों देशों को काम करने की जरूरत है.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 37; 5-11 अगस्त 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

भीतर

सुर्खियां
विपक्ष: गठबंधन का तानाबाना
पेज 8

अर्थात्: पाखंड के आर-पार
पेज 32

फुरसत
सिनेमा: अनसुनी कहानियां सुनाएंगी निर्माता बनीं अभिनेत्रियां
पेज 86

सवाल-जवाब/राकेश ओमप्रकाश मेहरा: हिंदुस्तान की कहानी
पेज 90

38

राहुल उमराव

आवरण कथा

वास्तविक अनियंत्रण रेखा

चीन तिब्बत के पठार पर अपने हवाई ठिकाने और सुविधाएं बढ़ा रहा है, जबकि भारत अपनी टुकड़ियों की तैनाती में नया संतुलन बना रहा. ऐसे में हल्की गलतफहमी भी टकराव के मोर्चे खोल सकती है.

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

कांग्रेस

34 कमान संभालने की जद्दोजहद

राहुल गांधी पार्टी में कई स्तरों पर फेरबदल लाकर एक नई टीम बनाने की कोशिश में जुटे हैं. क्या वे सफल हो पाएंगे?

बेस्ट यूनिवर्सिटी

49 दौड़ में आगे

बदलती जरूरतों के मुताबिक तेजी से ढलने में सफल यूनिवर्सिटी सबसे अगली कतार में.

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

JOIN INDIA'S MOST VIBRANT INSTITUTION

We are geared up with both online and offline education so that you do not lose out on quality education and experience

VIT®

Vellore Institute of Technology
(Deemed to be University under section 3 of UGC Act, 1956)

PROGRAMMES OFFERED

VELLORE CAMPUS

- **B. Arch.**
- **B. Des.** Industrial Design
- **B.Sc.** (Hons.) Agriculture
- **B.Sc.** Catering and Hotel Management
- **B.C.A.**
- **B.Com.**
- **B.B.A.**
- **B.Sc.** Computer Science
- **B.Sc.** Multimedia and Animation
- **B.Sc.** Visual Communication

CHENNAI CAMPUS

- **B.A.**
- **B.A., LL.B.** (Integrated)
- **B.B.A., LL.B.**
- **B.Com.** (Honours)
- **B.Sc.** (2 Majors and 1 Ancillary from Physics, Chemistry and Mathematics)
- **B.Sc.** Mathematics and Computing
- **B.Sc.** Fashion Design
- **B.B.A.** (Hons.) (2+2) (In collaboration with RIT, USA)

Education opens up the mind and allows you to improve your life in so many ways.

At VIT, we believe it is crucial to provide students with an environment that positively influences their thoughts, stimulates their interest and encourages learning in different settings. Our programmes are structured in line in with the changing times. Our faculty and infrastructure are geared to be future ready. And, our students learn and imbibe lifelong values that equip them to be futuristic.

IoE
Recognized as an **Institution of Eminence*** by Govt. of India

TOP 20
NIRF rankings past 4 years*
(HRD Ministry, Govt. of India)

3245+
Total Number of **Super Dream** and **Dream offers**

*Vellore and Chennai Campus

+ Inclusive of Internship Offers

SAP
SEMESTER ABROAD PROGRAMME
Final semester at a Partner University

300+
INTERNATIONAL PARTNER UNIVERSITIES
(Europe, America, Asia, Australia etc.)

INTER LINKED CURRICULUM
With partner universities abroad

Find Your Future and Explore New Possibilities at

www.vit.ac.in

vituniversity | VIT_univ | vellore-institute-of-technology
vellore_vit | VITUniversityVellore

असमः मिजोरम संघर्ष
सीमा पर संघर्ष
पेज 12

उत्तराखंडः देवता
पर दावा!
पेज 20

सुर्खियां

झारखंडः सरकार गिराने का
खेल ऐसे हुआ फेल
पेज 22

बिहारः अब गहन मंडल
युग की ओर
पेज 28

एएनआइ

एक और कोशिश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के बाद बाहर निकलतीं ममता बनर्जी

विपक्ष

गठबंधन का तानाबाना

रोमिता दत्ता

ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तस्वीर के साथ एक ट्वीट 25 जुलाई को कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चर्चित टिप्पणी 'आप क्रोनोलॉजी समझिए' को टेक की तरह दोहराते हुए एक छोटी-सी कैफियत थी. जाहिर तौर पर शाह ने विपक्ष पर संसद ठप करने की साजिश का आरोप लगाया था. लेकिन इस ट्वीट में उन्हीं की टिप्पणी का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव 2021 के बंगाल चुनाव के दौरान पेगासस स्पाइवेयर का शिकार हुए. ट्वीट के लिए चुना गया वक्त भी कोई इत्तफाक नहीं था. साल 2024 में भाजपा से निपटने के लिए संभावित रणनीति पर विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ममता अगले दिन राष्ट्रीय राजधानी के पांच दिनों के दौरे पर आ रही थीं.

ममता ने 28 जुलाई की शाम सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसे उन्होंने 'चाय पे चर्चा' कहा और इस तरह अपने सियासी विरोधी पर निशाना साधा. बाद में रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'होप 24' की खातिर मोदी-विरोधी गठबंधन का तानाबाना बुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष भी बराबर उत्सुक हैं. होप 24, यानी '24 की उम्मीद, अगले आम चुनाव को ममता का दिया उपनाम है. उन्होंने कहा, ''हमने 'अच्छे दिन' बहुत देख लिए, अब हम 'सच्चे दिन' देखना चाहते हैं.''

कांग्रेस, टीएमसी और दूसरी समानधर्मा पार्टियों ने पहले भी भाजपा की प्रचंड ताकत का मुकाबला करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय विपक्ष की जरूरत को लेकर काफी हो-हल्ला मचाया है. खासकर तब तो और भी जब भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए तीन-तिकड़म से गुरेज नहीं किया. तो इस बार क्या फर्क है? अपने राज्य में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद अपनी

AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
School of Engineering

AMRITAPURI • BENGALURU • CHENNAI • COIMBATORE

4TH BEST UNIVERSITY nirf

RECOGNISED AS INSTITUTION of EMINENCE BY THE UGC

95% STUDENTS PLACED in 2020

₹66 LAKH P.A. HIGHEST CTC

₹6 LAKH P.A. AVERAGE CTC

50% SEATS WITH SCHOLARSHIP

You can still apply with JEE Mains score

Last Date To Apply
15 August 2021

amrita.edu/btech
Apply Online
+91 94437 97777
Helpline Number

Apply with your best scores from
- AEEE 2021
- JEE Mains 2021
- SAT
- PUEE

SCAN TO APPLY

#CLAIMYOURFUTURE WITH CUTTING-EDGE B.TECH PROGRAMMES

- Aerospace
- Civil
- Computer Science
- Computer Science (Cyber Security)
- Electrical & Electronics
- Chemical
- Computer & Communication
- Computer Science (A.I.)
- Electrical & Computer
- Mechanical
- Electronics & Computer
- Electronics & Communication

INTRODUCING B.Tech in Automation & Robotics Engineering

The B.Tech Programmes are offered across 4 campuses of Amrita School of Engineering

A ONE-OF-A-KIND INITIATIVE

FOR 2022 ENGINEERING ASPIRANTS

DF/115

AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
BRIDGE +2

SHORT, FOCUSED LEARNING PROGRAMMES DESIGNED TO TRANSITION +2 STUDENTS INTO ENGINEERING.

Enroll Online
amrita.edu/epf
Programme Extended Till March 2022

SCAN TO ENROLL

CERTIFICATE PROGRAMME

Engineering Foundation
Bridging the gap between science and technology among high school students who aspire to become engineers.

UPSKILLING PROGRAMME

Tech Talks
Sessions on futuristic technologies like IoT, Robotics, A.I. and M.L. by the experts from Amrita School of Engineering, Chennai.

Education for Life. Education for Living.

सत्ता को बचाने के बाद ममता इस ओर बढ़ी हैं. इस प्रक्रिया में उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें मोदी की भाजपा को चुनौती देने की हिम्मत है. इस बार इस जमावड़े में कुछ और अहम खिलाड़ी भी आ जुटे हैं. मसलन, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) जिन्होंने बंगाल में ममता की जीत में उनकी मदद की. किशोर देश भर के विपक्षी नेताओं से मुलाकात में व्यस्त हैं. वे एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार से भी मिले. साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश में पवार भी सक्रिय हैं.

इस बीच 28 जुलाई को दिल्ली स्थित बंग भवन में विपक्षी नेताओं की बैठक का ममता का बड़ा मनसूबा भले परवान न चढ़ सका, पर अलग-अलग कई नेता उनसे मिलने आए. इनमें कांग्रेस के कमलनाथ और आनंद शर्मा भी थे. वे आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलीं और संजय राउत (शिवसेना) तथा अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी) के साथ भी उनकी मुलाकात तय हैं.

हालांकि कई पर्यवेक्षक अभी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यह सारा शुरुआती उत्साह वाकई भाजपा के लिए वास्तविक खतरे में तब्दील हो पाएगा. समाज विज्ञानी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस प्रशांत रे कहते हैं, ''मैं कुछ पकता हुआ देख सकता हूं और दोनों पार्टियां साझा लक्ष्य (मोदी की हुकूमत का खात्मा) की तलाश में अपने मतभेद छोड़ने को राजी दिखाई देती हैं.'' वे ध्यान दिलाते हैं कि इससे पहले कांग्रेस कभी-भी अपने दंभ और गुरूर के घोड़े से नीचे नहीं उतरी थी और किसी दूसरी पार्टी के नेता का नाम सामने नहीं रखा था.

कुछ पक रहा है

इससे पहले 13 जुलाई को दिल्ली में जब किशोर राहुल गांधी के घर गए और उनके, प्रियंका तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के. सी. वेणुगोपाल और हरीश रावत (पंजाब मामलों के प्रभारी) के साथ लंबी बैठक की, तो दिल्ली में कानाफूसी शुरू हो गई. नतीजा यह हुआ कि पी. चिदंबरम और दिग्विजय सिंह सरीखे शीर्ष कांग्रेसी नेता 21 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में टीएमसी की सालाना शहीद दिवस रैली में दिखाई दिए. इस रैली को ममता ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और इसमें मौजूद दूसरे नेताओं में पवार और सुप्रिया सुले (राकांपा), राम गोपाल यादव (सपा), मनोज झा (राजद), तिरुचि शिवा (द्रमुक) और प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना) भी थे. ममता ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताने में जरा देर नहीं की और साल के आखिर में बंगाल में विपक्ष की महारैली का न्यौता भी फटाफट भेज दिया.

एक महीने पहले टीएमसी ने बंगाल में एक नए नारे का आगाज किया था, 'भारत निजेर मेके चाय (भारत अपनी बेटी चाहता है)'. यह 'बंगाल निजेर मेके चाय (बंगाल अपनी बेटी चाहता है)' नारे का ही तार्किक विस्तार था, जिसने महज कुछ महीनों पहले इतनी जबरदस्त जीत दिलाई थी. टीएमसी संभावनाएं टटोलती नजर आ रही है, क्योंकि जल्द ही सोशल मीडिया पर #बंगाली प्राइममिनिस्टर घूमने लगा. मगर दिल्ली आते ही ममता ने अपनी

अपने तीसरे कार्यकाल में व्यवस्थित हो जाने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले प्रशांत किशोर को विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने के काम में जुटा दिया

राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की तमाम अफवाहों को किनारे लगा दिया. सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद उनसे पूछा गया कि अगर विपक्ष का पचमेल गठबंधन बन भी गया तो उसकी अगुआई कौन करेगा. उन्होंने दो-टूक जवाब दिया, ''मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर कोई दूसरा भी नेतृत्व करता है. जब इस पर बात होगी, हम फैसला कर सकते हैं. मैं किसी पर कुछ थोप नहीं सकती हूं.''

बंगाल का चुनाव हाल का बहुत बारीकी से देखा-परखा गया चुनावी मुकाबला था. कई सारे नेताओं—जिनमें पवार, राजद के नेता तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, द्रमुक के एम.के. स्टालिन शामिल थे—ने न केवल इसमें गहरी दिलचस्पी ली बल्कि चुनाव आयोग के कथित 'मनमानेपन' के खिलाफ ममता के साथ डटकर खड़े रहे. इन सभी ने जीत के बाद ममता की खूब तारीफ की.

टीएमसी के अंदरूनी जानकारों का कहना है कि मोदी-शाह के नेतृत्व में भाजपा जब ममता की सरकार और पार्टी के खिलाफ आक्रामक चुनाव अभियान चला रहा था, तो पवार ने उन्हें बहुत ढाढस बंधाकर शांत किया और उनका मार्गदर्शन किया था. आज, वाम मोर्चे सरीखे पुराने दुश्मन भी ममता के साथ काम करने को राजी हैं. मई में सीबीआइ के हाथों तीन टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बोलते हुए माकपा के वरिष्ठ नेता विमान बोस ने ऐसा कहा भी.

जीत का फॉर्मूला

अपने तीसरे कार्यकाल में रचने-बसने के बाद ममता का पहला कदम यह था कि उन्होंने किशोर को विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने के काम में लगा दिया. बताया जाता है कि पवार और भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, जो अब टीएमसी में आ गए हैं, इसमें उनकी मदद कर रहे हैं. सिन्हा कहते हैं, ''हम सबसे अच्छे को अच्छे का दुश्मन नहीं बनने दे सकते. एक बात साफ है कि कांग्रेस के बिना कोई प्रभावी विपक्षी गठबंधन नहीं बन सकता है.'' हो सकता है, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ किशोर की हालिया मेल-मुलाकात ने भी धुंध छांटने में मदद की है. मगर इस बीच बेसुरे राग भी कायम हैं. यहां तक कि ममता जब दिल्ली में थीं, राहुल गांधी ने सदन में विपक्ष की संयुक्त रणनीति तय करने के लिए संसद में बैठक बुलाई. उस बैठक में चौदह पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन टीएमसी का कोई नुमाइंदा उनमें नहीं था.

अभी तक ममता का फॉर्मूला सीधा-सादा है और यह वही है जो उन्होंने बहुत पहले जनवरी 2019 में आम चुनावों से भी पहले विपक्ष की महारैली में सामने रखा था. जिन जगहों पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है, वहां गठबंधन के दूसरे दलों को मिलकर अपना समर्थन कांग्रेस को देना चाहिए. मगर जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा को चुनौती देने की मजबूत स्थिति में हैं, वहां कांग्रेस को उनके लिए मैदान खुला छोड़ देना चाहिए. उस वक्त सार्वजनिक तमाशे के अलावा, यह परवान नहीं चढ़ पाया.

इस बार पवार और सिन्हा सरीखे दिग्गज नेता अलग-अलग सियासी पार्टियों और असमान विचारधाराओं को जोड़ने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) पर काम कर रहे हैं. विवादास्पद कृषि कानून, पेगासस जासूसी मामला, महंगाई, तेल की कीमत और बेरोजगारी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें संसद में भाजपा पर दबाव डालने के लिए सीएमपी के हिस्से के तौर पर उठाया जा सकता है. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कसरत कितनी दूर तक जाती है, लेकिन अगर यह क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हो गईं तो तो भाजपा को 2024 में जोरदार टक्कर मिल सकती है. ■

www.rntu.ac.in | Follow us on

Rabindranath TAGORE UNIVERSITY™

MADHYA PRADESH, BHOPAL AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Approved by : AICTE, NCTE, BCI, INC, MP PARAMEDICAL COUNCIL, | Recognized by : UGC | Member of : AIU, ACU

Rank Band 151-200 University Category in nirf 2020

GREAT PLACE TO STUDY CERTIFICATION 2019-20

ACCELERATING with changing times.

Unlimited access to eLearning materials with Learning Management System (LMS)

- 10,000+ students registered
- 500+ faculties conducting online classes
- 4,500+ classes conducted

*AGU unified LMS

Striving to make you future ready.

PROGRAMMES OFFERED

Engineering & Technology | Management | Humanities & Liberal Arts Education | Computer Science & IT | Law | Commerce | Nursing & Paramedical Science | Agriculture | Science | B.Voc. & M.Voc. Mass Communication & Journalism

Ph.D. in selected subjects through separate entrance tests

Integrated future-ready courses in association with

AISECT FUTURE SKILLS ACADEMY | coursera Access to World Class Online Learning Programmes | Red Hat | Micro Focus Software University Build the Skills to Succeed

Industry Partners & Learning Partners

Acxiom Consulting | AIS Asahi India Glass Ltd. | Biome Technologies | BYJU'S | Collabera | CIS | DAAWAT | EduSkills | genpact | hitech | IFFCO KISAN | ISC Software | jaro education | Jayaswal Neco Industries Limited

and many more...

AIC-RNTU ATAL Incubation Centre, Rabindranath Tagore University Supported by: ATAL Innovation Mission, NITI Aayog

Rishi Tagore Scholarship

University's Radio Channel Yuvaaz Youth Ki Awaaz www.aisectyuvaaz.com

International Partners

- International Centre of Excellence in Water Resources Management (ICE WaRM), Australia
- MOI University, Kenya
- Brno University of Technology, Czech Republic
- Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), USA
- Institute of Asian and African Studies, Moscow State University
- Nepal Academy of Science and Technology (NAST)
- KYIV, Ukraine Environmental Engineering Experts

Centre of Excellence for Research

- Centre for Incubation, Entrepreneurship & Start-ups
- Centre for Science & Communication
- Centre for Advance Material
- Centre for Agriculture
- Centre for Environmental Science
- Centre for Renewable Energy
- Tagore International Centre for Arts & Culture
- Centre for Innovation in IoT
- Sanskrit evem Prachya Bhasha Shikshan Kendra
- Pravasiya Bhartiya Sahitya evem Sanskruti Shodh Kendra

And Many More....

Honoured for Hardwork

- 1st Rank Private University 2020 in Bhopal — INDIA TODAY
- 1st Rank Private University in Madhya Pradesh 2020 — Outlook
- 1st Rank Multidisciplinary Private University in Madhya Pradesh — THE WEEK
- AAA Rated Universities under Fastest Growing Academic Hub — CAREERS360
- 1st Rank All India for Best Academia Industry Alliance 2021 — EducationWorld

ADMISSIONS OPEN 9993006401, 8109578044, 8878852348, 9319866685

Rabindranath Tagore University : Bhopal – Chiklod Road, Near Bangrasia Chouraha, Bhopal, Madhya Pradesh, India
Ph. : +91-755-2700400, 2700413

City Office : 3rd Floor, Sarnath Complex, Opposite to Board Office, Link Road No. 1, Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Ph. : +91-755-4289606 | Email: info@rntu.ac.in

SCAN FOR THE WEBSITE www.rntu.ac.in

टकराव
असम और मिजोरम की सीमा पर लैलापुर में 26 जुलाई को हिंसक संघर्ष हुआ

एएनआइ

असम-मिजोरम संघर्ष

सीमा पर संघर्ष

कौशिक डेका

असम और मिजोरम के बीच विवादित लैलापुर-वैरेंगटे सीमा पर 26 जुलाई को हिंसक झड़प के परिणामस्वरूप छह असम पुलिस कर्मियों की मौत की घटना भारत के पूर्वोत्तर के रूप में जाने जाने वाले सात भारतीय राज्यों के बीच बढ़ते तनाव की गंभीर चेतावनी है. इस क्षेत्र में अंतरराज्यीय सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है लेकिन जो बात इस घटना को अनोखा बनाती है वह है, दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच संघर्ष और मिजोरम पुलिस की ओर से असम पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी के लिए लाइट मशीन गन का उपयोग.

जैसा कि अपेक्षित था, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिंसा शुरू करने के लिए दूसरे पक्ष के पुलिस बलों को दोषी ठहराते हुए तुरंत राजनैतिक छींटाकशी शुरू कर दी. जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तनाव शांत करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मिजोरम समकक्ष जोरमथंगा को फोन किया, वहीं एनडीए सदस्यों की ओर से संचालित दो राज्य सरकारों के प्रमुखों—असम में भाजपा और मिजोरम में एमएनएफ (मिजो नेशनल फ्रंट) के बीच सोशल मीडिया पर विवाद दर्शाता है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है. यही नहीं, सरमा इस क्षेत्र में सभी गैर-कांग्रेसी पार्टियों के संगठन पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी हैं, जिनमें एमएनएफ भी शामिल है.

विडंबना यह है कि शाह की पूर्वोत्तर यात्रा के दो दिन बाद ही ये झड़पें हुईं, जिस दौरान उन्होंने शिलांग में इस क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें 2022 तक सभी अंतरराज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए कहा, जब भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाएगा. यह अब असंभव लक्ष्य लगता है—असम अब मिजोरम के साथ लगी

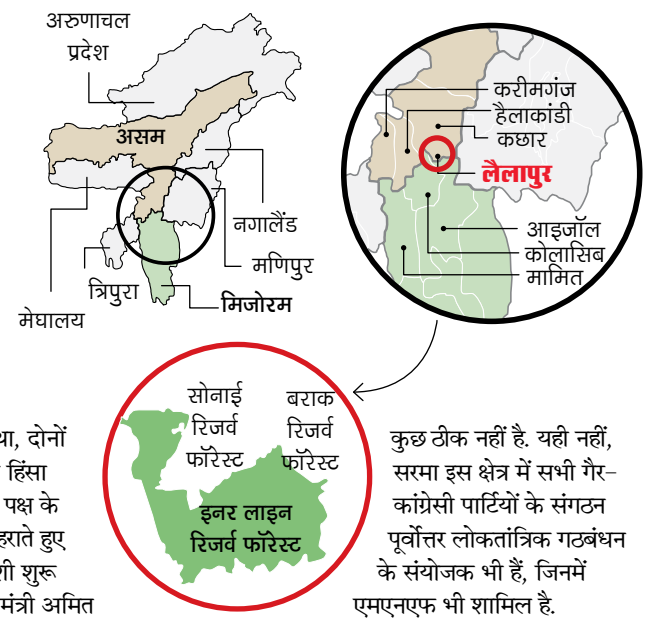

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

सीमा की रक्षा की खातिर 4,000 कमांडो तैनात करने के लिए तैयार है. ऐसे में संभावना नहीं दिखती कि अगले एक साल में इसका कोई राजनैतिक समाधान निकल आएगा.

26 जुलाई की झड़प का स्थल असम के कछार जिले के लैलापुर और मिजोरम के कोलासिब जिले में वैरेंगटे के बीच की सीमा है. पिछले अक्तूबर में यहां नागरिकों के बीच इसी तरह की झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगाया था. उसी महीने, असम के करीमगंज जिले और मिजोरम के ममित जिले की सीमा पर भी झड़पें हुईं (देखें नक्शा). असम, मिजोरम के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे पहले असम के एक जिले लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था.

दरअसल, 1875 में भारत के ब्रिटिश शासकों ने मिजो सरदारों के साथ सीमा संधि की थी, जो कछार के मैदानों से लुशाई पहाड़ियों—तब एक स्वतंत्र क्षेत्र था—का सीमांकन करती थी. 1890 में लुशाई हिल्स क्षेत्र पर ब्रिटिश भारत ने कब्जा कर लिया. वर्ष 1933 में लुशाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी. मिजोरम को 1972 में असम से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था; 1987 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया. मिजोरम जहां 1875 के सीमांकन को स्वीकार करता है, क्योंकि उस निर्णय में मिजो लोगों से सलाह ली गई थी, वहीं असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करने पर जोर देती है.

हालांकि, हालिया संघर्ष सीमा दावों और ऐतिहासिक समझौतों की तुलना में ज्यादातर भूमि और वन अधिकारों पर असहमति के कारण हुए हैं. वर्तमान विवाद के केंद्र में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट है, जो 509 वर्ग किमी में फैला असम और मिजोरम के बीच की प्राकृतिक सीमा को कवर करता है. यह निचली पहाड़ियों से बना है, जो लुशाई पहाड़ियों का उत्तरी ऊंचाई वाला इलाका है, यह असम में कछार और हैलाकांडी जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है, जो मिजोरम और मणिपुर की सीमा पर है. असम की तरफ से दावा किया गया है कि मिजोरम एक ऐसी सड़क का निर्माण कर रहा है जो असम के अंदर आरक्षित वन को नष्ट कर रही है. इसी तरह, करीमगंज में अक्तूबर 2020 में सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व के आसपास झड़प हुई, जो दस्तावेजों में असम के अधिकार क्षेत्र में है.

मिजोरम के इतिहासकारों का दावा है कि ये वन क्षेत्र मिजो जनजातियों के शिकार के मैदान थे और सीमा के दोनों किनारों पर लोग सदियों से शांतिपूर्वक मिल-जुलकर रहते थे. मिजोरम विश्वविद्यालय में इतिहास और नृवंशविज्ञान विभाग के प्रोफेसर ओरेस्टेस रोसंगा कहते हैं, ''ये झड़पें हालिया घटनाएं हैं, जो शायद राजनैतिक प्रेरणाओं को दर्शाती है.'' हालांकि, असम के लोग राजनैतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की खातिर संघर्ष को भड़काने के लिए मिजोरम में नागरिक समूहों को दोषी ठहराते हैं. कई लोगों का दावा है कि 2018 में जोरमथांगा के सत्ता में आने के बाद से इस तरह की झड़पों में वृद्धि हुई है—जिनकी राजनैतिक विशेषता मिजो पहचान के दावे पर निर्भर है—क्योंकि वे मिजोरम में छात्र समूहों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं. गैलरी में खेलते हुए, उनके एमएनएफ सहयोगी और राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना ने 28 जुलाई को संसद के बाहर गरजते हुए कहा, ''अगर वे (असम पुलिस) फिर से आए, तो हम उन सभी को मार देंगे.'' असम के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका का कहना है कि ''छात्र समूहों सहित कई नॉन-स्टेट ऐक्टर्स राज्य में राजनैतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं.'' मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान असम पुलिस ने मिजोरम के सर्वोच्च छात्र निकाय मिजो जिरलाई पॉल (एमजेडपी) के सदस्यों की ओर से बनाई गई एक झोपड़ी को गिरा दिया. झोपड़ी कथित तौर पर असम की धरती पर खड़ी थी और चुनावी मुद्दा बन गई थी.

हालिया संघर्ष सीमा पर दावों के बजाय भूमि और वन अधिकारों पर असहमति के कारण ज्यादा हुए हैं

इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शिलांग में मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने जोर देकर कहा कि ''असम की तरफ से जिन क्षेत्रों पर दावा किया गया है, उनका बड़ा हिस्सा मिजोरम की संवैधानिक सीमा के भीतर हैं'' और मिजोरम के लोग 100 साल से ज्यादा अरसे से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि असम ने इन क्षेत्रों पर इसलिए दावा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनसंख्या दबाव स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर प्रवासियों की आमद के कारण होता है. मिजोरम में सिविल सोसाइटी समूह अधिक स्पष्टवादी रहे हैं. एमजेडपी के अध्यक्ष बी. वनलालताना कहते हैं, ''बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी हमारी पारंपरिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरी समझ में नहीं आता कि असम सरकार उनका समर्थन क्यों कर रही है.'' लेकिन असम सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री सरमा कहते हैं, ''असम जंगल की रक्षा करना चाहता है. वह वन क्षेत्र में किसी भी बस्ती की अनुमति नहीं दे रहा है और वहां कभी भी कोई बस्ती नहीं बनने देगा.'' असम पुलिस के सूत्रों का दावा है कि मिजोरम के निवासी खेती के लिए इन वन क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री सरमा इसे राज्य सरकार के हाल में नशीली पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियानों के परिणाम के रूप में भी देखते हैं. मणिपुर और मिजोरम के रास्ते म्यांमार से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ असम और देश के बाकी हिस्सों में आते हैं. पिछले दो महीनों में, असम पुलिस ने 163 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को जब्त किया है और लगभग 1,500 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है. राज्य सरकार ने राज्य से होकर मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किया है. असम से बांग्लादेश और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में फल-फूल रहे पशु तस्करी व्यवसाय पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है. केंद्र सरकार के अनुसार, सीमा सुरक्षा बलों ने 2016 और 2020 के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा पर 4,76,035 मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया. मुख्यमंत्री सरमा कहते हैं, ''इन कदमों से असामाजिक तत्व बौखला गए हैं. निश्चित तौर पर ऐसे प्रयास होते रहेंगे. इसलिए मैंने यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है कि नागरिक असम पुलिस का हथियारों से कैसे सामना कर सकते हैं. यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि उन्हें हथियार किसने मुहैया कराए.''

जहां तक 26 जुलाई को हुई दोनों राज्यों की पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प की बात है तो जांच से पता चल सकता है कि किसने पहले गोली चलाई, लेकिन बातचीत में उन क्षेत्रों के निवासियों को शामिल करने से ही स्थायी समाधान हो सकता है. केंद्र की तरफ से क्षेत्र में सभी सीमा विवादों के दस्तावेजीकरण के लिए इस साल जून के महीने में एक समिति बनाकर विवादों को सुलझाने की अपनी मंशा दिखाई गई है. इस प्रक्रिया में तेजी लाने से मदद मिल सकती है, हालांकि संपत्ति पर परस्पर व विरोधी दावों और आजीविका का पेचीदा सवाल इन विवादों को काफी कठिन बना देता है. लेकिन इस समस्या का समाधान जल्द करना समय की मांग है. ■

SRM
INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act, 1956)

GIVE WINGS TO YOUR DREAM WITH A DEGREE IN SRM

SRM Institute of Science and Technology (formerly known as SRM University) is accredited with the highest grade of A++ by NAAC and graded by UGC/MHRD as Category I university with 12 B status. All Engineering, Pharmacy, Architecture, and MBA programs are approved by AICTE and programs under Health Sciences are approved by various Statutory Bodies of India. SRMIST has secured the second rank in the Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA-2020). SRMIST is ranked globally by QS and rated by QS with '4 Star' globally and awarded India centric QS IGAUGE Diamond rating.

SRMIST carries out cutting edge research in frontier areas with more than 238 government-funded research projects at an outlay of Rs.150 Crores. It has 23 both national and international patents also. The institute recently opened Sir C V Raman Research Park at an estimate of Rs.120 crores with state-of-the-art equipment. The facility was opened by Hon'ble Minister of HRD, Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank'.

The University functions from five campuses in the country, namely, at Kattankulathur in Chengalpattu district, Tamil Nadu, Ramapuram and Ramapuram Part (Vadapalani) in Chennai city , Modi Nagar, in NCR New Delhi, and at Tiruichirappalli (Irungalur), built over a total land area of about 400 acres with a built-up area of over 12 million square feet.

SRMIST has over 50,000 students and nearly 3,300 faculty across all the campuses offering a wide range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in Engineering, Management, Medicine and Health Sciences, Hotel Management, Science and Humanities, Agricultural Sciences and School of Law. The curriculum and syllabus are outcome based with specialized programs even at undergraduate level. The University offers 5 year M.Tech integrated programs under Engineering. At the Kattankulathur campus, Five engineering programs have been accredited by ABET, USA (www.abet.org), and another four Engineering programs by IET, UK. It has more than 1000 international students from 64 countries studying in various programs.

In addition to the academic spaces, there are around 45 hostels that house more than 15,000 students inside the campuses. The academic infrastructure includes all modern classrooms, laboratories, studios, conference halls, seminar rooms, open workspaces, computer labs, etc. The Central Library of the University houses over three lakhs books, 40,777 e-books among other e-journals and journals.

For the need of common researchers, SRMIST has established a high-performance computing facility with 73 teraflops. A good number of students come from various parts of Chennai and the institute has made adequate transport facilities through 125 buses plying on a daily basis. For all-round development of students, excellent sports facilities like an indoor stadium, synthetic courts, football and cricket grounds, gymnasium, other indoor and outdoor sports facilities are available.

SRMIST is a green, clean, and energy-efficient campus. Solar energy is one of the major sources of power in the institution. The energy generated from it is used to power solar water heaters and solar steam cooking installed in hostels. Battery-driven vehicles are also available in the institution.

Dr. T.R. Paarivendhar,
Founder Chancellor
SRM Group of Institutions.

SAP

Around 200 meritorious students, every year, under Semester Abroad Program (SAP), go to reputed universities abroad for a semester of study funded by SRMIST.

PLACEMENTS

SRMIST is the place that comes first to the minds of recruiters during the placement season. The process

is enhanced every year by constantly exploring opportunities to engage with corporates through multiple touch points including Faculty Development Programs, Curriculum Development, establishing Centres of Excellence, Hackathons, Seminars, Competitions etc.
On average, 600 companies from all over India participate in campus placement programs every year. Reputed companies that have been associated with SRMIST are TCS, Infosys, CTS, Wipro, Accenture, LTI, IBM, Amazon, WorkIndia, MotorQ, Arcesium, DE Shaw, Paypal, Direct i, Barclays, Amadeus, Nielsen, Commvault, Oracle, Adobe, Capgemini, Deloitte, Bank of America, ZS Associates, Fractal Analytics, EY and many others . Even among the the core sectors, companies such as HeroMotocorp, Reliance Industries, Akzonobel, HUL, IFB, Siemens, Titan, Ceat, Hitachi ABB, Fiat, Linde, Schneider, TATA Chemicals, L&T group, Cummins, KPIT, Adani Group, Nilkamal visit SRMIST every year.

Our records this year are:

- 7111+ offers and counting
- 2000 Super Dream & Dream offers

INDUSTRY AWARDS

SRMIST has received several recognitions that are of National and International importance. This QS-IGauge Diamond rated institute has been the recipient of:

- STEM Impact Award
- Green Metric Award
- AICTE-CII Award for Best Industry-linked Institution for Electrical Engineering and Allied Institute,
- University of the Year Award 2019 from FICCI and three Swachhata ranking awards from AICTE
- No.1 under category of AICTE – Residential Universities
- Clean and Smart Campus Award
- 'One student One tree' campaign, where 50,000 saplings were planted in 26 villages.

OUR PRIDE

SRMITE first Indian woman sailor to qualify for Olympics

SRMIST student Nethra Kumanan (23) has become the first Indian woman to qualify for the Olympics. She will be representing India in sailing. She qualified for the Tokyo Olympics by coming first at the Laser Radial event in the Mussanah Open Championship, a joint Asian and African Olympic qualifying event.

As a second-year engineering student of SRM, she has represented the country at the 2014 and 2018 Asian Games in Incheon and Jakarta, respectively. She became the first Indian woman to win a World Cup medal in sailing when she clinched a bronze medal at the 2020 Sailing World Cup in Miami, USA. She trains in the Canary Islands, Spain.

CAMPUS LIFE

Over 400 acres replete with a variety of facilities, State-of-the-art labs, libraries, Wi-Fi, knowledge center, 4000 capacity AC auditorium, 100 online smart classrooms, boys and girls hostels with premium facilities, endless convenience on campus including ATM's, bookstores, dining options, cafeterias, prayer halls, gym and more. The students are engaged with community radios, student clubs, cultural events, fitness centers and prayer halls.

SCHOLARSHIPS

Every year 3200+ students avail themselves of various scholarships to the tune of Rs. 47 Crores

FOR ADMISSIONS

For students/parents who need support and guidance, our counselors may be contacted via our Helpdesk: +91 (044) 27455510, 47437500, 67370700, from Monday to Saturday (except public holidays), between 9 am and 5 pm or by email to admissions.india@srmist.edu.in.

To apply to our B. Tech/M.Tech and other programs visit www.srmist.edu.in for more details.

कर्नाटक

अखिर चली येदियुरप्पा की

2023 के विधानसभा चुनावों के लिए अहम लिंगायत मतों पर नजर रखते हुए भाजपा ने येदियुरप्पा के वफादार बासवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना

अरविंद गौड़ा

एएनआइ

बदली भूमिका
27 जुलाई को भाजपा की तरफ से कर्नाटक का सीएम चुने जाने पर पर बासवराज बोम्मई को सम्मानित करते बी.एस येदियुरप्पा

अपनी सबसे बड़ी सियासी पराजय में भी कर्नाटक के भाजपाई दिग्गज बी.एस. येदियुरप्पा की ही चली. उनके वफादार, 61 साल के बासवराज एस. बोम्मई को 27 जुलाई को नया मुख्यमंत्री चुना जाना यही संकेत करता है कि 'रिटायरमेंट' के बाद भी राज्य में येदियुरप्पा की ही चलेगी और केंद्रीय नेतृत्व उनकी अनदेखी नहीं कर सकता. लिंगायतों में, जिनकी कुल वोटरों में हिस्सेदारी कोई 17 फीसद है, भाजपा के कद्दावर नेता के तौर पर येदियुरप्पा 2023 में सत्ता में वापसी के लिए पार्टी के लिए अहम पत्ते हैं.

78 साल के येदियुरप्पा उन कुछ गिने-चुने नेताओं में हैं जो भाजपा के 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति के अलिखित नियमों से परे जाकर भी पद पर बने रहे. उनकी अहमियत के सुबूत के तौर पर, उनके उत्तराधिकारी, मितभाषी और सरल बोम्मई मुख्यमंत्री पद इस दौड़ में शुरुआत में कहीं नहीं थे. अपनी नियुक्ति के बाद बोम्मई ने दरियादिली दिखाते हुए मीडिया के सामने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में वे उनका मार्गदर्शन लेंगे.

बोम्मई ही क्यों?

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (ब्राह्मण) और हुबली-धाड़वाड़ पश्चिम के विधायक अरविंद बेलाड (लिंगायत) तक सीमित हो गई थी. अन्य लिंगायत उम्मीदवारों में राज्य के मंत्री मुरुगेश निरानी और उमेश कट्टी थे. बेंगलूरू में राजनैतिक इतिहासकार ए. वीरप्पा कहते हैं, ''येदियुरप्पा ने बोम्मई को सबसे आगे कर दिया. भाजपा के पास बात मानने के सिवाय चारा नहीं था. अगले विधानसभा चुनावों में उन्हें येदियुरप्पा के प्रतीक के तौर पर जरूरत है.''

(Established by MP State Legislature Act No. 26/2018, Recognized by UGC & Approved by AICTE, PCI, NCTE, INC, CCH & BCI New Delhi)

SARDAR PATEL UNIVERSITY

Balaghat • MP

BEST INNOVATIVE UNIVERSITY OF CENTRAL INDIA

ADMISSIONS OPEN 2021 – 22

ENGINEERING {AICTE Approved}

DIPLOMA / B.TECH

Part Time / Full Time

- Mechanical Engg.
- Civil Engg.
- Electrical Engg.
- Computer Science & Engg.
- Fire & Safety Engg.
- Mining Engg.
- Automobile Engg.
- Mining & Mine Surveying Engg.

M.TECH

- Industrial Mgmt. Engg.
- Structural Engg.
- Computer Science & Engg.
- Digital Communication Engg.
- Environmental Engg.

AGRICULTURE

- Diploma In Agriculture
- B.Sc (Hons.) Agriculture
- B.Tech. (Agril.) Engg.
- M.Sc. (Ag.) Agronomy / Horticulture

PHARMACY {PCI Approved}

- D. Pharmacy
- B. Pharmacy
- M. Pharmacy

Pharmacology
Pharmaceutics

LEGAL STUDIES {BCI Approved}

- BA. LLB
- LLB
- LLM

MANAGEMENT

- BBA (Hons.)
- BBA (Hotel Mgmt. & Tourism)
- MBA

Part Time / Full Time

EDUCATION {NCTE Approved}

- D.El.Ed.
- B.Ed.
- M.Ed.
- BA. B.Ed.
- B.Sc. B.Ed.
- B.Ed (Part Time)

COMMERCE

- B.Com.
- M.Com.

SCIENCE

- B.Sc. (All Sub.)
- M.Sc. (All Sub.)

COMPUTER APPLICATION

- DCA
- PGDCA
- BCA
- MCA
- B.Sc. (CS)
- M.Sc. (IT)

ARTS & SOCIAL SCIENCE

- BA (All Sub.)
- MA (All Sub.)
- BSW
- MSW

PARAMEDICAL

- D.MLT
- B.MLT
- B.PT
- DIPLOMA

MEDICAL

- BHMS
- BAMS*
- GNM
- B.Sc. Nursing

Ph.D in all Major Subject

NCC Cadets Training Center

NSS General Training & Sports Activities

100+	15+	21+	50+ MOUs	5000+	80+	Students From 15+
Acres of Lush Green Campus	Education Institutions	Years of Educational Excellence	National & International	Admissions	Courses are Available	States

SARDAR PATEL KNOWLEDGE CITY, WARASEONI ROAD, DONGARIYA, BALAGHAT (MP)

+91 9174192111, 9174202111, 9174212111, 9174422111

www.spubgt.ac.in

info@spubgt.ac.in

51 साल के बेलाड 2013 से भाजपा के विधायक हैं और पार्टी में उनको युवा आइकन के तौर पर देखा जाता है. फ्रांस के आइएनएसईएडी बिजनेस स्कूल के छात्र रहे बेलाड का विकास का अपना नजरिया है और उन्हें राज्य भाजपा के भविष्य के चेहरे के तौर पर आरएसएस का एक धड़ा तैयार कर रहा है. येदियुरप्पा ने संभवतया बेलाड को अपने सबसे छोटे बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष 45 वर्षीय बी.एस. विजयेंद्र के लिए खतरा मान लिया, जिन्हें वह राज्य में बड़ी राजनैतिक भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं. उनके बड़े बेटे, बी.एस. राघवेंद्र लोकसभा सांसद हैं.

येदियुरप्पा के कुर्सी छोड़ने के कई हफ्ते पहले से बेलाड ने दिल्ली के कई चक्कर लगाए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके फोन की टैपिंग की जा रही है. तुमकुरू स्थित राजनैतिक टिप्पणीकार बी.मंजूनाथ कहते हैं, ''अरविंद बेलाड इसलिए मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर नहीं हुए कि उनके अंदर कोई कौशल नहीं या पार्टी का समर्थन नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट कारक (येदियुरप्पा) हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बोम्मई की छत्रछाया में अगले दो साल में अब विजयेंद्र का राजनैतिक करियर कैसे आकार लेता है.''

बोम्मई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और वे जनता दल (यूनाइटेड) और फिर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल में लंबा वक्त बिताने के बाद 2008 में भाजपा में शामिल हुए. उनके पिता एस.आर. बोम्मई कर्नाटक में जनता पार्टी के शासन (1988-1999) के दौरान मुख्यमंत्री रहे थे. एस.आर. बोम्मई जनता दल के संस्थापक सदस्यों में थे. भाजपा में शामिल होने से पहले बासवराज बोम्मई दो बार कर्नाटक विधानपरिषद के लिए (1998 और 2004) में निर्वाचित हुए थे. 2008 में, वे हवेरी जिले के अपने गृहनगर शिगगांव से भाजपा के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव जीते थे. उसके बाद से वे उस सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं.

साफ छवि

बोम्मई की न तो जननेता की छवि है और न ही येदियुरप्पा की तरह मुखर वक्ता हैं. उन्हें लिंगायत समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बोलने वाले सक्रिय नेताओं में भी नहीं माना जाता है. फिर भी, कुछ चीजें उनके पक्ष में काम कर गईं. दो दशकों के सार्वजनिक जीवन में बोम्मई की छवि साफ रही है. पिछले दो साल से राज्य के गृह मंत्री के तौर पर और अतीत में जल संसाधन, कॉर्पोरेशन, कानून और संसदीय मामले जैसे कई मंत्रालयों का जिम्मा संभालने के बाद, उन्हें प्रशासन का अच्छा अनुभव है. भाजपा के कई लोगों का मानना है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद उनकी निष्ठा की वजह से सौगात में मिला है—बोम्मई भाजपा के साथ तब भी बने रहे जब येदियुरप्पा ने 2012 में भाजपा छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी, कर्नाटक जनता पक्ष (केजेपी) खड़ी कर ली थी.

कुछ लोगों के लिए, बोम्मई सुरक्षित दांव हैं क्योंकि किसी और को मुख्यमंत्री बनाने से गुटबाजी प्रभावित प्रदेश भाजपा में और असंतोष पैदा हो सकता था. प्रेक्षकों का कहना है कि भाजपा को येदियुरप्पा से सत्ता लेने के लिए लिंगायत नेता की तलाश करनी पड़ी ताकि यह महत्वपूर्ण वोट बैंक न खिसक जाए. 1990 में जब कांग्रेस ने एस. बंगारप्पा के लिए रास्ता बनाने के लिए लिंगायत मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हटा दिया, तो लिंगायतों ने भाजपा का दामन थाम लिया. इससे येदियुरप्पा को एक मौका मिल गया जो कर्नाटक में जमीनी स्तर पर भाजपा को स्थापित करना चाहते थे. मैसूर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और कर्नाटक की जातीय राजनीति के जानकार एन. प्रकाश कहते हैं, ''विधानसभा चुनाव को महज दो साल बचे हैं इसलिए भाजपा प्रयोग की स्थिति में नहीं थी. बोम्मई का मनोनयन उनके लिए बड़ा मौका है कि वे कोशिश करें और अगले असरदार लिंगायत नेता के रूप में उभरें.''

कर्नाटक में भाजपा ने कभी लगातार दो बार सत्ता हासिल नहीं की है और बोम्मई के पास इस ट्रेंड को बदलने का मौका है. लेकिन यह कुर्सी चुनौतियों से भरी है. उन्हें विरासत में ऐसा प्रशासन मिला है, जिसने कोविड 19 की दूसरी लहर का प्रबंधन ठीक से नहीं किया, साथ ही राज्य मॉनसूनी बाढ़ की चपेट में भी है. साल 2021-22 के लिए वित्तीय घाटा करीब 59,240 करोड़ रुपए आंका गया है क्योंकि महामारी के दौरान राजस्व काफी घट गया. मौजूदा वित्त वर्ष में राजस्व घाटा करीब 15,134 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है. राज्य के चार राज्य परिवहन निगमों के 1,10,000 कर्मचारियों का अप्रैल-जून का करीब 975 करोड़ रुपए का वेतन भी बकाया है. अब यह टुकड़ों में दिया जा रहा है. 69 सरकारी अस्पतालों के सीनियर डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों को भी 2020 में चार महीने का वेतन नहीं दिया जा सका था. उनके बकाया भुगतान भी इस साल जनवरी में हुए. बेंगलूरू में अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टरों की तनख्वाह भी अप्रैल में दी गई.

सरकार का राजस्व प्रवाह, उत्पाद शुल्क, टिकटों और पंजीकरण, सड़क कर और अन्य स्रोतों से, अभी तक पूर्व-कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पाया है. पूर्व जनता दल (सेकुलर)-कांग्रेस गठबंधन सरकार में सलाहकार और अर्थशास्त्री जी. हनुमंतैय्या कहते हैं, ''बोम्मई को ऐसा प्रशासन नहीं मिला है, जिसका खजाना भरा-पूरा हो. अगले दो साल में, उन्हें न सिर्फ राज्य की दशा-दिशा बदलनी होगी, साथ भाजपा को सत्ता में वापसी के लिए तैयार करना होगा. दोनों ही काम चुनौतीपूर्ण हैं.''

लेकिन मुख्यमंत्री आत्मविश्वास से लबरेज हैं. वे कहते हैं, ''मुझे इस नई जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी. महामारी के कारण राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. मैं सभी हितधारकों को विश्वास में लूंगा और एक जन-समर्थक प्रशासन चलाऊंगा.''

बोम्मई की सबसे बड़ी चुनौती येदियुरप्पा को खुश रखना होगा और उनके महत्वाकांक्षी बेटे विजयेंद्र से निबटना होगा. कथित तौर पर येदियुरप्पा ने यह भरोसा दिलाया है कि 2023 में वे भाजपा के लिए पूरे तरीके से चुनाव अभियान चलाएंगे, लेकिन इसके साथ कई अगर-मगर लगे होंगे, मसलन विजयेंद्र का प्रमोशन और कांग्रेस तथा जद (एस) के 15 विधायकों के हितों की रक्षा करना भी, जो दल-बदल करके भाजपा में आ गए और 2019 में सरकार गठित करने में मदद की.

2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए विजयेंद्र ने तगड़ी लामबंदी की, लेकिन टिकट नहीं मिला था. हर बार कर्नाटक उपचुनावों में उनका नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में आता है. लगता है कि वे 2023 का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं. मंजूनाथ कहते हैं, ''बोम्मई को कुशलता से येदियुरप्पा और उनके परिवार के साथ पेश आना होगा और यह काम आसान नहीं रहेगा.''■

ये हैं नए सीएम

- बासवराज एस. बोम्मई पहले समाजवादी थे और 2008 में भाजपा में आने से पहले उन्होंने जनता दल में 10 साल गुजारे
- कर्नाटक के पूर्व सीएम एस.आर. बोम्मई के बेटे हैं और राज्य के दूसरे पिता-पुत्र सीएम हैं, इनसे पहले राज्य में एच.डी. देवेगौड़ा और उनके पुत्र एच.डी. कुमारस्वामी सीएम रह चुके हैं
- पूर्व मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल (जनता दल) के राजनैतिक सचिव रह चुके हैं
- पहला चुनाव 2008 में भाजपा के टिकट पर हवेरी जिले में गृहनगर शिगगांव से जीते और तब से जीतते चले आ रहे हैं
- मैकेनिकल इंजीनियर हैं, राजनीति से पहले ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करते थे

www.cvru.ac.in

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Approved by : AICTE | NCTE | BCI | AIU | Joint Committee : (UGC | DEB | AICTE) | Recognized by : UGC | A NAAC Accredited University

1st NAAC Accredited Private University in CG

BE THE CHANGE

CHANGE, GROW, TRANSFORM.

Striving to change your future.

Unlimited access to eLearning materials with **Learning Management System (LMS)**

- 10,000+ students registered
- 500+ faculties conducting online classes
- 4,500+ classes conducted

*AGU unified LMS

Prominent features

- **Over 75 labs and workshops**
- **Offers short-term** courses through **CVRU NSDC Academy**
- **Nine advanced research centres of excellence**
- **15 International** & **30 National** Level collaborations
- Over **800 research papers** and **50 books** written by faculty and scholars

PROGRAMMES OFFERED

Engineering & Technology | Education | Management
Information Technology | Law | Commerce
Journalism & Mass Comm. | Pharmacy | Arts | Science
Physical Education | Research Programmes (Ph.D. & M.Phil.)

Integrated future-ready courses in association with

AISECT FUTURE SKILLS ACADEMY | coursera Access to World Class Online Learning Programmes | Red Hat

Honoured for Hardwork

- Rated AAA among State Private Universities by CAREERS360
- Ranked 2nd among the Best Private Law University Central India by THE WEEK
- Listed among the Top Universities in India by competition success review
- Ranked 8th among the Multi-Disciplinary Private University in the zone by THE WEEK
- Ranked among India's Top 30 Private Universities of India by INDIA TODAY
- Ranked among State Private Universities by OUTLOOK

Exclusive Campus Radio Channel

90.4 RADIO RAMAN — AN INITIATIVE BY DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Bihan Bihar Scholarships

Industry Partners & Learning Partners

Acxiom Consulting | AIS Asahi India Glass Ltd. | Biome Technologies | BYJU'S | Collabera | IFFCO KISAN | ISC Software | hitech | CIS | DAAWAT | EduSkills | genpact | jaro education | Jayaswal Neco Industries Limited | and many more...

ADMISSIONS OPEN

+91-7753-253801,
6261-900581/82

Apply Now

For enquiries & other information, contact us at:

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) | Fax: +91-7753-253728
Email: info@cvru.ac.in | admissions@cvru.ac.in

Scan to visit
www.cvru.ac.in

उत्तराखंड

देवता पर दावा!

अखिलेश पांडे

राकेश रमण शुक्ल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में संशोधन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का आश्वासन दिया है. इसके बाद बोर्ड को लेकर मचा घमासान फिलहाल कुछ हद तक शांत हो गया है. लेकिन आंदोलन की चिंगारी अंदर-ही-अंदर सुलग रही है. चार धाम तीर्थ पुरोहित हक-हकूकधारी महापंचायत ने इस आश्वासन पर शीघ्र कदम उठाने की मांग की है. बोर्ड के खिलाफ आंदोलित पुरोहितों ने सत्तासीन भाजपा के नेताओं पर अपना गुस्सा जताना शुरू कर दिया था, जिससे सरकार थोड़ी झुकती दिखी.

दरअसल, 5 जून को राज्य के सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व, दिलीप जावलकर ने इस बोर्ड में कुछ सदस्यों को नामित करने की अधिसूचना जारी की, जिसने इस मामले में आग में घी डालने का काम कर दिया था. इस अधिसूचना से बोर्ड में आठ सदस्य नामित किए गए हैं. इनमें तीन उद्योगपति और पांच तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों के वंशजों को शामिल किया गया है. इसमें हिंदू धार्मिक मामलों में विशेष रुचि रखने वाले भूत, वर्तमान और भविष्य के दानदाता की श्रेणी में उद्योगपति अनंत अंबानी की नियुक्ति की गई है. इनके अलावा सज्जन जिंदल और महेंद्र शर्मा को भी बोर्ड में सदस्य बनाया गया है. बोर्ड में पुजारियों और हक हकूक धारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जिन पांच तीर्थ पुरोहितों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है, उनमें श्रीनिवास पोस्ती, जयप्रकाश उनियाल, कृपाराम सेमवाल, गोविंद सिंह पंवार और आशुतोष डिमरी शामिल हैं.

विवाद इस बिंदु को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या बोर्ड में सदस्य बनाने की शर्त हिंदू धार्मिक मामलो में विशेष रुचि रखने के साथ ही दानदाता होना भी है? इस पर सवाल उठाते हुए तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता डॉ. बृजेश सती कहते हैं, ''अगर दानदाताओं को नामित करना है तो चारधाम के लिए काली कमली वाले से बड़ा दानदाता कौन है? काली कमली ने तो तब यहां दान के लिए थैलियां खोल दी थीं जब चारधाम का दुनिया को पता ही नहीं था.'' भविष्य के दानदाता के रूप में बोर्ड का सदस्य नामित होना पंडा बिरादरी के बीच चर्चा और संदेह का कारण बना है. बोर्ड में सर्वाधिक संख्या नौकरशाहों की रखी गई है. व्यवस्था है कि बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल भारतीय सेवा का उच्चतम वेतनमान के ग्रेड वेतन वाला अफसर ही होगा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के अंदर असीमित अधिकार प्राप्त पदाधिकारी होगा. बोर्ड में उच्च अधिकार प्राप्त समिति अलग से होगी जो कि ऐक्ट की धारा 11(2) के अनुसार समय-समय पर बोर्ड की ओर से प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी.

तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा इस कारण और भड़क गया था कि जिस बोर्ड के खिलाफ लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर चारों धामों में भी लड़ी जा रही है, उसमें सदस्य नामित करने की हड़बड़ी सरकार क्यों दिखा रही है. वह भी तब जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पुरोहितों को इस बोर्ड के गठन को लेकर पुनर्विचार करने का भी आश्वासन दे चुके थे. तीर्थ पुरोहितों इसलिए भी भड़क गए हैं कि राज्य के पर्यटन तीर्थाटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बोर्ड पर किसी तरह के पुनर्विचार को खारिज कर दिया. नाराज पुरोहितों ने उनका पुतला जलाकर मंत्रिमंडल से उनकी बर्खास्तगी तक की मांग कर डाली. फिर मंत्री ने यह कहकर इस विवाद से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया.

तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का मकसद सीधे तौर पर मंदिर की पारंपरिक और आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप करना है. इस बोर्ड के जरिए सरकार चार धाम समेत बाकी के मंदिरों में अपने चहेते लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाने की फिराक में है, ताकि पुरानी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं. तीर्थ पुरोहित सरकार की उस मंशा पर भी सवाल उठाते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बोर्ड का गठन प्रदेश के चारों प्रसिद्ध धामों को सुनियोजित विकास और देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा तथा सुरक्षा मुहैया करवाने के मकसद से हुआ है.

पंच पंडा सिमिति, रुद्रपुर के अध्यक्ष अनित शुक्ल कहते हैं कि अगर सरकार का वास्तव में मकसद धामों में बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा को लेकर है, तब उन्हें यह काम हरिद्वार की मंशा देवी और अन्य बड़े मंदिरों से करना चाहिए, जहां यात्रा साल भर चलती रहती है. उन्होंने कहा कि असल में सरकार ने उन्हीं मंदिरों को बोर्ड के अधीन शामिल किया

नाराजगी
मुख्यमंत्री धामी के आश्वासन के बाद देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फिलहाल शांत हुआ

है, जिनमें पारंपरिक तौर पर हक-हकूकधारी सदियों से जुड़े हुए हैं. तीर्थ पुरोहित राज्य के अन्य बड़े मंदिरों जैसे कोटद्वार का सिद्धबली मंदिर, सुरकंडा देवी और नीलकंठ महादेव आदि को इस बोर्ड से अलग रखे जाने पर भी सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि सरकार मंदिरों के प्रबंधन में अफसरशाही को हावी बनाकर अपने चहेते लोगों को बोर्ड में शामिल कर हक-हकूकधारियों के अधिकार छीनने का खेल शुरू कर रही है. इस खेल से मंदिरों की संपत्ति के भी खतरे में आने की आशंकाएं बढ़ गई हैं. बद्री-केदार मंदिरों की संपत्तियां-धर्मशालाएं देश के विभिन्न स्थानों पर हैं.

दिसंबर 2019 में देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में पारित किया था और जनवरी 2020 में इसके जरिए देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया. बोर्ड का गठन होने से पहले ही इसे लेकर तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था.

डॉ. बृजेश सती के अनुसार, देवस्थानम अधिनियम के एक क्लॉज में यह व्यवस्था दी गई है कि चार धाम की संपत्ति का विनिमय, विक्रय, गिरवी रखने या पट्टे पर देने की कार्यवाही अब बिना बोर्ड की अनुमति के नहीं होगी. राज्य में विपक्षी पार्टियां जिनमें वामपंथी संगठन शामिल हैं, इस अधिनियम के खिलाफ अधिक मुखर हैं. उनके अनुसार, असल में ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि इन संपत्तियों को बोर्ड जिसे चाहे उसे दे देगा, और यह अब कानूनी तरीके से किया जाएगा.

बोर्ड के खिलाफ आंदोलन से जुड़े गद्दी पुरोहित पंकज शुक्ल कहते हैं कि सरकार कहती रही कि पुरोहितों और हक-हकूकधारियों के हित प्रभावित नहीं होंगे, पर बोर्ड ने विभिन्न पूजा के बाकायदा रेट तय कर उसे वेबसाइट पर डालकर इसे कमर्शियल बना डाला है तो पुरोहितों के हक अब बचे कहां.

गंगोत्री मंदिर के रावल शिवप्रकाश महाराज का कहना है कि बोर्ड गठन के पीछे सरकार की मंशा सीधे उन लोगों के हाथ में मंदिरों का नियत्रंण दे देना है, जो इस मुल्क में पहले ही संपत्ति के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर चुके हैं. वहीं, राज्य में भाकपा माले के नेता इंद्रेश मैखुरी इस बोर्ड के गठन को ही असंवैधानिक करार दे रहे हैं. उनके अनुसार, संविधान में यह उल्लेखित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. यहां नागरिकों का तो धर्म है, अनुच्छेद 25 में नागरिकों को पूजा का अधिकार भी दिया गया है, पर राज्य धर्मनिरपेक्ष है. लेकिन जो बोर्ड विधेयक सरकार ने पारित किया, उसमें श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री तो होगा लेकिन शर्त यह है कि तभी होगा जब वह हिंदू हो. अगर वह हिंदू नहीं होगा तो वह हिंदू धर्म को मानने वाले वरिष्ठ मंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष नामित करने को बाध्य होगा. बोर्ड में नामित होने वाले तीन सांसदों और छह विधायकों के लिए भी हिंदू धर्म का अनुसरण अनिवार्य शर्त रखी गयी है. मैखुरी कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 15 तो कहता है कि किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जो कानून पास किया, उसमें मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों के साथ ही धार्मिक आधार पर भेदभाव की व्यवस्था कर दी गई है.

मुख्यमंत्री के अलावा बोर्ड में धर्म-संस्कृति के मंत्री होंगे, मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव, धर्म, संस्कृति के सचिव, वित्त सचिव के अलावा भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव या उससे उच्च पद के व्यक्ति, विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. ये शासकीय सदस्यों की श्रेणी में हैं. वहीं, नामांकित सदस्यों में सबसे पहले टिहरी रियासत के राजपरिवार के सदस्य रखे गए हैं.

जाहिर है, धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फिलहाल शांत है. लेकिन अगर इस आश्वासन को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो उनकी नाराजगी आगामी चुनावों में भाजपा पर भारी पड़ सकती है. ■

चार धाम देवस्थानम बोर्ड में मनोनीत आठ सदस्य

- **अनंत अंबानी:** उद्योगपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे 25 वर्षीय अनंत अंबानी को बोर्ड में भविष्य के दानदाता श्रेणी में मनोनीत किया गया है. राज्य में महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए अनंत और रिलायंस फाउंडेशन ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं. अंबानी परिवार बद्रीनाथ और केदारनाथ में दान देता रहा है
- **सज्जन जिंदल:** स्टील उत्पादक जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल बोर्ड में दानदाता सदस्य के रूप में नामित हुए हैं. केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि निर्माण का खर्च उठा रहे हैं
- **महेंद्र शर्मा:** हिमाचल के उद्योगपति महेंद्र शर्मा को भी बोर्ड में मनोनीत किया गया है. इन्होंने केदारनाथ के गर्भ गृह में चांदी का आवरण चढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए

पुजारियों और हक-हकूकधारियों के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत पांच सदस्य

- **श्रीनिवास पोशती:** केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित व केदारनाथपालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं
- **कृपाराम सेमवाल:** सेमवाल गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित हैं
- **जयप्रकाश उनियाल:** वे यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित हैं
- **गोविंद सिंह पंवार:** पांडुकेश्वर निवासी बदरीनाथ धाम के हक-हकूकधारी हैं
- **आशुतोष डिमरी:** देहरादून में पत्रकार हैं और बद्रीनाथ डिमरी पंचायत के अध्यक्ष भी हैं

झारखंड

सरकार गिराने का खेल ऐसे हुआ फेल

अमिताभ श्रीवास्तव

साजिश के हरकारे >
रांची में 24 जुलाई को आरोपियों को गिरफ्तार करती पुलिस; मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

झारखंड में 24 जुलाई को रांची पुलिस ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गिराने की कथित साजिश का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों—अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को शहर से गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी साजिश के तहत तीन विधायकों के साथ 15 जुलाई को नई दिल्ली गए थे. इनमें दो कांग्रेस के विधायक थे.

पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों के पास से विधायकों के राष्ट्रीय राजधानी के दौरे से संबंधित दस्तावेजों के अलावा दो लाख रुपए नकद मिले हैं. दुबे, अमित सिंह और महतो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जनप्रतिनिधित्व कानून और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार, इन तीनों ने खुलासा किया है कि भाजपा के महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर दिल्ली में झारखंड के तीन विधायकों से मुलाकात की थी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक की व्यवस्था की थी. दुबे ने यह भी दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की गठबंधन सरकार को गिराने के लिए विधायकों को एक-एक करोड़ रुपए अग्रिम की पेशकश की गई थी. हालांकि, उसने बताया कि विधायक 16 जुलाई को उन्हें वादा किए गए अग्रिम राशि के बिना रांची लौट आए.

पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पता चला है कि महाराष्ट्र से पांच लोग 21 जुलाई को रांची पहुंचे और ली लैक होटल के चार कमरों में ठहरे. उनके साथ दिल्ली का दौरा करने वाले एक विधायक भी शामिल हुए. दुबे को भी होटल में बुलाया गया था. उसी दिन, हजारीबाग के एक विधायक ने कथित तौर पर अमित सिंह को सूचित किया कि सरकार को गिराने की योजना में आठ विधायक शामिल थे. जाहिर तौर पर, चार और विधायकों को लुभाने की योजना थी.

सत्तारूढ़ गठबंधन को 82 सदस्यीय झारखंड विधानसभा (एक मनोनीत सदस्य सहित) में 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. इनमें से 30 झामुमो के हैं. झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के दो विधायकों, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के फरवरी 2020 में पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास 18 विधायकों की प्रभावी ताकत है. दलबदल को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मंजूरी मिलना अभी बाकी है. वहीं, राजद के पास एक विधायक है.

दिसंबर, 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने वाली भाजपा के पास 26 विधायकों की प्रभावी ताकत है (झाविमो के संस्थापक बाबूलाल मरांडी पिछले साल फरवरी में फिर से भाजपा में शामिल हो गए). वहीं, भाजपा की पूर्व सहयोगी आजसू (ऑल झारखंड स्टुडेंट्स यूनियन) पार्टी के पास दो विधायक हैं.

हेमंत सोरेन, जो झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मुखर आलोचक हैं. उन्होंने विवादास्पद कृषि कानूनों और हाल ही में पेगासस जासूसी विवाद जैसे विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के अलावा, कोविड-19 महामारी से निपटने में केंद्र के रवैये पर बार-बार सवाल उठाए हैं.

नवंबर 2000 में गठित झारखंड में राजनैतिक दलबदल और सरकारों के बार-बार परिवर्तन का इतिहास रहा है. साल 2014 तक राज्य में नौ सरकारें और राष्ट्रपति शासन के तीन दौर देखे गए थे. भाजपा के रघुबर दास, जिन्होंने दिसंबर 2014 में पदभार ग्रहण किया, पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. लेकिन उनके कार्यकाल में भी झाविमो के छह विधायक दलबदल कर भाजपा में शामिल हो गए (फरवरी 2015 में). भाजपा से सत्ता छीनने वाले हेमंत सोरेन को विधानसभा में आसानी से बहुमत प्राप्त है. लेकिन अगर मुट्ठी भर विधायकों ने भी गठबंधन छोड़ दिया या अपना पाला बदल लिया, तो सोरेन की बहुमत अल्पमत में बदल सकता है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोरेन सरकार को अस्थिर करने के इरादे से रांची

सोमनाथ सेन

में डेरा डाले प्रभावशाली राजनैतिक लोगों और वित्तपोषकों के खिलाफ 22 जुलाई को बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद इस साजिश का पर्दाफाश हो गया था. अनूप सिंह ने शिकायत में दावा किया कि इसके लिए पैसे का लेनदेन हवाला के जरिए किया जा रहा था.

आंकड़ों का हिसाब

झारखंड विधानसभा **कुल सीटें 82**
बहुमत का आंकड़ा **41**

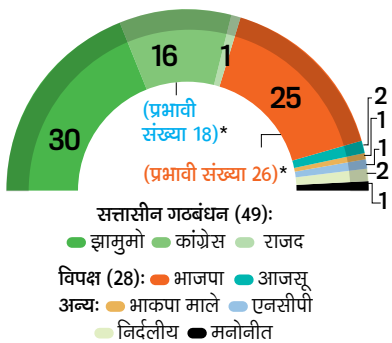

* झाविमो के दो विधायक कांग्रेस में चले गए, जबकि झाविमो संस्थापक बाबूलाल मरांडी फरवरी, 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे. इनकी मंजूरी विधानसभा स्पीकर के पास लंबित है

ग्राफिकः असित रॉय

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और ली लैक होटल में छापेमारी करके दुबे को पकड़ा गया. पुलिस ने एक बयान में कहा है कि होटल में ठहरे कुछ अन्य संदिग्ध छापेमारी से कुछ मिनट पहले भाग गए थे. पुलिस ने उनका सामान जब्त कर लिया है और ठहरने के समय जमा किए गए उनके पहचान पत्रों की फोटोकॉपी भी ले ली है. महतो और अमित सिंह को रांची के अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस का कहना है कि दुबे रांची का रहने वाला है और एक छोटी-सी दुकान चलाता है. अमित सिंह बोकारो का रहने वाला है और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में संविदा कर्मचारी है. वहीं, महतो का फलों का कारोबार है. महतो ने बोकारो से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उसकी बहुत बुरी हार मिली थी.

झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. झामुमो के प्रमुख महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की घटनाओं ने दिखा दिया है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता पर कब्जा करने के लिए किस तरह की चालबाजी की.

इन गिरफ्तारियों के एक दिन बाद, कांग्रेस के कोलेबिरा विधायक, नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने दावा किया था कि उनसे लगभग आधा दर्जन बार तीन लोगों ने संपर्क किया था और सोरेन सरकार को हटाने में मदद करने के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक देने की पेशकश की थी. कोंगाड़ी ने कहा कि उन्होंने सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ सभी विवरण साझा किए हैं.

वहीं, भाजपा की राज्य इकाई ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर पलटवार किया है. मरांडी ने सोरेन पर झूठे इलजाम में तीन लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की.

मार्च में, चुनावी सुधारों की वकालत करने वाले समूह, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2016 और 2020 के बीच 405 दलबदलू विधायकों में से 182 (लगभग 45 फीसद) भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेस (38) का स्थान था. रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में इस अवधि के दौरान दलबदल के कारण सरकारें गिर गईं.

झारखंड में विपक्षी खेमा भले सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, पर पुलिस ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि दुबे, अमित सिंह और महतो ने सरकार को गिराने के लिए राजनेताओं से संपर्क करने तथा उन्हें पैसे पेशकश करने की बात स्वीकार की है. पुलिस अपने मामले का समर्थन करने के लिए छापेमारी के दौरान जब्त 'सबूत' की जांच कर रही है. अगर वाकई कोई साजिश थी तो सोरेन सरकार बाल-बाल बच गई है. वैसे, इसने सत्तारूढ़ गठबंधन को अपने विधायकों के साथ फिर से जुड़ने और अपने खेमे को व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया है. इस विवाद से कुछ समय तक राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो जाएगी. ■

छत्तीसगढ़

दरकने लगा गढ़!

राहुल नरोन्हा

पंजाब में कांग्रेस की कलह, बेशक फौरी तौर पर ही सही पर थमती नजर आनी शुरू ही हुई थी कि उस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गंभीर अंदरूनी मतभेद उभकर सामने आने लगे जहां पार्टी की शायद सबसे सुरक्षित सरकार है.

उत्तरी छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि 24 जुलाई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उन पर हमला कराया था. विधायक ने कहा कि मंत्री से उनकी जान को खतरा है. विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था और इन आरोपों ने तूफान खड़ा कर दिया. गुस्साए सिंहदेव यह कहते हुए सदन से बाहर चले गए कि वे तभी लौटेंगे जब उनका सम्मान बहाल हो जाएगा.

इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच की आपसी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है. भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच तनावपूर्ण रिश्ते छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसी से छुपे नहीं हैं. इस तनाव के मूल में 2018 में मुख्यमंत्री के चयन के समय तय किया गया 'सत्ता की साझेदारी का फॉर्मूला' है. उस फॉर्मूले के अनुसार, मुख्यमंत्री का पद बघेल और सिंहदेव के बीच बारी-बारी से ढाई-ढाई साल के लिए जाना था. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सत्ता बंटवारे के उस फॉर्मूले की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है. इसलिए इस स्थिति पर उसका कोई स्पष्ट रुख नहीं दिख रहा है. सत्ता परिवर्तन की समय सीमा जून के मध्य में समाप्त हो चुकी है. उस दौरान राज्य की राजनैतिक गतिविधियों में बहुत तेजी आ गई थी और सिंहदेव के समर्थन में कांग्रेस विधायकों के दिल्ली के चक्कर लगाने की अफवाहें भी गर्म थीं.

तो यह ताजा संकट कैसे शुरू हुआ? बृहस्पति सिंह का चुनाव क्षेत्र सिंहदेव के चुनाव क्षेत्र अंबिकापुर से बहुत दूर नहीं है. 24 जुलाई को बृहस्पति अंबिकापुर थाने पहुंचे और कहा कि उनके साथ चलने वाली सुरक्षा गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया. उनका कहना था कि जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसके ड्राइवर के साथ ओवरटेक को लेकर 'हमलावरों' का विवाद हो गया था और वे सिंहदेव के दूर के रिश्तेदार निकले. विधायक ने तब आरोप लगाया कि सिंहदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए उनकी हत्या तक करा सकते हैं. संयोग से, जब गाड़ी के चालक पर हमला हुआ था तब बृहस्पति मौके पर मौजूद नहीं थे. अगले दिन 25 जुलाई

बीती बात
भूपेश बघेल (खड़े हुए) और टी.एस. सिंहदेव

भूपेश केशरवानी

को बृहस्पति बिलासपुर गए, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आरोप दोहराए. उसी शाम वे रायपुर पहुंचे और वहां भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें कांग्रेस के करीब 20 विधायक मौजूद थे. कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की एक बैठक भी हुई, लेकिन उसमें इस मामले पर चर्चा नहीं हुई. सीएलपी बैठक के बाद सिंहदेव से जब आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''विधायक ने भावावेश में आरोप लगा दिए होंगे. हर कोई मेरी छवि से परिचित है. क्या मैं वह कर सकता हूं जैसे आरोप विधायक लगा रहे हैं.''

हालांकि 26 जुलाई को विपक्षी भाजपा की ओर से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, सिंहदेव ने पार्टी मंच पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. यह फैसला किया गया कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अगले दिन विधायक का बचाव करते हुए सदन में बयान देंगे. मंत्री ने इस मुद्दे पर बयान तो दिया लेकिन सिंहदेव के बारे में कुछ नहीं कहा.

इससे नाराज सिंहदेव विधानसभा से निकल गए और अपने आवास चले गए. बड़ी संख्या में उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके आवास पहुंचे. रायपुर में मौजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पी.एल. पुनिया को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया और उन्होंने सिंहदेव से बात की. शाम को मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें सिंहदेव शामिल हुए. उसी रात विधायक बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया कि आखिर किस आधार पर उन्होंने सिंहदेव पर आरोप लगाए हैं. विधायक को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया था.

इस प्रकरण का बुधवार को तब पटाक्षेप हुआ जब बृहस्पति सिंह ने सदन में बयान दिया कि उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया गया है. उसके बाद गृह मंत्री ने औपचारिक रूप से सदन में कहा कि इस घटना में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की कोई भूमिका नहीं थी. दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री बघेल ने मामले को खत्म करने के लिए बृहस्पति सिंह को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा भी की.

इसकी पृष्ठभूमि में एक और कहानी आकार ले रही थी जिसमें बघेल घिर रहे थे और इसने दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ा दिया था. ऐसी जानकारियां आई थीं कि छत्तीसगढ़ सरकार दुर्ग के एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने जा रही है. मेडिकल कॉलेज का संचालन बघेल की बेटी के ससुराल पक्ष के लोग करते हैं. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए सरकार की ओर से कॉलेज के अधिग्रहण का विधेयक उन्हें पेश करना था और इस बात की आशंका थी कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इस पर आपत्ति थी. 28 जुलाई को पारित होने से पहले कृषि मंत्री रवींद्र चौबे को विधेयक को पेश करने के लिए स्टैंड बाइ में रखा गया था. सदन में गृह मंत्री के बयान के बाद सिंहदेव थोड़े नरम पड़े, हालांकि उनकी यह नरमी अस्थायी मानी जा रही है. उन्होंने वह विधेयक पेश किया. अधिग्रहण के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़े नौकरशाहों का मानना था कि कॉलेज का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मान्यता प्राप्त नहीं था और इसके ऊपर बड़ी मात्रा में असुरक्षित ऋण था. यह अधिग्रहण कॉलेज की ओर से सरकार को दी गई एक याचिका पर आधारित था.

कलह की कहानी

ताजा मामला
कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से खुद को जान का खतरा बताया और हमला करवाने का आरोप लगाया

नाराजगी
जारी मॉनसून सत्र में यह मामला गूंजा. नाराज सिंहदेव सदन से बाहर चले गए और कहा कि जब तक उनका सम्मान बहाल नहीं होता वे वापस नहीं आएंगे

खींचतान
इस पूरे विवाद को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है

साझेदारी का फॉर्मूला
बघेल और सिंहदेव के बीच तनाव की जड़ सत्ता में साझेदारी के कथित फॉर्मूले को माना जा रहा. इसके अनुसार, दोनों को बारी-बारी से ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनना था

गायब आलाकमान
कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने न तो इस फॉर्मूले से इनकार किया है, न ही पुष्टि की है. वहीं तनाव दूर करने के लिए भी वह सक्रिय नहीं दिख रही

बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, बघेल की टीम राजनैतिक और प्रशासनिक कदमों के जरिए सिंहदेव को हाशिए पर लाने में जुट गई. पिछले ढाई वर्षों में सियासी मोर्चे पर सिंहदेव के आधार को खत्म करने के कई प्रयास हुए. 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के 19 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सिंहदेव की थी. कांग्रेस ने सभी 19 सीटों पर जीत दर्ज की और विधायकों को सिंहदेव का वफादार माना जाता था. सिंहदेव के वफादारों में बृहस्पति शामिल थे, अब वे बघेल के वफादार बन गए हैं. उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक अन्य विधायक अमरजीत भगत को मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया. सियासी पंडितों का कहना है कि ऐसा उत्तरी छत्तीसगढ़ में सत्ता का एक और केंद्र बनाने के लिए किया गया है. कहा जाता है कि प्रशासनिक रूप से सिंहदेव को कमजोर करने के लिए बघेल उन्हें अपनी टीम में मनपसंद अधिकारियों को रखने से वंचित करते रहे हैं.

इस बीच भाजपा को कांग्रेस पर हमले करने का मौका मिल गया. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, ''जो कुछ भी हुआ वह कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा है. भाजपा ने मामले की जांच की मांग की, क्योंकि इस नाटक में पर्दे के पीछे भी कई कलाकार काम कर रहे हैं.'' संघर्ष विराम के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को मामूली गलतफहमी बता दी. राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, ''कुछ गलतफहमी थी जिसे दूर कर लिया गया है. विधायक बृहस्पति सिंह और मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा दिल दिखाया है और स्पष्ट किया है कि अब सब ठीक है.''

बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने उपचुनावों में विपक्ष से दो और सीटें—दंतेवाड़ा और मरवाही छीन लीं और 90 सदस्यों के सदन में उसके अब कुल 70 विधायक हो गए हैं. कांग्रेस ने शुरुआत में 90 में से 68 सीटें जीती थीं. ऐसे में शायद यह देश में कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सरकार है. पार्टी पहले ही अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप फैसले लेने में असमर्थता के कारण सरकारें गंवा चुकी है, बावजूद इसके वह छत्तीसगढ़ के इस कलह को नजरअंदाज कर रही है. सियासी विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं, ''छत्तीसगढ़ में जो हुआ वह अंतिम नहीं है, ऐसा आगे भी होता रहेगा. इसका कारण सरल है: जब दो गुट वर्चस्व के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, कांग्रेस आलाकमान बेपरवाह बना रहता है.'' ■

विरासत की जंग
पन्ना में राज मंदिर पैलेस

एएनआइ

पन्ना

राजसी कलह

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश के पन्ना के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच एक विवाद ने 22 जुलाई को तब बदसूरत मोड़ ले लिया, जब स्थानीय पुलिस ने महारानी जीतेश्वरी देवी को उनकी सास दिलहर कुमारी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया. दिलहर कुमारी ने अपनी बहू के खिलाफ 19 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी और पन्ना पुलिस ने जीतेश्वरी, उनके पति महाराजा राघवेंद्र, उनके बच्चों और एक अन्य आरोपी सलीम खान पर बलपूर्वक अनाधिकार प्रवेश और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

शाही परिवार के बीच चले आ रहे पुराने विवाद के इस नवीनतम प्रकरण में, दिलहर कुमारी ने पुलिस के सामने जो शिकायत दी है उसके अनुसार, जीतेश्वरी देवी, राघवेंद्र सिंह, उनके बच्चों और सलीम खान ने राज मंदिर पैलेस के एक हिस्से पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की. 19वीं शताब्दी में निर्मित राज मंदिर पैलेस पूर्व पन्ना राजघराने का निवास है. यह सब तब हुआ जब दिलहर कुमारी और उनकी बेटी कृष्णा कुमारी मुंबई में थीं. महल के उस हिस्से की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने जीतेश्वरी देवी को रोका. कथित तौर पर जीतश्वरी ने गार्डों पर एक देसी पिस्तौल तान दी थी. एक गार्ड आखिरकार उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रहा और इस झगड़े में राघवेंद्र घायल हो गए. उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. अगली सुबह दिलहर कुमारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और गार्ड ने देसी पिस्तौल भी पुलिस को सौंप दी.

इस पूर्व शाही परिवार के विभिन्न सदस्य पिछले कुछ वर्षों से आपस में झगड़ रहे हैं. इस विवाद की जड़ में राजघराने की करोड़ों रुपए की संपत्ति है. स्वतंत्रता पूर्व भारत में 11 तोपों की सलामी की हकदार रियासत पन्ना में देश की एकमात्र हीरे की खदानें हैं. बाद में, यह क्षेत्र अपने टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाने लगा, जिसे 1980 के दशक की शुरुआत में स्थापित किया गया था. यह रिजर्व अपने सभी बाघों के खत्म हो जाने के कारण भी खबरों में रहा था. लेकिन, इसमें फिर से बाघ लाए गए और उनकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि एक बार फिर खबरों में रही.

पूर्व राजपरिवार बुंदेला राजपूतों का वंशज है. वे राजा छत्रसाल के वंशज हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी में पन्ना रियासत की स्थापना की थी. पेशवा बाजीराव प्रथम की पत्नी मस्तानी—जिन पर बाद में बॉलीवुड फिल्म बनी—को उनकी बेटी बताया जाता है.

पन्ना की विरासत और संपत्ति के तीन प्रमुख दावेदार हैं. राघवेंद्र और उनकी पत्नी जीतेश्वरी पहली दावेदार हैं; दूसरे नंबर पर दिलहर कुमारी और कृष्णा कुमारी हैं; और राघवेंद्र के चाचा और पूर्व सांसद दिवंगत लोकेंद्र सिंह की पत्नी इंदिरा कुमारी और उनकी बेटी कामाक्षा तीसरी दावेदार हैं. सूत्रों का कहना है कि राघवेंद्र और जीतेश्वरी पिछली पीढ़ी में संपत्ति के विभाजन के बाद लोकेंद्र सिंह के परिवार के हिस्से आई संपत्ति पर भी दावा करते हैं.

पन्ना जिले में फैली संपत्तियों को लेकर इन विभिन्न गुटों के बीच मुकदमेबाजी चल रही है. पन्ना शहर में विशाल राज मंदिर पैलेस, गुन्नौर तहसील के बलगाहा फार्म, लक्ष्मीपुर फार्म, पुरुषोत्तमपुर और बहारगंज में जमीनें और पन्ना शहर तथा बग्गीखाना के भूखंड पर अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है. हालांकि पूर्व राजपरिवार में से कोई भी इसकी पुष्टि नहीं करता है लेकिन भूमि कई सौ एकड़ में फैली हुई है और कीमत सैकड़ों करोड़ रूपए में होगी.

इतना ही नहीं, कहा जाता है कि राजघराने की संपत्तियां पन्ना के अलावा दिल्ली और मुंबई में भी हैं. पन्ना शहर के मंदिर परंपरागत रूप से शासक या पूर्व शासक की देखरेख में हैं. अचल संपत्ति के अलावा, इस परिवार

पन्ना परिवार के सदस्य

नरेंद्र सिंह जूदेव
पन्ना के आखिरी शासक

मानवेंद्र सिंह जूदेव
दिवंगत महाराज

दिलहर कुमारी
मानवेंद्र सिंह की पत्नी और शिकायतकर्ता

लोकेंद्र सिंह
मानवेंद्र के दिवंगत छोटे भाई

राघवेंद्र सिंह
महाराजा और जीतेश्वरी देवी के पति

कृष्णा कुमारी
मानवेंद्र सिंह और दिलहर कुमारी के बेटी

कामक्षा कुमारी
लोकेंद्र सिंह और इंदिरा कुमारी की बेटी

के पास उत्कृष्ट प्राचीन वस्तुएं और दुनिया की कुछ सबसे मूल्यवान बंदूकें और राइफल हैं. चूंकि पन्ना में हीरे की खान है, इसलिए स्थानीय मीडिया में इस परिवार के पास हीरे के ढेरों आभूषण होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं.

साल 2015 में जीतेश्वरी ने अपने ससुर दिवंगत मानवेंद्र सिंह की वसीयत पेश की थी. वसीयत के अनुसार, संपत्ति का उत्तराधिकारी उनकी पोती या जीतेश्वरी और राघवेंद्र की बेटी को बनाया गया था. वहीं, दिलहर कुमारी ने वसीयत को जाली दस्तावेज बताकर खारिज कर दिया था.

महल की घटनाओं पर नजर रखने वालों का एक वर्ग मानता है कि परिवार के बीच कलह का कारण केवल संपत्ति नहीं है बल्कि दूसरी कई वजहें भी हैं. उनका कहना है कि जहां पूर्व राजघरानों के बीच संपत्ति विवाद एक आम बात है, वहीं रुक-रुक कर होने वाली हिंसा इस विवाद को एक अलग रंग देती है. पन्ना जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और पन्ना निवासी उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, ''अगर जबरन घुसने के आरोप सही हैं, तो जीतेश्वरी देवी को यह नहीं करना चाहिए था. हालांकि, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामला एक ऐसे बिंदु पर आ गया जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.'' जीतेश्वरी देवी ने अपनी गिरफ्तारी के लिए राज्य के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और खजुराहो के सांसद तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पर आरोप लगाए हैं. जीतेश्वरी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया को बताया, ''छोटी-सी बात को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है. इसकी आड़ में एक सियासी साजिश चल रही है.''

इस मामले के आरोपियों में से एक सलीम खान को सबसे पहले 19 जून को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उसके बाद खान को जमानत मिल गई. दूसरी ओर, निचली अदालत ने जीतेश्वरी देवी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. लेकिन, जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 जुलाई को जीतेश्वरी देवी को जमानत दे दी थी.

इस पूर्व राजघराने की संपत्ति में राज मंदिर पैलेस, गुन्नौर तहसील के बलगाहा फार्म और लक्ष्मीपुर फार्म के अलावा बहारगंज और पुरुषोत्तमपुर में भूखंड शामिल हैं

इस राजपरिवार में पहले भी कई विवादास्पद घटनाएं हुई हैं. मानवेंद्र सिंह ने साल 2005 में अपने बेटे राघवेंद्र सिंह के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद, राघवेंद्र को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. कुछ साल बाद, मानवेंद्र सिंह और दिलहर कुमारी की बेटी कृष्णा को पन्ना शहर के बाहर तब गोली मारी गई थी जब वे अपने फार्म से लौट रही थीं. कृष्णा ने जीतेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें निचली अदालत ने जीतेश्वरी को दोषी ठहराया था. लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था.

पन्ना कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सोनी का कहना है, ''जीतेश्वरी देवी के खिलाफ पांच अन्य मामले दर्ज हैं. उन्हें पहले भी छह मौकों पर एहतियातन हिरासत में भी लिया जा चुका है.'' हालांकि कृष्णा ने इसे निजी मामला बताते हुए इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. ■

बिहार

अब गहन मंडल युग की ओर

अमिताभ श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति के विरोध के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना न करने के केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है.

जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई को लोकसभा में जातिवार जनगणना नहीं कराने की केंद्र की योजना के बारे में घोषणा की, तो इसे सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बहुत अहम यूपी विधानसभा चुनावों से पहले जातिगत मुद्दों को छेड़ने का जोखिम लेने से बचने के प्रयास के रूप में देखा गया.

केंद्र का कहना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, अन्य किसी भी वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं होगी. लेकिन नीतीश ने 24 जुलाई को पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि वे केंद्र से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगें क्योंकि इससे सबको फायदा होगा. उसी दिन, उन्होंने अपने रुख को ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाने के लिए एक ट्वीट भी किया. 24 जुलाई को पोस्ट किए गए ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, ''हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए. बिहार विधानमंडल ने दिनांक 18.02.19 एवं पुन: बिहार विधानसभा ने दिनांक 27.02.20 को सर्वसम्मति से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था. केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए.''

नीतीश का यह आग्रह बहुत महत्व रखता है क्योंकि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति-आधारित आरक्षण के समर्थन में पहले ही काफी तर्क दिए जा चुके हैं. नीतीश का मानना है कि जाति आधारित जनगणना से अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का विस्तृत जातीय आंकड़ा प्राप्त हो सकता है.

अन्य समुदायों की तरह ओबीसी, वास्तव में एक बड़ा सजातीय समूह नहीं बनाते हैं और न ही वे समान रूप से वंचित हैं. जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार को जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद करेंगे. नीति निर्माता इनका इस्तेमाल विकास की दौड़ में वास्तव में वंचित रहे लोगों की पहचान करने और उनके उत्थान के लिए कर सकते हैं.

जद (यू) का तर्क है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की मांग इसलिए कर रही है ताकि ओबीसी के लिए कोटा का समान पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जा सके. फिलहाल, नौकरियों और केंद्र से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण दिया गया है. पर, ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि सियासी रूप से संवेदनशील ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण कोटे के समान पुनर्वितरण के लिए केंद्र के बनाए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने पाया है कि इस कोटे का अधिकांश लाभ चंद जाति समूहों (देश में कुल 2,633 ओबीसी जातियों में से) ने प्राप्त कर लिया है और देश में 1,000 से अधिक ओबीसी जातियां अपनी आर्थिक और शैक्षिक अक्षमता समेत विभिन्न कारणों से, काफी हद तक आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गई हैं. बिहार का प्रमुख विपक्षी दल, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन कर रहा है.

कुछ लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना से विभिन्न जातियों के बीच सूक्ष्म स्तर पर ध्रुवीकरण संभव है, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण की गुंजाइश कम हो सकती है

सोनू किशन

जाति जनगणना के पीछे की राजनीति

लेकिन बहस राजनीति से मुक्त नहीं है. राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी के लिए नुक्सानदेह हो सकती है जो हिंदुओं को समान समूह में रखने के पक्ष में है और उससे चुनावी ताकत हासिल करती है.

पटना विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख डॉ. नवल किशोर चौधरी कहते हैं, ''यह समझना मुश्किल नहीं है कि जद (यू) और राजद जैसी पार्टियां, जो पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं, जातीय जनगणना की मांग क्यों कर रही हैं. इससे उन्हें अपनी पहचान की राजनीति मजबूत करने में मदद मिलेगी जबकि भाजपा जैसी पार्टी, जिस पर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगते हैं, कमजोर हो जाएगी. भाजपा यूपी चुनावों में इसका जोखिम नहीं उठा सकती.''

जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो जाति आधारित

सबका विकास
जाति आधारित जनगणना के समर्थन में हैं नीतीश कुमार

जातिगत जनगणना जरूरी?

- नीतीश का मानना है कि जाति आधारित जनगणना से अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का विस्तृत जातीय आंकड़ा प्राप्त हो सकता है. इससे आबादी की आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद मिलेगी
- नीति निर्माता जातिगत जनगणना के प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल विकास की दौड़ में वास्तव में वंचित रह गए लोगों की पहचान करने और उनके उत्थान के लिए कर सकते हैं
- जद (यू) का तर्कः वह अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की मांग इसलिए कर रही है ताकि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोटा का समान पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जा सके
- नीतीश जातिगत जनगणना के आंकड़े चाहते हैं ताकि वे अपनी कल्याणकारी योजनाओं को अधिक सटीक रूप से डिजाइन कर सकें

जनगणना के प्रबल समर्थकों में से एक हैं, ने दावा किया था कि इससे हिंदू-मुस्लिम संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. यादव ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि यह कैसे होगा, लेकिन उनके इस दावे का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना से विभिन्न जातियों के बीच सूक्ष्म स्तर पर ध्रुवीकरण संभव है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण की गुंजाइश कम हो सकती है.

पटना में जद (यू) के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ''यह पहले से ही खंडित हिंदू समाज को और बांट सकता है पर यह उन लोगों के बेहतर सशक्तीकरण को भी सुनिश्चित करेगा जो अब तक इससे वंचित रह गए हैं. इन सबसे बड़ी बात, यह धार्मिक ध्रुवीकरण को कम करेगा जो भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए राजनैतिक रूप से नुक्सानदेह हो सकता है.''

राजनैतिक समीक्षक इसकी तुलना नब्बे के दशक के मंडल बनाम कमंडल आंदोलन से भी करते हैं. पटना के एक वरिष्ठ जद (यू) नेता कहते हैं, ''मंदिर आंदोलन ने भी काफी उत्तेजना पैदा की और ध्रुवीकरण किया लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के सशक्तीकरण की बात करने वाले मंडल आंदोलन का प्रभाव कहीं अधिक और स्थायी है. इसने पिछड़ी जातियों के बीच ऐसी जागरूकता पैदा की है कि आज कोई भी राजनेता इसे बदलने की कल्पना भी नहीं कर सकता. दूसरी ओर, मंदिर आंदोलन एक बार की घटना थी और उसके असर को घटते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. हमारा मानना है कि जातिगत जनगणना से क्षेत्रीय दलों को बड़ी मदद मिल सकती है.''

बिहार की स्थिति

नीतीश का मानना है कि जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार को पॉजिटिव डिस्क्रिमेनेशन (संसाधनों और रोजगार के वितरण के संदर्भ में किसी वंचित समूह का पक्ष लेना) से वास्तविक और योग्य हकदारों को पहचानने और उन्हें लाभ के दायरे में लाने में मदद करेंगे. पॉजिटिव डिस्क्रिमेनेशन की नीति हमेशा से असमानता, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, को दूर करने के भारत के दृष्टिकोण के केंद्र में रही है. यही वजह है कि नीतीश जातीय जनगणना के आंकड़े चाहते हैं ताकि वे अपनी कल्याणकारी योजनाओं को सटीक रूप से डिजाइन और कार्यान्वित कर सकें.

नीतीश असल में जरूरतमंदों के पक्ष में अधिक केंद्रित पॉजिटिव डिस्क्रिमेनेशन के महत्व को समझते हैं. उनकी सरकार पहले ही आरक्षण कोटे के भीतर अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) के लिए एक अलग कोटा प्रदान कर चुकी है. बिहार ऐसी प्रणाली का अनुसरण करता है जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को दो श्रेणियों—ईबीसी और ओबीसी में बांटा गया है. केंद्र, ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देता है, वहीं बिहार ने ऐसी प्रणाली अपनाई है जिसके तहत ओबीसी को 12 फीसद, ईबीसी को 18 फीसद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3 फीसद आरक्षण दिया जाता है. वहीं, केंद्र में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ी जातियों की केवल एक श्रेणी है.

पिछले उदाहरण

महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य सरकारों ने पहले आगामी जनगणना में जातीय विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया था. अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, जिसमें पिछड़ी जातियों की आबादी 52 फीसद आंकी गई थी. कुछ ओबीसी जातियों और सवर्णों ने उस आंकड़े पर सवाल उठाया था.

यूपीए सरकार ने 2011 में जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर देश के हर परिवार का डेटा प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराई थी. इसमें भारत के महा रजिस्ट्रार (आरजीआइ) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ आवास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को शामिल किया गया था. जनगणना के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को 2015 में सार्वजनिक किया गया, पर विसंगतियों का हवाला देकर जाति आधारित आंकड़े जारी नहीं किए गए.

केंद्र की भाजपा सरकार के लिए जाति आधारित जनगणना कराना किसी दोधारी तलवार से कम नहीं होगा. लेकिन, चूंकि जाति को पहले ही सामाजिक न्याय को मापने के मुख्य मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए क्षेत्रीय राजनेताओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि आज नहीं तो कल जाति आधारित जनगणना तो होनी ही है.

राज्यों के सभी मौकों को पूरी तरह से उस राज्य के समुदायों की संख्या के अनुपात में बांटने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, पर मूल्यों को लेकर भी सवाल हैं. मिसाल के लिए क्या इस तरह का आवंटन—अगर होता और जब भी हो—खुली प्रतिस्पर्धा के रास्ते बंद नहीं करेगा और यह जाति-मुक्त समाज के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए एक बड़ा झटका नहीं होगा? इन प्रश्नों के उत्तर इतने सरल नहीं हैं. ■

क्योंझर/ओडिशा

कायापलट की पटकथा

रोमिता दत्ता

सुर्खियां

ज्ञान प्रकाश
क्योंझर के गुमुरा गांव में स्ट्रीटलाइट में पढ़ते बच्चे

साल 2020 के मध्य में एक साल की बच्ची फाल्गुनी नायक जबरदस्त कुपोषण से ग्रस्त पाई गई. उसके सिर पर बालों की छिटपुट पट्टियों का रंग बीमारी की वजह से सुनहरा भूरा हो गया. उसकी मां संयुक्ता को शक हुआ कि उसकी बीमारी का वास्ता कहीं लौह अयस्क की उस धूल से तो नहीं, जिसकी परत ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल गांव में हर चीज पर जमी रहती है. आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के जत्थे ने बीमारी का सही-सही पता लगाया.

क्योंझर में जिंदगी तकलीफदेह संघर्षों से भरी है. गरीबी का अनुपात 47 फीसद है, जबकि पिछला राष्ट्रीय औसत 28 फीसद है. मानव विकास के दूसरे संकेतक हालांकि राज्य के औसत से बेहतर हैं, फिर भी इसकी तकलीफ की तस्दीक करते हैं. जिला प्रशासन के मुताबिक, क्योंझर की शिशु मृत्यु दर (आइएमआर, प्रति 1,000 जीवित जन्म पर एक साल से छोटे बच्चों की मृत्यु से मापी जाने वाली) 2019-20 में 23.6 थी, जबकि एसआरएस 2019-20 के मुताबिक, इसी अवधि में यह ओडिशा में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 41 और भारत में 29.7 दर्ज की गई. बड़बिल गांव के परिवारों के साथ काम कर रहीं न्यूट्रिशनिस्ट और काउंसलर सानुश्री गुप्ता कहती हैं, ''फाल्गुनी को पोषण पुनर्वास केंद्र पर लाने के लिए हमें उसकी मां को 200 रुपए रोज का भत्ता देकर फुसलाना पड़ा.''

क्योंझर के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें जिले की खनिज रॉयल्टी का इस्तेमाल सामाजिक-आर्थिक हालत सुधारने के लिए किया जा रहा है. यहां मैंग्नीज, लौह अयस्क और क्रोमियम के भंडार हैं. बढ़-चढ़कर काम करने वाले आशीष ठाकरे 2018 में यहां जिला मजिस्ट्रेट बनकर आए. ठाकरे ने पाया कि 750-1,200 करोड़ रुपए की सालाना रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा है. कुछ धनराशि उन्होंने स्वास्थ कार्यक्रमों—कुपोषण, सांस की बीमारियों, मलेरिया और डेंगू से निपटने—के लिए सौंप दी. ज्यादा लंबे वक्त के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी बनाया गया.

जिले में नए डॉक्टर लाए गए. यहां तक कि अधिक वेतन देकर निजी क्षेत्र से भी लाए गए. ज्यादा वक्त रुकने को तैयार डॉक्टरों को प्रोत्साहन लाभ दिए गए. क्योंझर में डॉक्टरों की भारी कमी है: 13,154 बाशिंदों पर एक डॉक्टर है, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानक 1,000 डॉक्टरों पर एक का है. सबडिविजनल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला मुख्यालय अस्पतालों में खाली पद भरने के लिए 2019 से करीब 70 डॉक्टर नियुक्त किए गए. जिले का दावा है कि 17,000 से ज्यादा ग्रामीण मरीजों ने जिला मुख्यालय अस्पताल के सुपर-स्पेशिएलिस्ट डॉक्टरों से मुफ्त वीडियो कंसल्टेशन का लाभ लिया है. दूर-दराज के इलाकों में डिजिटल डिस्पेंसरी और डायग्नोसिस तथा जांच के लिए मोबाइल लैब की व्यवस्था से मरीजों को रेफर करने की जरूरत कम होगी और शहरों तथा कस्बों की तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव घटेगा.

ओडिशा का पिछड़ा जिला क्योंझर विकास के संकेतकों को दुरुस्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित इस्तेमाल कर रहा है

डीएमएफ फंड से मिड-डे मील की गुणवत्ता भी सुधारी जा रही है. साल में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से इसके मीनू में अंडा शामिल किया गया. इसका फायदा करीब 2,800 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 2,30,000 छात्र उठा रहे हैं. कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच या पालनाघर खोले गए. इससे छह माह से तीन साल तक के बच्चों को न केवल बेहतर सांस्थानिक पोषण बल्कि आरंभिक शिक्षा भी मिल रही है. महिलाएं भी बड़े बच्चों से मुक्त होकर उनके छोटे भाई-बहनों की बेहतर देखभाल कर पाती हैं. सबसे अहम यह कि क्रेच और उससे जुड़ी गतिविधियों पर साल में 2 करोड़ रुपए के खर्च से बच्चों में 'अपक्षय' और 'तीव्र अपक्षय' की घटनाएं कम होंगी.

जिले के अफसरों का दावा है कि क्योंझर अपने सभी 13 ब्लॉक में तमाम जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के तहत न्यूनतम मेहनताने (2020 में 298 रुपए और 2021 में 304 रुपए) की गारंटी देने वाले देश के पहले जिलों में था. कलेक्टर ठाकरे दावा करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान लौटा जिले का एक भी प्रवासी मजदूर इसी के चलते क्योंझर छोड़कर नहीं गया. खनिज क्षेत्रों में कार्यरत 6,000 महिलाओं को राज्य के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर कार्यक्रम के फंड से प्रोत्साहन सहायता दी जा रही है, जिसका मकसद महिला किसानों की आमदनी दोगुनी करना है.

ठाकरे का कहना है कि ये आमूलचूल बदलाव डीएमएफ के फंड की बदौलत मुमकिन हुए. वे कहते हैं, ''सरकार अपनी कोशिश कर रही है. हमारे पास क्षमता है तो उसका इस्तेमाल क्यों न करें?'' किस्मत ने साथ दिया तो पिछड़ा क्योंझर जल्द ही कहीं ज्यादा प्रशंसनीय कारणों से खबरों में हो सकता है. ■

www.LNCT.ac.in

LNCT GROUP OF COLLEGES
"WORKING TOWARDS BEING THE BEST"

LNCT GROUP OF COLLEGES

LNCT | JNCT | LNCTS | LNCP | LNCTE

Approved by AICTE, Affiliated to RGPV & BU, Bhopal

Why Choose LNCT Group?

- **2000+offers** for 2021 batch
- Highest Package offered **28 LPA** amazon
- **338+ Dream offer** (5.5 to 28 LPA) **Set New Records in Pandemic**
- **175+ Companies Visited 2020-21**
- **Ranked No. 1** In **Placements & Incubation Opportunities**
- **MSME approved Incubation center KLIC**
- Networking CISCO Academy & **AICTE IDEA Lab** One of only 49 idea labs in country

Most Trusted Group with **True Online Learning** and **Best Placement** During Covid Times

More than **25,000 Alumni** working in best of brands across the globe

ADMISSION OPEN 2021-22*

COURSES OFFERED

B.Tech	CSE (CSE- AIML / Data Science /IOT including BLOCKCHAIN/CYBER SECURITY /AI&DS)/ CE / EC / EE / EX / ME / IT & Lateral Entry
M.Tech	CSE / CTM / DC / Power Sys. / Structure Engg. Thermal / Power Elx. / VLSI
PHARMACY	D. Pharm. | B. Pharm. | M. Pharm. (Pharmaceutics / Pharm' Chemistry / Pharmacology)
MBA	Marketing, HR, Finance, Retails, Banking
POLYTECHNIC	ME / CIVIL
MCA	2 YEARS

LNCT GROUP 1993 28 2021 EXCELLENCE IN EDUCATION

*Admissions are based on Counseling Authorities Norms

Accreditations & Ranks

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK | NBA ACCREDITED COLLEGE | 1st Rank THE WEEK | 1st Rank Josh | 1st Rank THE WEEK | 1st Rank CAREERS360

OUR PREMIUM RECRUITERS

Cognizant vmware Infosys Tech Mahindra DXC.technology ADP Prism accenture Capgemini STANLEY amazon SAP STERLING & WILSON ORIANT dcode Business Services BYJU'S The Learning App XL Dynamics ZYCUS ValueLabs TEKsystems

LNCT Campus - Kalchuri Nagar, Raisen Road, Bhopal (MP) **Email: admission@LNCT.ac.in**

7440777111, 7440777222, 7440777555

अर्थात्

पाखंड के आर-पार

अंशुमान तिवारी

ऐसा कहां होता होगा कि भारतीय बैंक 2016 से जिन राजनैतिक लोगों को खाता खोलने और सेवाएं देने के लिए भी किस्म-किस्म की पड़ताल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को सरकार कोऑपरेटिव बैंकों में डायरेक्टर बनाती रही. शायद पाखंड ही भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत अदृश्य बहुदलीय शपथ है.

ताजा घटनाक्रम अब तक का सबसे नायाब नमूना है. जून के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में निदेशक और प्रबंध निदेशकों के पद पर सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के मनोनयन पर रोक पर लगा दी. इस तरह का कोई आदेश पहली बार जारी हुआ था. अलबत्ता इस आदेश की पावती, जब तक रिजर्व बैंक को मिलती तब तक केंद्र सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की फाइल चल चुकी थी.

यानी कि घोटालों और राजनैतिक दुरुपयोग के लंबे इतिहास के बाद पहली बार जब सहकारी बैंकों में राजनैतिक दखल खत्म करने की कोशिश शुरू हुई तो सरकार के दूसरे हाथ ने सियासी दखल की संभावनाओं को ही संस्थागत बना दिया. बहस तो सहकारिता को साफ-सुथरा, स्वायत्त और पेशेवर बनाने की थी लेकिन मंत्रालय के जन्म की बधाई बजते ही सहकारी राजनीति के सहारे देश की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने के 'गेम चेंजर प्लान' के नए नवेले डिजाइन पर तालियां बज उठीं.

इन तालियों ने ही हमें पाखंड के आर-पार देखने से रोक दिया है. रिजर्व बैंक ने 2016 में सभी बैंकों को राजनीति से जुड़े लोगों (पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन-पेप) से कारोबार करने में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश जारी किया था जो वक्त पर नए प्रावधानों से 'मजबूत' किया जाता रहा है.

मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बनी अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ के नियम के तरह जारी आदेश में सरकारों, सेना, न्यायालयों, केंद्रीय बैंक के मुखिया, सांसद, राजनैतिक दलों के शीर्ष नेता बैंकों के लिए 'हाइ रिस्क' वर्ग में रखे गए. जोखिम वाले पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की दूसरी श्रेणी में सेना, न्यायिक सेवा, सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, विधायक अन्य चुने हुए प्रतिनिधि, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हैं

यह राजनैतिक छल हमारे यहां ही मुमकिन है. जो लोग बैंकों के लिए कारोबारी तौर पर जोखिम से भरे हैं वही सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक बन जाते हैं. एक ताजा आरटीआइ सूचना के मुताबिक, 98 सरकारी कंपनियों के बोर्ड में 172 स्वतंत्र निदेशकों में 86 सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े हैं. यह प्रसाद 46 सेवानिवृत्त अफसरों में भी बंटा है.

कंपनी कानून के तहत निदेशकों को बहुत-सी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है. अगर वे किसी ऐसे फैसले में शामिल पाए जाते हैं जो उनके कारोबार या निजी हित से जुड़ा है तो उन्हें सजा मिल सकती है. लेकिन 2015 में धूम्रपान के साधनों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी निर्धारित करने वाली समिति में बीड़ी कारोबारी सांसदों को शामिल कर लिया गया.

राजनैतिक प्रभुत्व या रसूख के सहारे कारोबार (कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) करने का तंत्र लगातार पेचीदा हो रहा है. 2010 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री जयपाल रेड्डी का यह बयान चर्चा में रहा था कि लोकसभा में करीब एक-चौथाई सदस्यों पर राजनीति के जरिए कारोबारी स्वार्थ साधने का मामला बन सकता है. (एडीआर रिपोर्ट)

विधायिकाओं में अब कारोबारी पृष्ठभूमि से आ रहे लोगों की संख्या की लगातार बढ़ रही है. लोकसभा के पोर्टल के मुताबिक, 543 में से करीब (60 फीसद) 352 सदस्य इसी तरह के हैं. कुर्सी के जरिए कारोबारी फायदे उठाने का जोखिम केवल पद पर रहने तक ही नहीं है. राजनैतिक पदों पर बैठे लोग, इस दौरान मिली सूचनाओं का बेजा इस्तेमाल आगे भी कर सकते हैं.

इसे रोकने के लिए दुनिया के देशों में (ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका) राजनैतिक और सरकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए हर तरह की सूचनाएं सार्वजनिक करने पर बाध्य किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में चुने हुए प्रतिनिधियों को निजी व कारोबारी हितों के मामलों पर वोट देने का हक नहीं है. कोरिया, ताइवान और कनाडा में राजनैतिक पदों पर रहने के बाद दोबारा नौकरी या रोजगार करने के लिए तरह तरह की शर्तें हैं.

दूसरी ओर, भारत में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर रिपोर्ट 2015) के बताती है कि लोकसभा की आचरण (इथिक्स) समिति ने 2008 में कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट घोषित करने के लिए विस्तृत नियमों का सुझाव दिया था, जो कभी लागू नहीं हुए.

राजा मंत्री की अदला-बदली से भारत में दीमक वाला काठमहल इसलिए नहीं बदलता क्योंकि अब हमें सियासी खेमों में बांट कर इस पाखंड के आर-पार देखने से रोक दिया जाता है. इसलिए बात अब रिटायर्ड जजों को सियासत में लाने और सरकारी कंपनियों में अपनों को बिठाने तक सीमित नहीं है. राजनीति के हमाम के पर्दे उतर चुके हैं. कार्यकर्ताओं को सरकार में 'एडजस्ट' करना मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों का दायित्व बनने लगा है.

सनद रहे कि 2014 के चुनाव में सहकारिता मंत्रालय के गेम चेंजर दांव का नहीं बल्कि साफ-सुथरी सियासत के नए युग का वादा किया गया था, जबकि हमसे राजनैतिक पारदर्शिता के कब्रिस्तान में खड़े होकर ताली-थाली पीटने को कहा जा रहा है.

@anshuman1tiwari

शायद पाखंड ही भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत अदृश्य बहुदलीय शपथ है

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR

(University under Section 2(f) of the UGC Act)

Transforming Young Minds into Competent Professionals

FIRST STATE PRIVATE UNIVERSITY IN RAJASTHAN TO RECEIVE
NAAC A+ GRADE WITH 3.28 SCORE

ADMISSIONS OPEN 2021-2022

MUJ HIGHLIGHTS

- **68 YEARS** of Established Legacy of Manipal Education
- **485+** Highly Qualified & Experienced Faculty
- **9000+** Students
- **2.47 MILLION** Sq. Ft Built Up Area
- Upto ₹ **3 CRORES** Worth Scholarships for Meritorious & Deserving Students
- **EXCELLENT** Internships & Placement Opportunities

M.Tech. Programs
Stipend/Scholarship of
₹ 5000 to ₹ 15000 per Month
(For Meritorious and GATE Qualified Students)

State-of-the-Art Learning & Resource Centre
Member of DELNET, INFLIBNET, e-ShodhSindhu, ShodhGanga, British Council, Current Science, Indian Academy of Social Sciences, and American Library.

World Class Sports, Health and Fitness Facilities
Outdoor & Indoor Sports Facilities, Health Clinic, Swimming Pool, Gymnasium etc.

Placements 2020-21
Total offers 1250+

UG, PG & PhD PROGRAMS OFFERED IN

- ENGINEERING
- MANAGEMENT
- BASIC SCIENCES
- COMPUTER APPLICATIONS
- LAW
- HOTEL MANAGEMENT
- ARCHITECTURE & DESIGN
- HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
- BUSINESS & COMMERCE
- JOURNALISM & MASS COMMUNICATION

For Admission Scan this QR Code

For Virtual Tour Scan this QR Code

High-End Research Facilities
"Sophisticated Analytical Instrumentation Lab", "Central Analytical Facility", "Multi-Scale High-End Computing Facility", "Dassault-CATIA lab" and many more.

Holistic Development of Students
Student Clubs : 65+

Global Exposure to Students & Faculty Members
National & International Collaborations with Institutes and Universities: 100+

Spirit of Entrepreneurship Development
Entrepreneurship Cell
Startups incubated : 49

Atal Incubation Centre

SOME OF OUR MAJOR RECRUITERS IN 2020-21

CAPGEMINI | ACCENTURE | MINDTREE | CISCO | INFOSYS | ADOBE | TRELL | DELL | MICROSOFT | SECURE METERS | HEXAWARE TECHNOLOGIES | DXC TECHNOLOGY | ZS ASSOCIATES

Dehmi Kalan, Jaipur-Ajmer Expressway, Jaipur, Rajasthan - 303007

0141-3999100 (Ext. 257/142/297/301)

Follow us on :

jaipur.manipal.edu | 1800 1020 128

खास रपट
कांग्रेस

कमान संभालने की जद्दोजहद

राहुल गांधी पार्टी में कई स्तरों पर फेरबदल लाकर एक नई टीम बनाने की कोशिश में जुटे हैं, क्या वे इसमें कामयाब हो पाएंगे?

❙ कौशिक डेका ❙

बात 2010 की गर्मियों का है. तब राहुल गांधी महासचिव थे और उनके जिम्मे भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभार था. उन्होंने गुवाहाटी में पार्टी की युवा शाखा की सभा में कहा कि वे अपने वरिष्ठ नेताओं को गलती करते देखें तो आवाज उठाएं. उनकी सलाह मानकर कुछ हिम्मतवरों ने दिलेरी दिखाई और कई बड़े नेताओं के कामकाज पर उंगली उठा दी. उन्हें पार्टी में किनारे लगा दिया गया. उन्होंने राहुल गांधी का दरवाजा खटखटाया मगर उनके दफ्तर से बस इतना कहा गया कि ''संगठन की व्यवस्था का पालन करें और पहले राज्य इकाई से मदद मांगें.''

अब तकरीबन एक दशक बाद लगता है कि गांधी परिवार के वारिस की सोच में आमूलचूल बदल आ गया है. 18 जुलाई को क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया. आधिकारिक नियुक्ति तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही की, पर यह खुला रहस्य है कि राहुल और उनकी बहन, उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धू की हिमायत में कोई कसर नहीं छोड़ी. 2010 में असम के युवा कांग्रेस के विपरीत, सिद्धू को दो साल से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत में राहुल का समर्थन मिला. उन्हें प्रदेश कांग्रेस प्रमुख बनाने का फैसला सोनिया के वफादार माने जाने वाले अमरिंदर के भारी विरोध के बावजूद किया गया.

सिद्धू भाजपा से टूटकर आए हैं और कांग्रेस संगठन में खास पैठ भी नहीं रखते. लेकिन उन्हें ही आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि राहुल और अक्सर प्रियंका ने साथ-साथ ऐसे कई फैसले किए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि राहुल ने आधिकारिक तौर पर दूसरी बार पार्टी की बागडोर थामने के पहले शायद ''संगठन में सफाई'' की प्रक्रिया शुरू की है. कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इसी साल तय है. हालांकि उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बारे में खुद कुछ नहीं कहा है लेकिन उनके सहयोगियों को यकीन है कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है.

राहुल ने कई कांग्रेस दिग्गजों की कार्यशैली को लेकर अपनी असहजता कभी छिपाई नहीं. इतने साल में उन्होंने मान लिया है कि पार्टी की एकता, स्थिरता और कई बार वित्तीय सेहत की खातिर उन्हें पुराने नेताओं को साथ रखना होगा. 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने बड़े नेताओं के प्रति अपनी चिढ़ खुलकर जाहिर की थी. उन्होंने पी. चिदंबरम, अशोक गहलोत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेकर कहा था कि वे बेटों को आगे बढ़ाने में लगे रहे और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में वे अकेले हैं. साफ कहे बगैर उन्होंने इशारा कर दिया था कि भावी कांग्रेस नेताओं में वे क्या तलाश करेंगे—मोदी और भाजपा से हर स्तर पर लड़ने की अदम्य इच्छा और लोगों का ध्यान खींचने की काबिलियत.

अपनी इस तलाश में वे बाहर से प्रतिभाएं आयात करने को भी तैयार हैं. जनवरी में उन्होंने नाना पटोले को पार्टी में भाजपा से आने के तीन के साल के भीतर ही महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया. तेलंगाना में एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के पूर्व सदस्य अनुमुला रेवंत रेड्डी को जुलाई में पार्टी की कमान सौंप दी. रेड्डी टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) और टीडीपी (तेलुगु देशम पार्टी) में भी वक्त गुजार चुके हैं. कांग्रेस में वे अक्तूबर 2017 में आए. उत्तराखंड में गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया गया, जो हैं तो पारंपरिक कांग्रेसी, पर राज्य के बाहर उन्हें ज्यादा नहीं जाना जाता. गोदियाल ने सार्वजनिक बहस में सीधे मोदी को ललकारा था और

एएनआइ

इंदिरा हृयदेश (मई में जिनका निधन हो गया) सहित राज्य के बड़े नेताओं के आलोचक रहे हैं. असम में, जहां पार्टी मई में विधानसभा चुनाव हारी, रिपुन बोरा की जगह भूपेन बोरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया. देबब्रत सैकिया, प्रद्युत बोरदोलोइ और गौरव गोगोई सरीखे दूसरे बड़े नेताओं के नाम की अटकलें थीं, लेकिन जिम्मेदारी भूपेन को दी गई जो राहुल गांधी के कृपापात्र माने जाते हैं. 2013 में राहुल ने उन्हें और राणा गोस्वामी को एआइसीसी सचिव बनाया था. गोस्वामी अब असम के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं.

राहुल के तेजी से ज्यादा साहसी फैसले लेने की एक वजह अहमद पटेल की गैर-मौजूदगी लगती है, जिनका पिछले साल कोविड के चलते निधन हो गया. सोनिया के राजनैतिक सलाहकार होने के नाते वे पार्टी की धुरी हुआ करते थे, जिनके इर्द-गिर्द तमाम पुराने नेता एकजुट थे और वे उनकी बात कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचा सकते थे. अब जब तीनों—सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका—सक्रिय राजनीति में हैं, हर राजनैतिक सलाह-मशविरा इन्हीं तीनों तक सिमट गया है. पहले की तरह वे जानकारी और फीडबैक के उस तंत्र पर निर्भर नहीं हैं, जिस पर पुराने दिग्गजों का कब्जा था. केंद्रीय कमान व्यवस्था पहले ही बदल चुकी है, जिसमें के.सी. वेणुगोपाल महासचिव (संगठन) हैं और तकरीबन हर राज्य में जितेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और मणिकम टैगोर तक युवा एआइसीसी प्रभारी हैं.

अहम बात यह है कि इस प्रयोग और अपनी टीम का राहुल को इच्छित नतीजा मिलता है या नहीं. ऐसे प्रयोग उन्होंने पहले भी किए हैं, जब पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने चुनिंदा लोगों को ताकत दी और जरूरत पड़ने पर बड़े नेताओं से लोहा भी लिया. 2014 में उन्होंने अरुण सिंह, सचिन पायलट और अशोक तंवर को क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का पार्टी अध्यक्ष बनाकर भेजा था. पायलट ने 2018 के चुनाव में जीत दिलवाई, मगर बाकी दोनों छाप छोड़ने में नाकाम रहे. तंवर तो आखिरकार पार्टी छोड़कर ही चले गए. पिछले साल गहलोत के खिलाफ नाकाम बगावत की अगुआई करने के बाद पायलट अब पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ जाने के बाद अब राहुल पर निगाहें टिकी हैं कि वे पायलट के बारे में क्या फैसला करते हैं.

राहुल ने कोई साफ संकेत भी नहीं दिया है कि वे राजनीति की मांग के मुताबिक चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाले नेता बनने को तैयार हैं. वे अब भी कई अजूबे फैसले लेते रहते हैं. मसलन, पिछले दिसंबर में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले वे इटली के लिए उड़ गए. हालांकि पार्टी के सर्वोच्च पद पर न लौटने की जिद पर वे कायम हैं, लेकिन इस साल तमिलनाडु और केरल के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने हृदय परिवर्तन के संकेत दिए. उन्होंने कहा था कि वे पार्टी की इच्छा के मुताबिक कोई भी भूमिका निभाने को तैयार हैं.

नरेंद्र मोदी की सरकार कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारी नाकामी और खस्ताहाल

राज्यों के नए सिपहसालार

कांग्रेस के ये राज्य प्रमुख दो में से एक कसौटी पर खरे उतरते हैं—प्रधानमंत्री मोदी से भिड़ने का जज्बा और राहुल गांधी के प्रति वफादारी

नाना पटोले
जनवरी में महाराष्ट्र इकाई के मुखिया नियुक्त. 2018 में भाजपा से पाला बदलकर कांग्रेस में आए

अनुमुला रेवंत रेड्डी
जुलाई में तेलंगाना इकाई के मुखिया बने, एबीवीपी के पूर्व सदस्य, कुछ वक्त टीआरएस और टीडीपी में भी रहे. 2017 में कांग्रेस में आए

नवजोत सिंह सिद्धू
राहुल-प्रियंका के कृपापात्र को पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई. भाजपा से पाला बदलकर 2017 में कांग्रेस में आए

गणेश गोदियाल
जुलाई में उत्तराखंड इकाई के मुखिया बने. राज्य के वरिष्ठ नेताओं के आलोचक होने के लिए जाने जाते हैं

भूपेन कुमार बोरा
राहुल के वफादार. वे ही 2013 में एआइसीसी सचिव के तौर पर उन्हें कांग्रेस में लाए

एएनआइ

पेगासस जासूसी विरोध
नई दिल्ली के विजय चौक पर 28 जुलाई को दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ मीडिया से रू-ब-रू राहुल

राहुल में पार्टी नेताओं के बीच मतभेद मिटाने के लिए निजी पहल के बदले व्यवस्थागत प्रक्रिया को तरजीह देते हैं. वे दूसरे राजनैतिक नेताओं की तरह हर मामले में अपने को ही केंद्र में रखने यकीन नहीं करते

अर्थव्यवस्था के लिए चहुंतरफा आलोचना की शिकार है, लेकिन राहुल और इकलौती राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एकजुट हमले के लिए विपक्ष को साथ लेने की जहमत नहीं उठाई. जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के दिग्गज शरद पवार ने विपक्षी नेताओं से पींगें बढ़ानी शुरू की, जो कई लोगों की राय में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में साझा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए है, तो राहुल ने देर से कदम बढ़ाने का फैसला किया. उन्होंने पेगासस जासूसी मामले में संसद को ठप करने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक भी बुलाई और किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचने जैसा प्रहसन भी किया.

राहुल के ढुलमुल राजनैतिक बर्ताव की क्या वजह है? वे जो भी करते हैं, क्या उसमें कोई तारतम्य है, या जैसा कि पार्टी में कई आलोचक कहते हैं, क्या पार्टी उनके मिजाज के उतार-चढ़ावों के हिसाब से हिचकोले खाए? आम राय का फैसला अलबत्ता यह है कि उनसे उस तरह काम करने की उम्मीद करना भारी भूल है जैसे ठेठ हिंदुस्तानी राजनेता करता है.

उन्हें जानने वाले ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे आहत अहंकारों पर खुलकर मल्हम लगाने के बजाए व्यवस्था को तरजीह देते हैं कि शिकायतें दूर करे. मसलन, एआइसीसी के हरेक प्रभारी महासचिव और मुख्यमंत्री के पास उनका निजी मोबाइल नंबर है. मगर वे ऐसे किसी टेक्स्ट मेसेज का जवाब नहीं देते जिसमें व्यक्ति के निजी हित झलकते हों. एक करीबी सहयोगी कहते हैं, ''इससे ज्यादा कोई बात उन्हें नहीं खिझाती कि झगड़ते नेता पद और सत्ता मांगते हुए उनके पास आएं.''

राहुल के कामकाज और पार्टी की उम्मीदों के बीच फासला पंजाब संकट दूर करने के तरीके में भी साफ दिखाई दिया. राहुल कई कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ मंत्रियों से खुद मिले. सिद्धू-अमरिंदर के बीच चल रही अदावत पर उनके विचार राहुल के दफ्तर ने एहतियात से दर्ज भी किए. दोनों नेता उम्मीद कर रहे थे कि राहुल उनकी बात गौर से सुनेंगे और मानेंगे. वे

कृपापात्रों में कुर्सी बदल का खेल

राहुल ने 2007 से पार्टी की राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू किया, उसके बाद से उनके सलाहकारों और करीबियों की टोली बदलती रही है

जितेंद्र सिंह
(2007-2011)
सीडब्ल्यूसी के सदस्य और असम के प्रभारी महासचिव. नजरे इनायत तो कम नहीं हुई है, पर अब सुर्खियों से दूर रहते हैं; 2014 से अपने निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित

दिग्विजय सिंह
(2007-2012)
कभी राहुल के 'गुरु' के तौर पर देखे जाते थे, पर उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव की हार के बाद धीरे-धीरे रुतबा घट गया. उस चुनाव के वक्त राज्य के प्रभारी महासचिव थे

मीनाक्षी नटराजन
(2008-2014)
राहुल के चुने युवाओं में थीं. 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कृपापात्रों के दायरे से बाहर हो गईं

जयराम रमेश
(2008-2014)
नीतिगत मामलों पर अब भी सलाह ली जाती है, पर 2014 के पहले जैसा रुतबा अब नहीं

सी.पी. जोशी
(2012-2017)
प्रभारी रहने के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को गलत तरीके से संभालने के कारण राहुल की नजदीकी गंवा बैठे

मधुसूदन मिस्त्री
(2013-2017)
आर्थिक मितव्ययिता और आंकड़ों की जुगाली उनकी यूएसपी थी, पर जमीन पर नतीजे देने में नाकाम रहे. पार्टी के बड़े नेताओं को उनका असरदार होना रास नहीं आया

अजय माकन
(2013-2015)
खराब सेहत और पार्टी के चुनावी पराजयों ने नेपथ्य में जाने को मजबूर कर दिया. सीडब्ल्यूसी के सदस्य और राजस्थान के प्रभारी महासचिव के तौर पर फिर नजरे इनायत हुई हैं

अशोक गहलोत
(2017-2018)
2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव प्रभारी के तौर पर उनके प्रदर्शन ने राहुल पर अच्छी छाप छोड़ी. संगठन का सचिव होना उन्हें गांधी परिवार के वारिस के करीब ले आया. सचिन पायलट के मुकाबले तरजीह देकर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया

निजी मुलाकात से बचते रहे जब तक उन्हें ''समाधान नहीं दिखने लगा.''

पंजाब के दोनों नेताओं से अकेले या एक साथ नहीं मिलने के उनके फैसले में 'सही चैनल' से समाधान निकालने की जबरिया सनक ने भी बड़ी भूमिका अदा की. वे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं, इसलिए दोनों नेताओं से मिलकर गलत संदेश नहीं देना चाहते थे. सिद्धू से वे प्रियंका के जोर देने पर मिले, लेकिन कोई तस्वीर पोस्ट करने नहीं दी, जैसी उन्होंने ट्विटर पर प्रियंका के साथ डाली थी.

अमरिंदर के दूत और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब उनसे मिलने दिल्ली आए, तो राहुल ने जोर दिया कि प्रभारी महासचिव हरीश रावत और प्रियंका भी मौजूद रहें. कांग्रेस के एक सांसद कहते हैं, ''समाधान में नेता का निजी पुट होना चाहिए. बड़े नेता बैठकों में नहीं खुलते. वे मुलाकातों को तरजीह देते हैं. पार्टी न तो कॉर्पोरेट है और न एनजीओ, मगर राहुल ये बारीकियां नहीं समझते.''

राहुल के तौर-तरीकों में हर प्रक्रिया प्रभारी महासचिवों से शुरू होती है. उनके करीबी सहयोगियों के मुताबिक, राहुल जब लोगों को पद पर नियुक्त करते हैं, तो वे आंख मूंदकर उन पर भरोसा करते हैं, उनके काम में दखल नहीं देते. यही वजह है कि उन्होंने असम में विधानसभा चुनाव के लिए एआइयूडीएफ (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) के साथ गठबंधन के महासचिव जितेंद्र सिंह के फैसले में दखल नहीं दी, हालांकि कई स्थानीय नेताओं ने उन्हें इसके खिलाफ सलाह दी थी.

वफादारी का इनाम मिलता है, इसकी झलक इन दो नेताओं के आगे बढ़ने से मिलती है. एक हैं राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे पार्टी के महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल. खड़गे पार्टी के सबसे भरोसमंद संकटमोचन बनकर उभरे, जिन्हें कांग्रेस की तकरीबन हर शीर्ष समिति में जगह मिली है. वहीं, वेणुगोपाल वह शख्स हैं जिसे राहुल के तमाम फैसले लागू करने का काम सौंपा जाता है. यहां तक कि कई तो उन्हें वही भूमिका निभाते देखते हैं जो अहमद पटेल सोनिया के लिए निभाते थे. वैसे, मौजूदा व्यवस्था में प्रियंका, राहुल के राजनैतिक सलाहकार का काम करती हैं और भाई-बहन मिलकर अपनी मां के लिए थिंक-टैंक का काम करते हैं.

राजनैतिक सलाह से ज्यादा पार्टी को सत्ता में लौटने के रास्ते की जरूरत है. कांग्रेस सात साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है. ज्यादातर राज्यों से उसके पैरों की छाप तक गायब होती जा रही है. मगर राहुल किसी हड़बड़ी में दिखाई नहीं देते. वे अनुकूल माहौल का इंतजार कर रहे हैं. मगर क्या देश भी सबसे पुरानी पार्टी के जिंदा होने का अंतहीन इंतजार करेगा? ■

वास्तविक अनि

चीन तिब्बत के पठार पर अपने हवाई ठिकाने और सुविधाएं बढ़ा रहा है जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा और चीन से लगती उत्तरी सीमा पर अपनी टुकड़ियों की तैनाती में नया संतुलन बना रही है, लिहाजा, भरोसे की कमी और बातचीत प्रोटोकॉल के न होने का मतलब है कि हल्की गलतफहमी भी टकराव के मोर्चे खोल सकती है

संदीप उन्नीथन

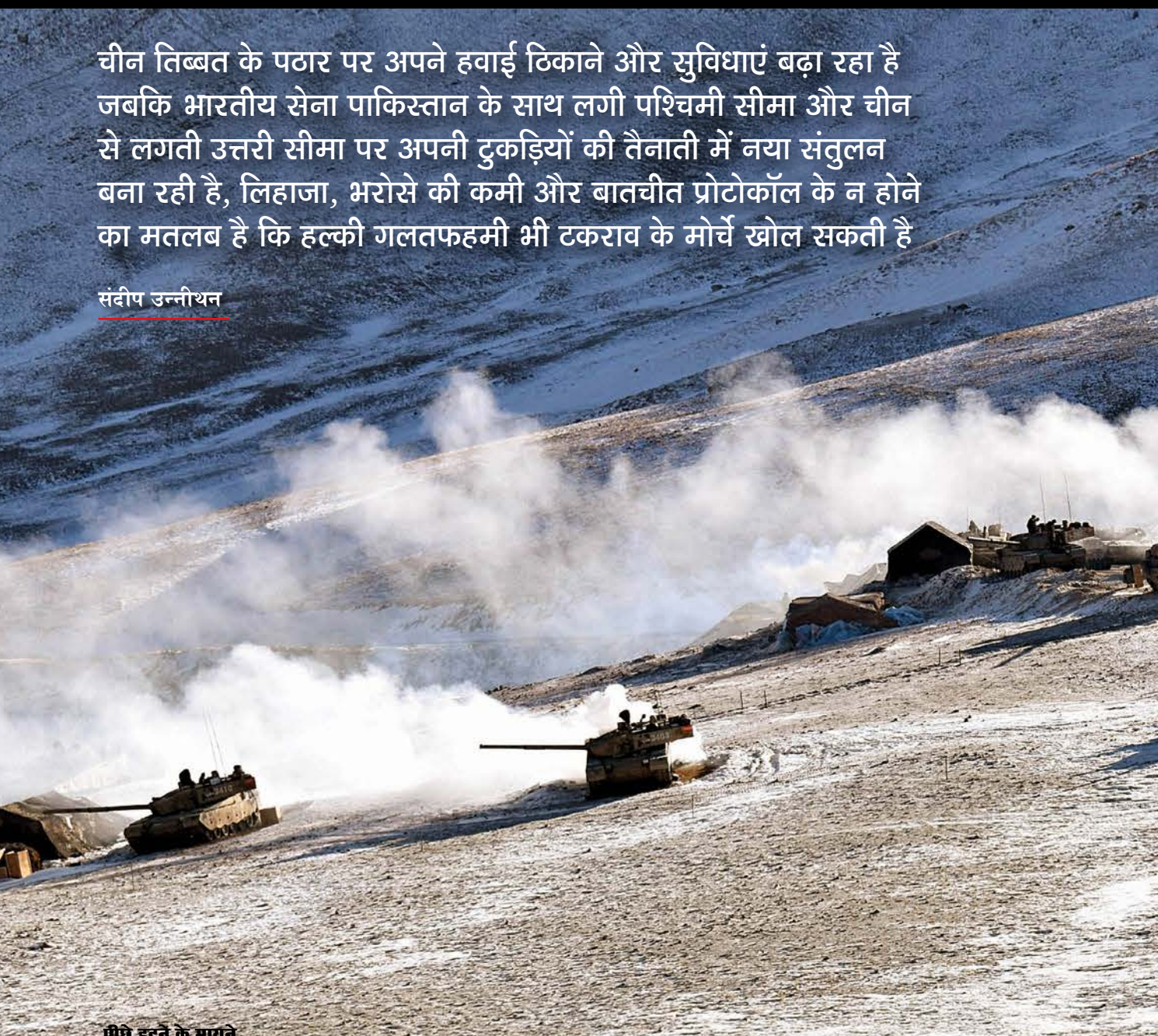

पीछे हटने के मायने
पूर्वी लद्दाख में पैंगॉंग झील के किनारों से 16 फरवरी, 2021 को भारत और चीन के सैनिक और टैंक पीछे हटते हुए

यंत्राण रेखा

उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे धूसर रंग के तिब्बती पठार के सामने भूरे रंग का कंक्रीट से बना एक विशाल विमानवाहक युद्धपोत खड़ा है. सैटेलाइट तस्वीरें चीन की तरफ निर्माण की उन्मादी गति का प्रमाण देती हैं और हाल के वर्षों में यह सबसे तेज गति है. नए एयरफील्ड्स बनाए जा रहे हैं और पुराने एयरफील्ड में नए टैक्सी ट्रैक, एप्रन और लंबे रनवे जोड़कर उनका विस्तार किया जा रहा है. लड़ाकू विमानों को तीन फुट मोटे कंक्रीट के ढांचे के बीच रखा जा रहा है जो मिसाइलों और हवा से गिराए गए प्रीसिजन बमों के हमले झेल सकते हैं. 100 किलोमीटर दूर से ही जहाजों को मार गिराने में सक्षम एचक्यू-9 मिसाइलें बेस के चारों ओर बने लॉन्च पैड में तैनात कर दी गई हैं.

एएनआइ

तिब्बत के पठार में हर इलाके में विभिन्न सैन्य स्थलों में मई से ही ट्रकों में भरकर कंक्रीट पहुंचाया जा रहा है (ऊंचाई वाले इलाकों में मई-अक्तूबर निर्माण कार्यों के लिए आदर्श मौसम होता है क्योंकि कंक्रीट सर्दियों में आसानी से सेट नहीं होता है). एक सरकारी सूत्र ने जानकारी दी कि पूरे पठारी क्षेत्र में मौजूद ट्रकों की गिनती की गई तो 800 ट्रकों को विभिन्न साइटों पर काम करते पाया गया. चीन, शिनजियांग में ताशकुरगन और तिब्बत में टिंगरी और दामसुंग में तीन नए हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है और काशगर, होतान, न्गारी-गुंसा, ल्हासा और बांगडा में मौजूदा अपने एयरबेस में बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है. इस साल मार्च में स्वीकृत बीजिंग की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-25) में तिब्बत में 20 बहुपयोगी हवाई क्षेत्रों का निर्माण प्रस्ताव शामिल था. चीन या तो एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है या नहीं तो कम से कम सीमा पर नए सिरे से युद्ध की स्थिति खड़ी करने की उसने तैयारी कर ली है.

ऊंचाई पर लगभग चार वर्षों के बुनियादी ढांचे के निर्माण और सैन्य अभ्यास के बाद, मई 2020 में पीएलए (चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी) ने पूर्वी लद्दाख में 840 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के लिए सेना की दो डिविजनों को रवाना किया था. लद्दाख में इतनी बड़ी तैनाती का पीएलए का कदम 1962 के भारत-चीन सीमा युद्ध के बाद से एलएसी को बदलने का उसका सबसे जबरदस्त प्रयास था और इसने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास-बहाली की तीन दशकों की कोशिशों को नष्ट कर दिया. भारतीय सेना पहले तो इसे बस पीएलए डिविजन का नियमित युद्धाभ्यास मान रही थी, लेकिन वह हैरान रह गई और उसने भी दो पैदल सेना डिविजन (प्रत्येक में लगभग 15,000 सैनिक) को एलएसी की ओर रवाना किया और पूरी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सेना को सक्रिय कर दिया. दोनों तरफ की सेना के आमने-सामने होने से पिछले साल 15 जून को गलवन घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय और चार चीनी सैनिकों की जान गई, जिसे नई दिल्ली अब चीन का दबाव बनाने का पैंतरा मानती है. 1967 के नाथू ला और चो ला की लड़ाई के

बाद यह जान का सबसे बड़ा नुक्सान था.

नौ महीने के गतिरोध के बाद 16 फरवरी को, दोनों देशों ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट और झील के दक्षिण के मैदानों से अपने सैनिकों, टैंकों और तोपखाने को पीछे खींच लिया, जहां भारतीय सेना ने अगस्त 2020 में मोल्डो स्थित चीनी सेना के कैंप के सामने की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था. लगभग दो किलोमीटर तक पीछे हटने के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सैन्य तैनाती में कमी या सेनाओं की पूरी तरह वापसी नहीं हुई है. भारतीय सेना चाहती है कि पहले पीएलए पीछे हटे क्योंकि उसे लगता है कि भारतीय सेना की तुलना में पीएलए ज्यादा तेजी से एलएसी तक पहुंच सकती है. इसलिए, अब एलएसी के दोनों तरफ करीब 2,00,000 सैनिक तैनात हैं.

भारत और चीन तीन जगहों—हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग के मैदान—पर एक-दूसरे के सामने आखों में आंखें डाले जमे हुए हैं. लद्दाख काफी हद तक अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित एक बंजर रेगिस्तान ही है लेकिन दोनों पक्षों के लिए सामरिक रूप से इसकी बड़ी अहमियत है. चीन ने मुख्य रूप से घुसपैठ लेह को भारतीय क्षेत्र के सबसे उत्तरी छोर से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण डीएसडीबीओ सड़क के पास की है जिसकी हिफाजत दौलत बेग ओल्डी सैन्य चौकी करती है. अक्साई चिन, जिस पर भारत अपना दावा करता है लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से ही चीन के कब्जे में है, शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ता है.

इन गतिरोध बिंदुओं के अगस्त में किसी भी समय होने वाली कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 12वें दौर में उठाए जाने की संभावना है. देपसांग पठार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर पीएलए का नियंत्रण है और वह पिछले साल से एलएसी पर पांच गश्ती क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों को गश्त नहीं करने दे रही है.

भारतीय सेना ने 15 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति में उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि फरवरी में सेनाओं के पीछे हटने की घोषणा के बाद भी भारतीय सेना और पीएलए के बीच झड़पें हुई थीं. इसमें कहा गया है कि 'दोनों पक्षों के बीच शेष मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत लगातार जारी है, संबंधित क्षेत्रों में नियमित गश्त जारी है', और जमीन पर स्थिति पूर्ववत बनी हुई है. भारतीय सेना सैनिकों की तैनाती समेत पीएलए की सभी गतिविधियों की निगरानी कर रही है.

दो एशियाई दिग्गज अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में अपनी तैयारियां चाक-चौबंद करने में जुटे हैं और चीनी वीकी (चीन की व्यूहरचना) चालों का माकूल जवाब देने के लिए भारत ने भी चतुरंगा व्यूह तैयार किया है. इस युद्ध में टैंक, सैनिक, मिसाइल और लड़ाकू जहाज, बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे.

भारतीय सेना, जिसने कभी पंजाब के मैदानी इलाकों और थार रेगिस्तान की रेतीली धरती पर युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई और तैयारियां की थीं, अब अत्यधिक ऊंचाई वाली मरुभूमि पर लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है, जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र माना जाता है. उत्तर की ओर बढ़ रहे इस कदम को आधिकारिक भाषा में 'पुनर्संतुलन या रिबैलेंसिंग' नाम दिया गया है. 2021 से पहले, सेना के 13.5 कोर में से नौ पाकिस्तान के लिए, जबकि साढ़े चार चीन के साथ (प्रत्येक कोर में 15,000 सैनिकों के साथ दो डिविजन हैं) मुकाबले के लिए रखी जाती थी. अब यह अनुपात बदल गया है और पाकिस्तान के लिए आठ और चीन के लिए छह कोर तय किए गए हैं. एलएसी पर करीब 50,000 नए सैनिकों को भेजा गया है.

सबसे महत्वपूर्ण कदम मथुरा स्थित 1 कोर की तैनाती का रहा है, जो एक स्ट्राइक कोर है और जिसे पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में हमले के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया था. उसे अब उत्तर की ओर मोड़ते हुए चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन की ओर रवाना किया गया है. एक डिविजन आकार की लगभग 15,000 सैनिकों की राष्ट्रीय राइफल्स की 'फोर्स हेडक्वार्टर' को जम्मू-कश्मीर से हटाकर लद्दाख में तैनात कर दिया गया है, जो आतंकवाद से लड़ने में महारत रखती है. पानागढ़ स्थित माउंटेन स्ट्राइक कोर के खर्च को ध्यान में रखकर 2016 में

21 जुलाई को शी जिनपिंग तीन दिन के दौरे के लिए तिब्बत पहुंचे, एलएसी के इतने करीब यह चीन के किसी राष्ट्रपति का तीन दशक में पहला दौरा है. वे ल्हासा भी गए और अपने टॉप सैन्य कमांडरों से भेंट-मुलाकात और विचार-विमर्श किया

युद्धक ठिकाने?

प्रधानमंत्री मोदी नवंबर 2020 में सेना का मुआयना करने के दौरान टैंक पर; तिब्बत में 21 जुलाई 2021 को न्यींगची हवाई अड्डे पर पहुंचते शी जिनपिंग

एपी

दो मार्चों पर नई तैनाती

2021 के पहले तक भारतीय सेना के कुल 13.5 कोर में से 9 पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, आठ पाकिस्तान के मोर्चे पर हैं तो छह चीन के सामने मुस्तैद हैं

ग्राफिक: नीलांजन दास और तन्मय चक्रवर्ती

फरवरी 2021 से पहले

भारतीय सेना की टुकड़ियों के ठिकाने*

फरवरी 2021 के बाद

भारतीय सेना की टुकड़ियों के ठिकाने*

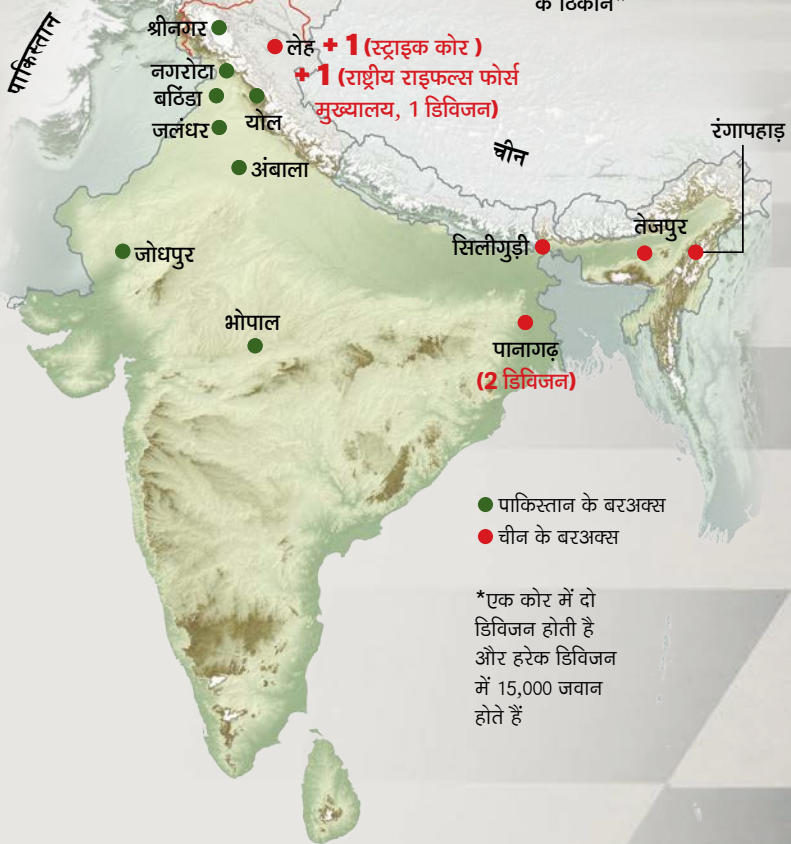

*एक कोर में दो डिविजन होती है और हरेक डिविजन में 15,000 जवान होते हैं

हवाई ताकत पर पहरा

चीन ने तिब्बत के पठार पर सैन्य हवाई सुविधाओं का अप्रत्याशित विस्तार कर लिया है. नए हवाई ठिकानों को ऐसे डिजाइन किया गया है, ताकि भारतीय जंगी जहाजों को मैदान से उड़ान भरने की बढ़त पर अंकुश लगे

भारतीय वायु सेना की बढ़त

लेह के अलावा सभी ठिकाने समुद्र तल से 1,000 फुट ऊपर या नीचे हैं

● भारतीय वायु सेना के ठिकाने

पीएलए वायु सेना के ठिकाने

सभी तिब्बत की पठार पर हैं

● अपग्रेड किया

● निर्माणाधीन

पीएलए वायु सेना अपने हवाई ठिकानों की संख्या बढ़ा रहा है, ताकि ज्यादा संख्या में जंगी विमान वहां जुटाकर भारतीय वायु सेना को बराबरी से जवाब दिया जा सके

पूर्वी लद्दाख में टकराव के ठिकाने

पीएलए ने मई 2020 में 840 किमी. एलएसी पर कई ठिकानों पर घुसपैठ की. फरवरी 2021 में चीन और भारत दोनों की सेना पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर पीछे हट गई. चीन अभी भी देपसांग मैदान, गोगरा और हॉटस्प्रिंग में काबिज

मात्र एक इन्फैंट्री डिविजन तक सीमित कर दिया गया था, अब उसे रांची में बनाए गए एक दूसरे डिविजन के साथ मजबूत किया गया है और यह कोर अब विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है.

एलएसी को 'हार्डेंड या पहले से मजबूत' कर दिया गया है. यह एक सैन्य शब्द है जो बताता है कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनात की गई है, हथियार और गोला-बारूद पर्याप्त मात्रा में जमा कर लिए गए हैं, सैनिकों को ऊंचाई पर युद्ध के लिए जलवायु की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा चुका है, और वायु सेना अलर्ट पर है. 2020 से पहले, लद्दाख में सिर्फ एक इन्फैंट्री डिविजन थी. अब वहां चार डिविजन हैं. लेह स्थित 14 कोर ने अपनी बढ़ी हुई तैनाती की शीतकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्तूबर से शुरू होने वाले सर्दियों के मौसम के लिए भोजन और ईंधन जैसी रसद का भंडारण शुरू कर दिया है.

एक शीर्ष सैन्य अधिकारी इसे स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सेना की तैनाती रणनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन (रिडिप्लॉयमेंट) बताते हैं. चीन की हरकतों के जवाब में भारत को भी उसी स्तर की तैयारियां करनी पड़ी हैं. इस तरह भारत और चीन की अस्पष्ट सीमा दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक सैन्य सीमा में बदल गई है जहां कभी भी युद्ध भड़क सकता है. पारंपरिक पूर्ण युद्ध लड़ने से ज्यादा, भारतीय सेना की तैनाती का उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ को रोकना और अपने सैनिकों का उपयोग करके 'जैसे को तैसा' की तर्ज पर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने वाला सैन्य अभियान छेड़ना है. इसके पीछे सोच यह है कि भारतीय सेना के कब्जे वाले चीनी इलाकों का बाद में समझौता वार्ता के दौरान लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है. फिर भी, ये तैनातियां जोखिम से भरी हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच 1996 में हुई सीमा पर हथियार इस्तेमाल न करने वाली संधि, 2020 में पीएलए घुसपैठ के बाद खत्म हो गई.

नॉर्दर्न आर्मी के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) डी.एस. हुड्डा कहते हैं, ''इस तरह की संधि की अनुपस्थिति में कोई छोटी-सी स्थानीय घटना भी युद्ध भड़का सकती है. यह एक बड़ी चिंता बनी हुई है. मसलन, वे (चीनी) एक स्थान पर घुस आते हैं, तो क्या हम उन्हें सिर्फ उसी क्षेत्र में खदेड़ने की कार्रवाई करने जा रहे हैं या हम उनके इलाके में घुसकर किसी दूसरी जगह पर कब्जा कर लेंगे?'' विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तेजी से अनियंत्रित रेखा बन रही है जो खतरनाक सैन्य टकराव का कारण बन सकती है.

अमेरिकी थिंक-टैंक स्ट्रैटेजिक फ्यूचर्स ग्रुप की 7 अप्रैल की एक रिपोर्ट में भी ऐसा अंदेशा जताया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि दो परमाणु शक्तियां 'युद्ध में उलझ सकती हैं' जिसे कोई भी पक्ष नहीं चाहता है. शीर्ष अमेरिकी खुफिया निकाय नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करने वाले थिंक-टैंक का कहना है कि ऐसा हो सकता है 'खासकर अगर विवादास्पद सीमा पर तैनात सैन्य बल, एक-दूसरे को चुनौती देने के लिए सीमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करते हैं तो उससे युद्ध भड़क सकता है.' शोधकर्ता केटियन झांग अपनी 2018 की एमआइटी डॉक्टरेट थीसिस, 'कैलकुलेटिंग बुली: एक्सप्लेनिंग चाइनीज कोएर्सन' में लिखती हैं, ''चीन को अब तक सैन्य बल प्रयोग के कारण भू-राजनीतिक नुक्सान काफी कम हुआ है.''

घुसपैठ के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट बहुत बढ़ गई है. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन के साथ रिश्ते तभी बहाल हो सकते हैं जब वह यथास्थिति के लिए राजी हो जबकि चीन चाहता है कि भारत ऐसी कोई शर्त रखे बिना संबंधों को बहाल करे. पिछले साल भारत ने 267 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस साल मई में, भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने चीनी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हुएई और जेडटीई को भारत में फिफ्थ जेनरेशन या 5जी दूरसंचार सेवाओं के परीक्षणों से रोक दिया. हालांकि, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है. यह पिछले साल बढ़कर 77 अरब डॉलर हो गया. चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है.

15 जुलाई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. उन्होंने नई दिल्ली की उसी लाइन को दोहराया कि 'एलएसी पर यथास्थिति में एकतरफा बदलाव भारत को स्वीकार्य नहीं होगा.' विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, 'हमारे संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और विश्वास की पूर्ण बहाली और उसे बरकरार रखना आवश्यक है.'

पीएलए वायु सेना और पीएलए थल सेना ने अपनी मिसाइल यूनिट की नई नेटवर्किंग की है, और तिब्बत के पठार पर वायु सुरक्षा का बड़ा तंत्र तैयार कर लिया है. लेकिन भारतीय वायु सेना को अभी काफी बढ़त हासिल है और स्ट्राइक पावर भी मजबूत है

दबाव का चीनी नुस्खा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बहुत ही प्रतीकात्मक यात्रा में, तिब्बत के तीन दिवसीय अघोषित दौरे के लिए 21 जुलाई को न्यींगची मेनलिंग हवाई अड्डे पर उतरे. न्यींगची प्रांत

एलएसी के काफी करीब तिब्बत में ग्यारी गुंसा असैनिक हवाई अड्डे की गूगल अर्थ इमेज; मई 2020 में लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद इसका विस्तार किया गया और सैन्य विमानों के लिए सुविधाएं बनाई गईं

अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 20 किमी उत्तर में है. भारतीय राज्य अरुणाचल को चीन 'दक्षिणी तिब्बत' बताकर उस पर अपना दावा करता है. तीन दशकों में एलएसी के पास किसी चीनी राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है. शी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग यूक्सिया भी शामिल थे. शी ने ट्रेन से ल्हासा की यात्रा की, जहां उन्होंने क्षेत्र के शीर्ष सैन्य कमांडरों को अलग से संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर सार्वजनिक रूप से बधाई दी तो उसके ठीक एक पखवाड़े बाद शी की यह यात्रा हुई. रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव और वर्तमान में सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस ऐंड स्ट्रैटेजी के अध्यक्ष जयदेव राणाडे कहते हैं, ''इस मोड़ पर शी की तिब्बत यात्रा इंगित करती है कि लद्दाख में घुसपैठ एकबारगी नहीं थी; वह हमारे खिलाफ अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की एक वृहत चीनी योजना का हिस्सा है और इस पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए.''

2012 में शी के सत्ता में आने के बाद चीन का लगातार बढ़ता साम्राज्यवादी रुख, भारत के साथ उसके सीमा विवादों और उसके लिए उठाए गए कदमें में झलकता है. 2013 के बाद से चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी परिणति 2020 में सैनिकों की झड़प में दिखी. पीएलए, खासकर नई दिल्ली को डराने के लिए तैयारियां कर रहा है. पीएलए की तीन बड़ी घुसपैठ 2013 में दौलत बेग ओल्डी और चुमार में और 2014 में डेमचोक में देखी गई.

नई दिल्ली ने शी की बेल्ट ऐंड रोड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से दूरी बनाए रखी है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर कड़ी आपत्ति जताई है.

सीमा पर भारी तैनाती और हिमालय क्षेत्र में शीत युद्ध की स्थिति पैदा करना चीन का पुराना खेल रहा है. बीजिंग सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करके धौंस जमाने की कोशिश करता आया है. पिछले एक दशक में, चीन ने दक्षिण चीन सागर को चीन की एक झील में बदलने और वियतनाम और फिलीपींस जैसे समुद्री पड़ोसियों को डराने के प्रयास में मानव निर्मित द्वीपों में हवाई पट्टियां तैयार की हैं और मिसाइल तैनात किए हैं. तिब्बत में इसकी निर्माण गतिविधि इस बात का संकेत है कि ताइवान को चीन में मिलाना जहां उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है—जैसा कि 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर शी ने अपने भाषण में कहा था—बीजिंग जब चाहे भारत के साथ विवादित सीमा पर धावा बोल सकता है.

चीन ने गोलमुड से ल्हासा को जोड़ने वाली 1,142 किलोमीटर लंबी किंघाई-तिब्बत रेलवे (क्यूटीआर) का काम 2006 में पूरा कर लिया था और उसके साथ ही सैन्य हवाई क्षेत्रों और सड़कों का विशाल नेटवर्क भी खड़ा किया. दुनिया के सबसे ऊंचे रेलमार्ग तिब्बत-किंघाई रेलवे के जरिए चीन एलएसी पर सैनिकों को हफ्तों के बजाय चंद दिनों में भेज सकता है. भारत का बुनियादी ढांचा निर्माण कार्य धीमा ही रहा है और इसने 2015 के आसपास ही गति पकड़ी. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का सड़कों और पुलों का तेजी से निर्माण सैन्य गतिरोध और महामारी के बीच भी जारी रहा. इस साल 28 जून को लद्दाख का दौरा करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 63 पुलों का उद्घाटन किया. 240 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं में लेह-लोमा सड़क पर 50 मीटर लंबा पुल है, जो 'तोपखाने, टैंकों और अन्य विशेष उपकरणों सहित भारी हथियारों की आवाजाही' दुरुस्त करेगा.

बीआरओ के 2023 तक एलएसी से लगती सभी 61 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने की उम्मीद है. ये सड़कें सेना और सैन्य साजो-सामान को सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से पहुंचाने में सक्षम होंगी और 2009 के सीक्रेट वारगेम 'डिवाइन मैट्रिक्स' में सामने आई कुछ कमियों को दूर करने में सक्षम होंगी. इस गुप्त अभ्यास ने बताया कि युद्ध की स्थिति में चीनी सेना बुनियादी ढांचे की बदौलत किस प्रकार निर्णायक बढ़त हासिल कर लेगी. इसने युद्ध को तिब्बत तक ले जाने के लिए एक नई पर्वतीय आक्रमण वाहिनी (स्ट्राइक कोर) को खड़ा करने की जरूरत पर बल दिया. वारगेम में सेना 1962 वाला युद्ध फिर से लड़ रही थी, और इसमें पीएलए वायु सेना पर भारतीय वायु सेना की बढ़त को शामिल नहीं किया गया था.

2017 में भारत और चीन के बीच 72-दिवसीय डोकलाम गतिरोध के दौरान बोलते हुए, पूर्व एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने डोकलाम में कहा था कि तिब्बती पठार पर पीएलए वायु सेना की तैनाती आक्रामक अभियानों के लिए नहीं थी, ''वे समझते हैं कि तिब्बत के हवाई क्षेत्रों और इन हवाई क्षेत्रों में अंतर है.'' अगस्त 2021 में समझा जा सकता है कि वे अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं. इन नए ठिकानों से, चीन पूरे उत्तर भारत में सैकड़ों लड़ाकू जहाज, बमवर्षक और यूसीएवी (मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन) भेज सकता है. भारत के मैदानों से हिमालय पर चढ़ने वाले लड़ाकू जहाजों, जिन पर हथियार का पूरा भार और ईंधन होता है, पर हमले के लिए चीन ने लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी हैं. (पठार पर होने के कारण चीनी लड़ाकू जहाज उनका सामना नहीं कर सकते, *बॉक्स देखें*) लेह स्थित 14 कोर के पूर्व जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा कहते हैं, ''ये सभी घटनाक्रम अलग स्तर की प्रतिस्पर्धा और एक नई तरह की हवाई कार्रवाई की रणनीति की जरूरत बताते हैं, इसलिए नए वारगेम तैयार करने होंगे और नए तरीके से योजनाएं बनानी होंगी.''

चीन की तरफ से सेना-केंद्रित सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में पहला उछाल

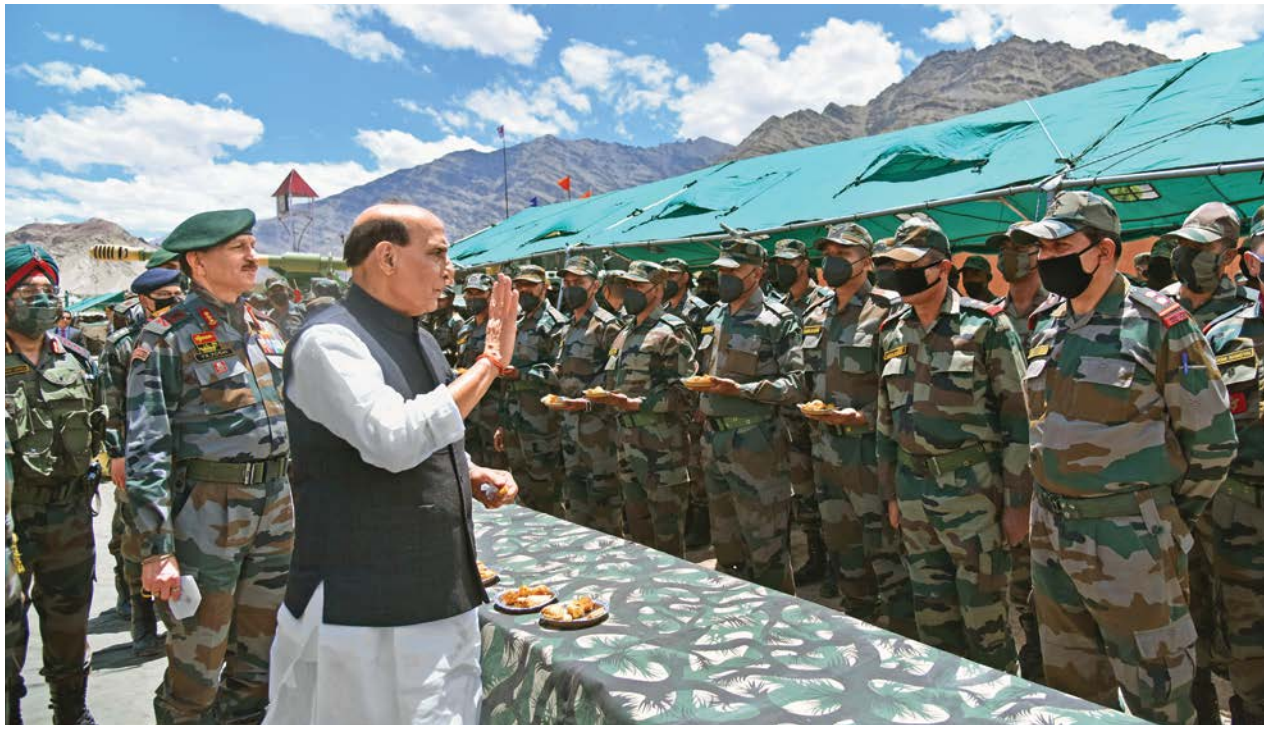

एएनआइ

अग्रीम मोर्चे पर
लेह के कारु सैन्य ठिकाने पर 28 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

भूटान के डोकलाम पठार पर 2017 के गतिरोध के बाद आया. पीएलए ने एलएसी के नजदीक अपने सैन्यबलों को ठहराने के लिए गर्म, तापरोधक सैन्य आश्रयों, सप्लाइ डिपो और अड्डों का निर्माण शुरू किया. मई 2020 में जब टुकड़ियों को लाया और पूरी सर्दियां रखा गया, तो इतनी ऊंचाई पर यह उनकी पहली तैनाती थी. फिर जब लड़ाकू विमान और गनशिप तेजी से उस इलाके में भेजे गए, तो सरहदी गतिरोध पर भारतीय वायु सेना की प्रतिक्रिया का जायजा लेकर चीनियों ने सैन्य हवाई बुनियादी ढांचे का विस्तार शुरू किया. वायु सेना के एक अफसर स्वीकार करते हैं, ''हवाई बुनियादी ढांचे के दूसरे दौर का लक्ष्य हमारी वायु सेना की लड़ाकू धार का मुकाबला करना है.''

शिलांग स्थित ईस्टर्न एयर कमान ने कुछ साल पहले आयोजित वारगेम में हिमालय के ऊपर उड़ान भरते और भारतीय वायु सेना के एयरबेस को तरबतर करते चीनी बमवर्षकों की तरंगों का वर्णन किया गया था. भारतीय वायु सेना के लिए चिंता की बात यह है कि बीते कुछ महीनों में पीएलए वायु और थल सेना ने अपनी मिसाइलों का नेटवर्क स्थापित करके विशाल हवाई रक्षा कवच बना लिया है. हालांकि रक्षा विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय वायु सेना को अब भी मजबूत बढ़त हासिल है. उसके थिंक-टैंक सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज (सीएपीएस) के डायरेक्टर-जनरल एयर मार्शल अनिल चोपड़ा कहते हैं, ''बनिस्बतन निचली जगहों पर स्थित अपने तमाम अड्डों से हम 250-300 लड़ाकू विमान सही जगह तैनात कर सकते हैं. चीनी लद्दाख के नजदीक होतान, काशगर और न्गारी-गुंजा से 70-90 से ज्यादा विमान मैदान में नहीं उतार सकते.''

अभी यह पूर्वानुमान जल्दबाजी होगी कि सैन्य विमानन के विस्तारित बुनियादी ढांचे का नतीजा उस किस्म की चीनी हवाई घुसपैठों में होगा या नहीं, जो जापान और ताइवान को धमकाने के लिए दक्षिण और पूर्वी चीन सागरों के ऊपर देखी गई थीं. मगर विशेषज्ञ किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर फॉर सिक्योरिटी, स्ट्रैटजी ऐंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर राजेश्वरी पिल्लै राजागोपालन कहती हैं, ''मुझे नहीं लगता कि भारत-चीन मोर्चे पर चीजें शांत होंगी, न तो विदेश नीति के स्तर पर और न ही सरहदी इलाकों में. सक्रियता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए

करगिल युद्ध के करीब 22 साल बाद भी थल सेना और वायु सेना के पास अभी भी मैप ग्रिड की एक रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो साझा आक्रमण अभियान छेड़ने के लिए बेहद जरूरी है. इस पर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

चीन तीव्रता कम करने को तैयार नहीं लगता. उलटे वह और मोर्चे खोल रहा है.''

भारत के विकल्प क्या हैं?

चीन के भारी जमावड़े से तकलीफदेह हकीकत सामने आती है, जिससे भारत का वास्ता पहले नहीं पड़ा—दरवाजे पर महाशक्ति देश के आ धमकने की संभावना. सेना के लिए यह बदतरीन आशंका—चीन और उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान के साथ धधकती अनसुलझी सरहदों की आशंका—का सच होना है. जीडीपी का भारी फर्क (चीन का 149 खरब डॉलर और भारत का 26 खरब डॉलर) रक्षा बजटों पर दिखाई देता है. चीन का रक्षा बजट 252 अरब डॉलर है जबकि भारत का 72 अरब डॉलर. चीन ने शीत युद्ध के बाद किसी भी देश के सबसे बड़े सैन्य विस्तार की शुरुआत की, जिसकी देखरेख माओ त्से तुंग के बाद बीजिंग के सबसे ताकतवर नेता कर रहे हैं.

भारत के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वह चीन को टकराव भड़काने से भयपूर्वक रोकने के लिए सैन्य बाहुबल का निर्माण करे. लद्दाख के गतिरोध का नतीजा यह होगा कि नई हथियार प्रणालियों के लिए दौड़-भाग मच जाएगी. कम से कम छोटे वक्त के लिए तो मच ही जाएगी. सरकारी सूत्र बताते हैं कि भारतीय वायु सेना को जल्द ही 36 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का मामला शुरू करना है. ये उन 36 राफेल के अलावा होंगे, जो 2016 में फ्रांस से खरीदे गए थे और जो सभी जून 2022 तक आ जाएंगे. वायु सेना के एक अफसर कहते हैं, ''राफेल पीएलए वायु सेना के बेड़े से बेहतर हैं.'' रक्षा बजट की पूंजीगत खरीद में 40 फीसद हिस्सा रखने वाली वायु सेना चाहती है कि यह सौदा जल्द हो ताकि विमानों की नई खेप तीन साल बाद आना शुरू हो जाए, जैसा कि फ्रेंच मैन्यूफैक्चरर डासो एविएशन ने संकेत दिया है. वायु सेना को अपने विमानों के लिए ब्लास्ट पेन यानी अंग्रेजी के 'ई' के आकार के दोहरे कक्षों की तादाद बढ़ाने, ईंधन और भंडारों सरीखा अहम विमानन बुनियादी ढांचा भूमिगत रखना शुरू करने की जरूरत है, ताकि इन्हें पूर्वरोधक हमलों से बचाया जा सके. उधर, सेना अपनी नई तैनात स्थापनाओं को लैस करने के लिए 350 हल्के टैंक और 400 तोपें चाहती है.

विश्लेषक मानते हैं कि चीनी आक्रमण की लागत बढ़ाने के लिए भारत को एलएसी को मजबूत बनाने की जरूरत है. पूर्व डी-जी आर्टिलरी, लेफ्टि. जनरल पी. रविशंकर कहते हैं, ''चीन महाशक्ति बनना चाहता है, हम नहीं. हम एलएसी को मजबूत करके इसकी अच्छी हिफाजत करते हैं, तो चीन के लिए इसका अर्थ होगा सैन्यबलों और हथियारों में और ज्यादा निवेश. वह भी वहां जिसे वह अपना दूसरे दर्जे का थिएटर मानता है. साथ ही, प्राथमिक थिएटर की कीमत पर, जो ताइवान है. सैन्य बलों का विन्यास और तैनाती कितनी भी बढ़ाएं, नतीजा ढाक के तीन पात ही है.''

टुकड़ा-टुकड़ा खरीद से कहीं ज्यादा भारत को चाहिए कि लंबे वक्त से टलते आ रहे सैन्य सुधारों को परवान चढ़ाए. चीनियों ने तिब्बत में अपने हथकंडे 2016 में शुरू किए, जब उन्होंने अपने सैन्य सुधार पूरे कर लिए, इफरात सैनिकों से भरे सैन्यबलों में कटौती की और हवाई तथा जमीनी सैन्यबलों को जोड़ने और टेक्नोलॉजी-सघन चलित बल बनाने के साथ सात सैन्य क्षेत्रों को मिलाकर पांच सैन्य थिएटर बना लिए. भारत ने 2023 तक 17 एकल-सेना कमान को जोड़कर पांच एकीकृत थिएटर कमान बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू की है.

इस किस्म की सिफारिशें लेफ्टि. जनरल डी.बी. शेकटकर की अगुआई वाली विशेषज्ञों की समिति ने 2016 में की थीं—कि सैन्यबलों को पहाड़ी ऊंचाइयों पर युद्ध के लिए तैयार करें, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ देश की विवादित सीमाएं 10,000 फुट ऊंचे इलाकों में ही हैं. इन सिफारिशों को अब गंभीरता से उलटा-पलटा जा रहा है. उनमें कुछ सबक अब तक सीखे नहीं गए हैं, बावजूद इसके कि करगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जिसमें वायु सेना को पाकिस्तानी टुकड़ियों की कब्जाई चोटियों और बंकरों पर बम बरसाने के लिए ऊंचाई की व्यूह-रचनाओं में तुरत-फुरत सुधार करने पड़े थे. करगिल के बाईस साल बाद भी सेना और वायु सेना के पास एक जैसी रेडियो फ्रीक्वेंसी और मैप ग्रिड नहीं हैं, जो संयुक्त हमलावर अभियानों में तालमेल के लिए बेहद जरूरी हैं.

कहते हैं, भारतीय नौसेना ने चीन से सीमा पर जमीनी टकराव छिड़ने पर उसकी जहाजी बेड़ों को मलक्का जलडमरूमध्य में अटकाने की आपात योजना तैयार की है लेकिन यह योजना बेहद जोखिम भरी है

चीन के मुकाबले इस सैन्य असंतुलन को कम से कम कुछ हद तक दूर करने के लिए भारत अब अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के 'क्वाड' में सक्रियता से हिस्सा ले रहा है. चारों देशों ने अब तक का अपना सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास पिछले नवंबर में बंगाल की खाड़ी में किया, जब चीन के साथ टकराव चल रहा था. 12 मार्च को चार क्वाड देशों के शासन प्रमुखों—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन—के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में 'कानून के शासन, नौवहन और ऊपर से उड़ने की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और भूभागीय अखंडता' का समर्थन किया गया.

क्वाड की एक बड़ी कमजोरी है—इसका तकरीबन पूरा जोर समुद्री क्षेत्र पर है. भारतीय अधिकारी स्वीकार करते हैं कि ऊपर बताए तीनों सदस्यों में से एक के भी चीन-भारत भूमि विवाद में उलझने की संभावना नहीं है. यह लड़ाई भारत को अपने दम पर लड़नी होगी. जमीन पर टकराव की स्थिति में मलक्का जलडमरूमध्य में चीनी जहाजों को बीच में रोकने की आकस्मिक योजनाएं भारतीय नौसेना के पास हैं, मगर इससे अंतरराष्ट्रीय जल विवाद छिड़ने का खतरा है. इसलिए जैसा कि फॉरेन कोऑपरेशन ऐंड नैवल इंटेलिजेंस के पूर्व फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे कहते हैं, ''हिंद महासागर में चीन के घुसने (जिसकी संभावना हो सकती है) का इंतजार करने के बजाय भारत दक्षिण चीन सागर में नौसैन्य बढ़त लेने और युद्ध के लिए तैयार होने के तरीकों और साधनों पर विचार कर सकता है. यहां समुद्री ताकत की पहुंच और आक्रामण की क्षमता अहम होगी.'' चीन हिमालय को गुस्से से खौला देने की धमकी दे रहा हो, तो ऐसे में कोई भी विकल्प दूर की कौड़ी नहीं. ■

इंडिया टुडे

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

इंडिया टुडे-एमडीआरए बेस्ट यूनिवर्सिटीज सर्वे 2021 में देश के उच्च शिक्षा का खाका तैयार कर उन विश्वविद्यालयों को उजागर किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव लाए हैं और विद्यार्थियों को सीखने का अनूठा अनुभव दिया है

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

कामयाबी की दौड़ में आगे

समाज की बदलती जरूरतों के मुताबिक अपने को नए स्वरूप और नए पदानुक्रम में तेजी से ढालने में कामयाब यूनिवर्सिटी पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता में भी सबसे अगली कतार में मौजूद

कौशिक डेका

बा की दुनिया की तरह पिछला एक साल भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहद मुश्किलजदा और खास रहा. कोविड-19 महामारी ने न केवल शैक्षणिक कैलेंडर चौपट कर दिया, बल्कि छात्रों की पढ़ाई में भी जबरदस्त फासला पैदा किया. टीमलीज के 'कोविड-19 लर्निंग लॉस इन हायर एजुकेशन' सर्वे ने छात्रों की पढ़ाई-लिखाई का 40 से 60 फीसद के बीच नुक्सान होने का अनुमान लगाया है. यह जी7 देशों में पढ़ाई-लिखाई के अनुमानित नुक्सान से दोगुना है. सर्वे का अनुमान है कि इस फासले को भरने में तीन साल लग सकते हैं.

हर संकट अलबत्ता अवसर की एक खिड़की भी खोलता है. महामारी से पैदा उथल-पुथल ने सरकार, नीति निर्माताओं और अकादमिक क्षेत्र के अगुआओं को शिक्षा देने के नए तरीकों और ढांचों पर विचार करने के लिए बाध्य किया. बुनियादी ढांचे की बहुत-सी अड़चनों के बावजूद वर्चुअल पढ़ाई-लिखाई अचानक आम ढर्रा बन गई. छात्र और शिक्षक कक्षा की पढ़ाई से लेकर शोध कार्य तक कम या ज्यादा कामयाबी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर करने लगे. जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति (एनईपी) की शुरुआत ने उच्च शिक्षा में और ज्यादा सुधारों के लिए उत्प्रेरक का काम किया. यह नीति देश के विश्वविद्यालयों की बहु-विषयी शिक्षा और शोध केंद्रों के रूप में परिकल्पना करती है जिनका उद्देश्य देश की समस्याओं के सार्थक और स्थानीय समाधान देना हो.

देश के शीर्ष विश्वविद्यालय एनईपी की आकांक्षाओं से मेल खाने वाले लक्ष्यों के अनुरूप माहौल बनाने में तेजी से आगे आए हैं. दिल्ली का जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) कैंपस से स्टार्ट-अप कंपनियां लॉन्च करके अपने शिक्षकों को नवाचारी-उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं आइआइटी दिल्ली इंजीनियरिंग की पढ़ाई को समाज विज्ञान से जोड़ रहा है. नेशनल लॉ

नं. 1 यूनिवर्सिटी देश की

कटगरी	यूनिवर्सिटी
जनरल नं. 1 (सरकारी)	**जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,** *नई दिल्ली*
नं. 1 (निजी)	**एमिटी यूनिवर्सिटी,** *उत्तर प्रदेश*
मेडिकल नं. 1 (सरकारी)	**ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,** *नई दिल्ली*
नं. 1 (निजी)	**श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी),** *चेन्नै*
टेक्निकल नं. 1 (सरकारी)	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,** *नई दिल्ली*
नं. 1 (निजी)	**इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर,** *बेंगलूरु*
लॉ नं. 1 यूनिवर्सिटी	**नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर,** *बेंगलूरु*

चंद्रदीप कुमार

396
यूनिवर्सिटी का प्रबंधन निजी हाथों में

420
यूनिवर्सिटी ग्रामीण इलाकों में स्थित

17
यूनिवर्सिटी सिर्फ महिलाओं के लिए

0.5
फीसद छात्रों का दाखिला पीएचडी के लिए

स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में जोर छात्रों को वर्चुअल कोर्ट रूम के लिए तैयार करने पर है, क्योंकि वर्चुअल कोर्टरूम महामारी के बाद की दुनिया में भी आम ढर्रा बन सकते हैं. यह हर क्षेत्र की बढ़ती जरूरत बनने लगा है.

अलबत्ता, जैसा कि जेएनयू के वाइस-चांसलर एम. जगदीश कुमार कहते हैं, ''देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में तो महज थोड़े-से छात्र ही पढ़ते हैं, हमारे करीब 60 फीसद विश्वविद्यालय ग्रामीण इलाकों में हैं. ऐसे में उच्च शिक्षा के छात्र देश भर में फैले हुए हैं. राष्ट्र की तरक्की के लिए देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता में एकरूपता लाना बेहद जरूरी है.'' इसका एक तरीका यह है कि उनके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया जाए. *इंडिया टुडे* ग्रुप का बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्वे देश के उच्च शिक्षा केंद्रों के बीच स्वस्थ अकादमिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने और इस तरह उन्हें ज्यादा उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है.

पढ़ाई और अपने करियर को सही दिशा देने के इच्छुक छात्र के लिए भी सही विश्वविद्यालय की तलाश बेहद अहम है. देश

कैसी यूनिवर्सिटी

	यूनिवर्सिटी कटगरी	कुल
1	सेंट्रल यूनिवर्सिटी	48
2	सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी	1
3	इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपर्टिंस	135
4	स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी	386
5	राज्य विधायी कानून के तहत बने संस्थान	5
6	स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी	14
7	स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी	327
8	स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी	1
9	डीम्ड यूनिवर्सिटी-सरकारी	36
10	डीम्ड यूनिवर्सिटी-सरकारी सहायता प्राप्त	10
11	डीम्ड यूनिवर्सिटी-प्राइवेट	80
12	कुल	1,043

विषयवार वितरण

	कटगरी	कुल
1	सामान्य	522
2	मेडिकल	66
3	टेक्निकल	177
4	लॉ	23

*बाकी दूसरी श्रेणी में

बढ़ता दायरा

पिछले पांच साल में यूनिवर्सिटी की संख्या में 30 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई

	वर्ष	यूनिवर्सिटी की संख्या
	2015-16	799
	2016-17	864
	2017-18	903
	2018-19	993
	2019-20	1,043

टॉप 5 राज्य, जहां सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं

	राज्य	यूनिवर्सिटी की संख्या
1	राजस्थान	89
2	उत्तर प्रदेश	81
3	गुजरात	76
4	कर्नाटक	69
5	मध्य प्रदेश	66

की अव्वल रिसर्च एजेंसी मार्केटिंग ऐंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स (एमडीआरए) से कराए जा रहे सालाना सर्वे अपने मजबूत तौर-तरीकों की वजह से भारतीय विश्वविद्यालयों के अकादमिक और बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में निर्णायक बनकर उभरा है. इसकी अहमियत हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसे लगातार नई जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है. संस्थानों को चार धाराओं—सामान्य, चिकित्सा, तकनीकी और कानून—में रैंक दी गई हैं. निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसार में उत्तरोत्तर ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं, सर्वे में उन्हें सामान्य धारा के तहत अलग से रैंक दी गई. रैंकिंग की विश्वसनीयता का अंदाजा इसमें भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की लगातार बढ़ती संख्या से लगाया जा सकता है, जो 2019 में 120 से बढ़कर 2020 में 133 और इस साल 150 हो गए.

इस साल की रैंकिंग से सबसे उत्साहजनक और मार्के की बात यह पता चली कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी खास इलाके तक सीमित नहीं है. मसलन, सामान्य श्रेणी के 10 शीर्ष सरकारी विश्वविद्यालयों में से चार उत्तर भारत में हैं, तो निजी क्षेत्र के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की फेहरिस्त में दक्षिण भारत का दबदबा है. इसी तरह मेडिकल, तकनीकी और कानून के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय विभिन्न इलाकों में समान रूप से बंटे हैं.

चिंता की बात अलबत्ता यह है कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में खासा फासला है. सरकारी श्रेणी के शीर्ष 10 सामान्य विश्वविद्यालयों ने 2,000 में से 1,885 से 1,600 के बीच अंक हासिल किए. वहीं निजी विश्वविद्यालयों ने 1,618 से 1,407 के बीच अंक पाए. शीर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने 1,954 अंक प्राप्त किए, तो शीर्ष निजी मेडिकल कॉलेजों ने 1,446 अंक हासिल किए. सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के बीच यह फर्क तकनीकी धारा में भी दिखाई देता है.

इसमें दो राय नहीं कि देश में उच्च शिक्षा में सकल दाखिला दर में सुधार की भारी आवश्यकता है और यही लक्ष्य निश्चित रूप से सर्वोपरि है. सरकार और नई शिक्षा नीति का भी यही सबसे अहम लक्ष्य है. लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है

सर्वेक्षण का तरीका

ऐसे हुई विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्व के 135 संस्थानों सहित 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं. इनमें देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी के चयन में *इंडिया टुडे* ग्रुप की सालाना रैंकिंग देश के शैक्षणिक कैलेंडर में विशेष अहमियत रखती है. समृद्ध जानकारी और व्यापक डेटा के आधार पर की जाने वाली यह रैंकिंग न केवल विद्यार्थियों के लिए अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान बनाती है, बल्कि नियोक्ताओं, अभिभावकों, पूर्व छात्रों, नीति निर्माताओं और बहुत से अन्य संबंधित लोगों और महकमों को विश्वविद्यालय की शिक्षा का विस्तृत हालचाल भी प्रदान करती है.

इंडिया टुडे के नॉलेज पार्टनर एमडीआरए के सर्वेक्षण के तरीकों ने कई मील के पत्थर गाड़े हैं. वस्तुनिष्ठ रैंकिंग के दौरान, विश्वविद्यालयों की सबसे व्यापक और संतुलित तुलना प्रदान करने के लिए एमडीआरए ने बहुत सावधानी से 120 से अधिक मापदंड तय किए हैं. कामकाज के संकेतकों को पांच मानदंडों में शामिल किया गया है. जैसे, 'प्रतिष्ठा और संचालन', 'अकादमिक और शोध उत्कृष्टता', 'बुनियादी ढांचा और रहने का अनुभव', 'व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास' तथा 'करियर प्रगति और प्लेसमेंट.' इसके अलावा, कोविड महामारी के लिए विश्वविद्यालयों की तैयारियों का भी आकलन किया गया. रैंकिंग, विश्वविद्यालयों से उपलब्ध कराए गए चालू वर्ष के आंकड़ों के आधार पर की गई.

इस पूरी प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं:

डेटाबेस तैयार करना: 750 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची तैयार की गई थी जो मापदंडों को पूरा करते थे. मूल्यांकन के लिए चार धाराओं—सामान्य, चिकित्सा, तकनीकी और लॉ के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर विचार किया गया. रैंकिंग के लिए केवल ऐसे विश्वविद्यालयों पर विचार किया गया, जो पूर्णकालिक, इन-क्लास कोर्स की पेशकश करते हैं और 2020 के अंत तक जहां से कम से कम तीन बैच पास होकर निकल चुके हैं.

विशेषज्ञ राय के साथ वेटेज का निर्धारण: अपने क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों से संबंधित श्रेणियों के विश्वविद्यालयों के लिए प्रासंगिक मानदंडों और उप-मानदंडों को तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया गया था. संकेतकों का निर्धारण बहुत सावधानी से किया गया था, और उनके सापेक्ष भार तय किए गए.

वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण: रैंकिंग के लिए योग्य पाए गए विश्वविद्यालयों को एक व्यापक वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली भेजी गई. वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली को एमडीआरए और *इंडिया टुडे* की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया गया था. विश्वविद्यालय इस सर्वे में समय रहते भागीदारी दे सकें, इसके बारे में याद दिलाने के लिए कई ई-मेल भेजे गए और टेलीफोन कॉल भी किए गए. 150 से अधिक विश्वविद्यालयों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना डेटा, उनकी पुष्टि करने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ प्रदान किया.

वस्तुनिष्ठ आंकड़े की जांच: विश्वविद्यालयों से वस्तुनिष्ठ आंकड़े प्राप्त होने के बाद, सहायक दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई. इन आंकड़ों का हर संभव माध्यम से सत्यापन किया गया. प्रत्येक विश्वविद्यालय को पांच संकेतकों के तहत वस्तुनिष्ठ अंक दिया गया.

अवधारणात्मक सर्वेक्षण: 30 शहरों में 369 विद्वानों और जानकारों (34 वीसी, 87 डायरेक्ट/ डीन/ रजिस्ट्रार, 248 वरिष्ठ संकाय (प्रोफेसरों और विभागाध्यक्षों) के बीच एक अवधारणात्मक सर्वेक्षण किया गया. प्रमुख शहर इस प्रकार हैं:

- उत्तर: दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़
- पश्चिम: मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और इंदौर
- दक्षिण: चेन्नै, बेंगलूरू, हैदराबाद और कोयंबत्तूर
- पूर्व: कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और पटना

विद्वानों से उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय और जोनल रैंकिंग ली गई और उन्हें क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत वेटेज दिया गया. उन्होंने विश्वविद्यालयों को पांच प्रमुख मापदंडों में हरेक के लिए 10-पॉइंट रेटिंग स्केल पर भी आकलन किया.

अंतिम स्कोर: वस्तुनिष्ठ स्कोर की गणना करते समय तय किया गया कि रेटिंग केवल समग्र आंकड़े के आधार पर न हो और इसीलिए डेटा को नॉर्मलाइज किया गया. वस्तुनिष्ठ और अवधारणात्मक सर्वेक्षणों से प्राप्त कुल अंकों को 50:50 के अनुपात में जोड़कर संयुक्त प्राप्तांक निकाला गया.

शोधकर्ताओं, सांख्यिकीविदों, विश्लेषकों और सर्वेक्षणकर्ताओं की एक बड़ी टीम ने दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक इस पर काम किया. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में एमडीआरए कोर टीम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर अबनीश झा, सीनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव राजन चौहान, एसिस्टेंट रिसर्च एग्जीक्यूटिव दक्षिता ड्रोलिया और एग्जीक्यूटिव-ईडीपी मनवीर सिंह शामिल थे.

इस साल की रैंकिंग की सबसे खास और मार्के का नतीजा यह है कि पढ़ाई और सुविधाओं की गुणवत्ता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. अगर सामान्य कटगरी में टॉप 10 सरकारी में 4 संस्थान उत्तर में हैं तो टॉप 10 निजी संस्थानों में दक्षिण का दबदबा है

कि सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों का बोझ कम करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों को तेजी से बढ़ती छात्र आबादी की जरूरतें पूरी करनी होंगी. लिहाजा, देश के हित में यही है कि सभी संबंधित लोगों और महकमों को निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को न केवल सस्ता बनाने बल्कि उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी संगठित प्रयास करने होंगे. *इंडिया टुडे* ग्रुप की विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की भी यही कुंजी है. ■

चंद्रदीप कुमार

समावेशी शिक्षा
जेएनयू कन्वेंशन सेंटर के बाहर कुलपति जगदीश कुमार

नं. 1 **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय**
नई दिल्ली

लक्षित पढ़ाई-लिखाई

एम. जगदीश कुमार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में, हम नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तीन महत्वपूर्ण घटकों–बहु-विषयक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तथा भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दे रहे हैं. एनईपी के लिए हम पहले ही एक शीर्ष समिति का गठन कर चुके हैं. एनईपी जारी होने से पहले ही, जेएनयू में बहु-विषयक शिक्षा चल रही है. विश्वविद्यालय का उद्देश्य विभिन्न विषयों के जानकारों के बीच एक संवाद माध्यम स्थापित करना है. इससे अधिक रचनात्मकता और नयापन आता है. यही बड़ी वजह है कि देश के सर्वश्रेष्ठ छात्र इस विश्वविद्यालय में आते हैं. उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में एमए करने वाला छात्र स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज या भाषाओं में दूसरा कोर्स भी कर सकता है.

हाल के दिनों में, जब हमने इंजीनियरिंग स्कूल शुरू किया तो हमने इसे बहु-विषयक बनाया. हमारे छात्रों को दो डिग्री मिलती हैं—एक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और दूसरी सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री. बहुत से छात्र, जिन्हें आसानी से किसी भी आइआइटी में प्रवेश मिल सकता था, हमारे पाठ्यक्रमों के बहु-विषयक स्वरूप के कारण यहां आ रहे हैं. मकसद हमारे इंजीनियरों को सामाजिक रूप से अधिक जागरूक बनाना है.

हमने आयुर्वेद जीव विज्ञान में पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (इंटीग्रेटेड प्रोग्राम) भी शुरू किया है. यह पूरी तरह से अंतर-विषयक पाठ्यक्रम है. आणविक औषधि (मॉलीक्यूलर मेडिसिन), जीव विज्ञान (लाइफ साइंसेज), जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर और संस्कृत के प्रोफेसरों के साथ मिलकर इस पाठ्यक्रम को एक साथ चलाते हैं. वे आधुनिक जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं. एनईपी के लागू हो जाने के बाद, हम ऐसे कई और पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं.

लंबे समय तक, इस विश्वविद्यालय में संस्कृति बुनियादी शोध पर ध्यान केंद्रित करने की थी. पिछले पांच वर्षों में, हम इसे बदलने में सक्षम हुए हैं. बुनियादी शोध अच्छा है, लेकिन हमें इसे उपयोग में

टॉप 10 सामान्य यूनिवर्सिटी (सरकारी)

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	रैंक 2020	रैंक 2019	रैंक 2018
1	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	1	1	1
2	दिल्ली यूनिवर्सिटी, *दिल्ली*	एनपी	एनपी	2
3	हैदराबाद यूनिवर्सिटी, *हैदराबाद*	2	2	3
4	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	3	3	5
5	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	5	5	एनपी
6	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, *नई दिल्ली*	8	7	7
7	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, *कोट्टायम*	6	6	11
8	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, *मुंबई*	9	एनपी	एनपी
9	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, *समस्तीपुर, बिहार*	10	एनपी	एनपी
10	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *कोच्ची*	7	9	9

एनपीः हिस्सा नहीं लिया

मेरा विश्वविद्यालय

“बहु-विषयक पाठ्यक्रम जेएनयू को देश में सबसे अलग तरह की यूनिवर्सिटी बना देता है. किसी भी पृष्ठभूमि का कोई छात्र अपनी पसंद का कोई भी कोर्स चुन लेने को आजाद है. मसलन, स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च में शोध कर रहा कोई छात्र चाहे तो मानव-विज्ञान की कक्षा में भी बैठ सकता है”

—रोहित कुमार
पीएचडी छात्र, स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, जेएनयू

गुरु वाणी

“हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब कम रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों का हाथ थामें और ज्ञान का एक संतुलित तंत्र स्थापित करें”

—एम. जगदीश कुमार,
कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

आने वाले शोध में बदलने की जरूरत है. हमें अपने शोध को किसी प्रकार के प्रयोग में ढालने की आवश्यकता है. जब हम अनुसंधान और नवाचार के बारे में बात करते हैं, तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ बात होगी. लेकिन सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के शिक्षक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोगियों के साथ काम कर सकते हैं और संयुक्त रूप से स्टार्ट-अप कंपनियों की स्थापना कर सकते हैं.

मसलन, कोई यह अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल विकसित करना चाहता है कि कोविड कैसे फैलता है, तो केवल एक आणविक जीव-विज्ञानी अकेला ऐसा मॉडल विकसित नहीं कर पाएगा. कोविड के प्रसार में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का सीधा संबंध है. विभिन्न स्थानीय समूहों में लॉकडाउन और कोविड के उचित व्यवहार जैसी सरकार की नीतिगत कार्यक्रमों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया रहती है. ये इनपुट, जो उस मॉडल के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं, समाज विज्ञानियों से ही मिल सकते हैं.

यही कारण है कि हम अंतर-विषयक अनुसंधान की वकालत करते रहे हैं. मसलन, जब हमने आपदा अनुसंधान के लिए विशेष

केंद्र या पूर्वोत्तर भारत के अध्ययन के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए, तो हमने यह आश्वस्त किया कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक एक साथ काम करें.

हम अपनी खुद की स्टार्ट-अप कंपनियां स्थापित करके आंतरिक संसाधन पैदा करने पर भी विशेष जोर दे रहे हैं. यह विश्वविद्यालय की संस्कृति से पूरी तरह से अलहदा और नई चीज है. प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए केवल सरकार पर निर्भर रहकर, हम अनुसंधान के बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार नहीं कर पाएंगे. सरकार की अपनी सीमाएं हैं. बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, और उपलब्ध धनराशि सीमित है.

पिछले पांच वर्षों में, हमारी शोध निधि चार गुना बढ़ गई है. हमने अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में संशोधन किया है. हम अपनी फैकल्टी को अपनी स्टार्ट-अप कंपनियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. हमारे कैंपस में पहले से ही तीन कंपनियां काम कर रही हैं और पांच और को मंजूरी दी जाने वाली है. हमने एक अत्याधुनिक इमारत बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जहां से अगले पांच वर्षों में लगभग 100 स्टार्ट-अप कंपनियां काम कर सकती हैं.

एनईपी के लिए शीर्ष समिति भारतीय भाषाओं में कुछ पाठ्यक्रमों की संभावना देख रही है. कुछ कोर्सेज में भारतीय भाषाओं में कुछ प्रोग्राम शुरू करना आसान है, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में. लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात आती है, तब भी हमारे शिक्षाविदों के बीच काफी विरोध दिखता है. उन्हें लगता है कि छात्र अलग-अलग जगहों से आते हैं और अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं. इसलिए, उन्हें किसी एक भारतीय भाषा में शिक्षा देना मुश्किल होगा. लेकिन हमारे अधिकांश छात्रों को अंतत: स्थानीय वातावरण में काम करना होता है, जो देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं. उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में किसी सिविल इंजीनियर को राज्य के निर्माण व्यवसाय में योगदान देना होता है और उन श्रमिकों और ठेकेदारों के साथ काम करना होगा जो केवल तमिल बोलते हैं. अपने जीवन के अधिकांश समय में उसके मन में जो विचार आएंगे, वे केवल तमिल में ही होंगे. इसलिए, वह अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा तमिल में प्राप्त करता है, तो मुझे इसमें समस्या नहीं दिखती.

साथ ही, हम यह नहीं कह सकते कि हम केवल हिंदी में एक कोर्स की पेशकश करेंगे क्योंकि हो सकता है कि हमारा कोई छात्र केरल से हो, जिसे हिंदी बिल्कुल न आती हो. जेएनयू में, हम यह मानते हैं कि भले ही हम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करें, फिर भी संचार के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सीखने पर भी जोर कम नहीं होना चाहिए. चुनौतियां हैं लेकिन हमें समाधान खोजने की जरूरत है. क्या हमारे पास ऐसे उपकरण हो सकते हैं जो क्लास में रियल-टाइम अनुवाद कर सकते हैं? शिक्षक अंग्रेजी में बोल रहे होंगे, लेकिन छात्र उसे उसी वक्त अपनी मातृभाषा में सुन सकेंगे.

अब हम एक अन्य बदलाव के मुहाने पर हैं, जिसे कोविड महामारी ने बढ़ावा दिया है. डिजिटल शिक्षा आज चर्चा का

➤ पांच सरकारी यूनिवर्सिटी, जहां सबसे अधिक स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स हैं

रैंक	यूनिवर्सिटी	पीजी कोर्स की संख्या
1	लखनऊ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	128
2	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	126
3	आंध्र यूनिवर्सिटी, *विशाखापत्तनम*	119
4	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	87
5	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, *नई दिल्ली*	80

➤ पांच सरकारी यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पेटेंट के आवेदन किए गए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, *गुंटूर*	112
2	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, *नई दिल्ली*	79
3	मिजोरम यूनिवर्सिटी, *आइजोल*	48
4	लखनऊ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	40
5	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, *केरल*	38

➤ पांच सरकारी यूनिवर्सिटी, जहां फैकल्टी-छात्र अनुपात सबसे अच्छा

रैंक	यूनिवर्सिटी	अनुपात
1	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, *हैदराबाद*	1.32
2	श्री कोंडा लक्ष्मी तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, मुलुगु, *सिद्दपेट*	1.06
3	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. पुसा, *समस्तीपुर*	0.59
4	डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर ऐंड फॉरेस्ट्री, *सोलन*	0.45
5	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	0.28

नोटः अनुपात में सिर्फ पीजी छात्रों की ही गणना; कुल फैकल्टी= स्थायी फैकल्टी+विजिटिंग फैकल्टी+ कॉन्ट्रैक्ट पर/अस्थायी फैकल्टी

➤ पांच सरकारी यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पेटेंट मंजूर हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	24
2	लखनऊ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	22
3	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	15
4	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	10
5	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, *नई दिल्ली*	10

➤ पांच सरकारी यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पीएचडी की गई

रैंक	यूनिवर्सिटी	पीएचडी की संख्या
1	भारतियर यूनिवर्सिटी, *कोयंबत्तूर*	3,567
2	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	2,453
3	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	2,142
4	दिल्ली यूनिवर्सिटी, *दिल्ली*	1,738
5	केरल यूनिवर्सिटी, *तिरुवनंतपुरम*	1,649

मुख्य विषय बन गई है, जेएनयू पहले से ही उस दिशा में अग्रणी रहा है. हालांकि, हमारा उद्देश्य इसे पारंपरिक प्रारूप के विकल्प के रूप में उपयोग करना नहीं था, बल्कि हमने इसे सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाया था. मसलन, लगभग चार साल पहले, हमने बाहरी परीक्षकों से पीएचडी उम्मीदवारों का साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की शुरुआत की थी. इसने न केवल आने-जाने और परीक्षकों को ठहराने के बहुत सारे खर्च बचे—हमारे यहां हर साल लगभग 600 पीएचडी होती है—बल्कि हम दुनियाभर के विशेषज्ञों तक पहुंचने में सक्षम रहे. इससे न केवल परीक्षकों का पूल बढ़ा है, बल्कि उसमें विविधता भी आई है और अंतत: हमारे शोध की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

हालांकि डिजिटल शिक्षा में पीपीटी को पूरी तरह ब्लैकबोर्ड की जगह लेने वाला नहीं समझा जाना चाहिए, फिर भी यह निश्चित रूप से हमारे लिए छात्रों के साथ संवाद करने के विभिन्न तरीकों का पता लगाने और पढ़ाई की प्रक्रिया में उन्हें सहभागी बनाने के एक अवसर

➤ पांच सरकारी यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पेटेंट प्रकाशित* हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, *नई दिल्ली*	79
2	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, *गुंटूर*	30
3	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	28
4	लखनऊ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	28
5	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	21

*प्रकाशित पेटेंट से शोधकर्ता को उस शोध का अधिकार हासिल नहीं हो जाता, बल्कि उससे पता चलता है कि भविष्य में शायद उसे पेटेंट हासिल हो जाए

के रूप में आया है. वास्तव में, यह जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बड़ा सहयोगी भी हो सकता है. बेशक, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमने विश्वविद्यालयों के बीच शीर्ष रैंक हासिल किया है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम ज्ञान की व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें.

देश में अधिकांश छात्र उन विश्वविद्यालयों में हैं जो शीर्ष 10 या शीर्ष 20 में नहीं हैं. बहुत थोड़े से छात्रों को जेएनयू या आइआइटी जैसे संस्थानों में दाखिला मिलता है. केवल अपने रैंक में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए, जेएनयू जैसे संस्थानों को छोटे संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि वे भी विकसित हो सकें. उदाहरण के लिए, जेएनयू किसी प्रोजेक्ट के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) में आवेदन कर रहा है, तो उन्हें हमसे पूछना चाहिए कि क्या जेएनयू का कोई सहयोगी संस्थान है जो उस जगह पर स्थित है जहां इस प्रोजेक्ट कार्य का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है. हमारे लगभग 60 प्रतिशत विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. इस तरह के सहयोग न केवल इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के लिए अवसर प्रदान करेंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे बल्कि शोध की गुणवत्ता में भी वृद्धि करेंगे. जेएनयू सहित कई शीर्ष विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से संयुक्त डिग्री प्रदान करते हैं. अब, हम विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम चला सकते हैं. इस तरह के सहयोग को सुगम बनाने में डिजिटल मोड बड़ी भूमिका निभा सकता है. जेएनयू में पीएचडी के बहुत से छात्र ऐसे विश्वविद्यालयों से आते हैं. जब तक शिक्षा के तंत्र में निचले हिस्से को मजबूत नहीं किया जाता, हम अच्छे छात्रों की उम्मीद नहीं कर सकते.

—कौशिक डेका से बातचीत पर आधारित

नं. 2 दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

वक्त के साथ पुरजोर कदमताल

प्रो. पी.सी. जोशी

वर्ष 2020 दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कई वजहों से चुनौतीपूर्ण था. इसकी कई वजहें तो सोच से परे थीं और विश्वविद्यालय का उन पर कोई काबू नहीं था. लेकिन कोविड महामारी के सबसे मुश्किल दौर में भी विश्वविद्यालय ने अपने तय विजन और मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास किया. पिछले एक साल के दौरान खासकर छात्र केंद्रित गतिविधियों पर ध्यान रहा है, जैसे, ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन परीक्षा और आकलन, डिजिटल प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री, दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन बनाने के साथ ही प्लेसमेंट और इंटर्नशिप.

महामारी और लॉकडाउन ने मिड-सेमेस्टर के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय का कामकाज लगभग ठप कर दिया. पारंपरिक क्लासरूम की जगह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने ले ली. छात्रों को पाठ्य सामग्री ऑनलाइन मुहैया कराई गई. इंटरनल एसेसमेंट और परीक्षाएं पहली बार ऑनलाइन कराई गईं. किताब खोलकर परीक्षा (ओबीई) पहली बार कराना—और वह भी इतने ज्यादा छात्रों और कोर्स के लिए—न केवल बहुत मुश्किल था बल्कि यह एक तरह का प्रयोग ही था (गौरतलब है कि अगस्त 2020 में पहली ओबीई में 2,90,000 छात्रों ने हिस्सा लिया और दिसंबर 2020 में 1,70,000 ने).

छात्रों ने अपने घर के सहज माहौल में परीक्षा दी; शिक्षकों ने उनका मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया. अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा पास करने के बाद 'डिजिटल प्रोविजनल सर्टिफिकेट' दिए गए ताकि वे विदेशी विश्वविद्यालयों समेत उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकें. छात्रों को पहली बार 'डिजिटल डिग्री' भी दी गई.

अकादमिक वर्ष 2020-21 में विभिन्न पाठ्यक्रमों और

चंद्रदीप कुमार

गुरु वाणी

"दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोविड चुनौती के अनुरूप ढलने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है"

—प्रो. पी.सी. जोशी
प्रो वाइस-चांसलर, दिल्ली विश्वविद्यालय

शक्ति स्तंभ
विश्वविद्यालय परिसर में प्रो. पी.सी. जोशी

मेरा विश्वविद्यालय

"दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई में व्यावहारिक नजरिए पर भी जोर दिया जाता है, जो हमें दुनियादारी में काम आता है और अपने करियर में मदद करता है. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से पढ़ने का मौका मिला"

—श्रेयस मेहरा,
अर्थशास्त्र में एमए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्नातक तथा स्नातकोत्तर समेत सभी डिग्रियों के लिए ऑनलाइन दाखिले किए गए और विश्वविद्यालय ने—अपने संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ—पेश आई तमाम तरह की समस्याओं का समाधान निकाला. सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने इंटर्नशाला (इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म) के साथ कोलैबोरेट किया. विश्वविद्यालय के 6,000 से ज्यादा छात्रों को डब्ल्यूएफएच (वर्क फ्रॉम होम) इंटर्नशिप और अन्य 4,000 को 'चलो इंडिया' कार्यक्रम के तहत इंटर्नशिप के अवसर मिले.

विश्वविद्यालय ने अपने ई-लर्निंग मॉडल को काफी विस्तार दिया और वनडीयू फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत विश्वविद्यालय के सभी ई-लर्निंग रिसोर्सेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया गया. वनडीयू सभी विभागों, कॉलेजों, सेंटरों और विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देगा. इसका उद्देश्य पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा को सबक लिए सुलभ बनाना, इसकी सर्वश्रेष्ठ परिपाटियां तैयार करना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है.

विश्वविद्यालय में शोध पर लगातार जोर बढ़ रहा है. इसने विश्वविद्यालय के लिए अधिक एच-इंडेक्स के मामले में ठोस नतीजे दिए हैं, जो 197 से बढ़कर जून 2020 में 218 हो गया.

पिछले एक साल में स्कोपस में शामिल जर्नलों में शोध-पत्रों की संख्या में करीब 5 फीसद का इजाफा हुआ है. विश्वविद्यालय में एक मल्टीडिस्पलिनरी कोर्स बॉयोफिजिक्स में एमएससी शुरु किया गया है. इसमें जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी सभी का मिश्रण है

यह आंकड़ा देश के विश्वविद्यालयों में सबसे ऊपरी कतार में शामिल है. इसके अलावा, पिछले एक साल के दौरान स्कोपस में शामिल जर्नलों में शोधपत्रों की संख्या में करीब पांच फीसद इजाफा हुआ है. यह भी ऐसे संकट काल में किसी उपलब्धि से कम नहीं है.

यह विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन और शोध को बढ़ावा देता रहा है. हाल ही में एक मल्टीडिसिप्लिनरी पोस्टग्रेजुएट कोर्स एमएससी बायोफिजिक्स (2021-22) शुरू किया गया है. यह जीवविज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी का मिश्रण है. विश्वविद्यालय ने एनवायरनमेंटल साइंस प्रोग्राम में बीएससी (ऑनर्स) का नया कोर्स भी शुरू किया है, जो आज जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के मामले में खास अहमियत रखता है.

विश्वविद्यालय में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट स्तरों पर पहले ही चॉएस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू कर दिया गया है. सीबीसीएस की पाठ्यचर्या मुख्य पाठ्यक्रम (फाउंडेशनल), वैकल्पिक पाठ्यक्रम (स्पेशलाइजेशन) और मुक्त वैकल्पिक पाठ्यक्रम (स्किल बेस्ड या मल्टीडिसिप्लिनरी) में विभाजित है.

सीबीसीएस 2018-19 से ही अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में लागू है. इस स्तर पर हर कोर्स में एक मल्टीडिसिप्लिनरी तत्व है. मिसाल के तौर पर, बीएससी (ऑनर्स) ऐंथ्रोपोलॉजी में जेनरिक इलेक्टिव के रूप में टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, फूड टेक्नोलॉजी और मेरीन साइंस जैसे विषय हैं. बीएससी बायोमेडिकल साइंस में 'ब्रिजिंग इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐंड बायोटेक्नोलॉजी' और 'इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स ऐंड ड्रग डेवलपमेंट' जैसे पेपर हैं.

दरअसल, विश्वविद्यालय में भविष्य को ध्यान में रखकर तमाम तरह की कोशिश की जा रही है. मसलन, नई शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया गया है. यह समिति विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने के बारे में सुझाव देगी. यह मल्टीडिसिप्लिनरी एप्रोच को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों, भाषाओं की पढ़ाई, नीतिशास्त्र, सामाजिक मूल्य-बोध तथा संस्कृति, पाठ्येतर गतिविधियों और खेलकूद, हुनर विकास तथा शोध समेत समग्र पाठ्यचर्या से जुड़े मुद्दों पर विचार कर रही है. इससे नए दरवाजे खुलेंगे. ■

—शेली आनंद से बातचीत पर आधारित

नं. 1 **एमिटी यूनिवर्सिटी**
नोएडा

पढ़ाई का उम्दा माहौल

प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में विश्वविद्यालयों से उम्मीद की गई है कि वे समग्र तथा बहु-विषयक स्नातक शिक्षा प्रदान करें. बाणभट्ट की *कादंबरी* जैसी प्राचीन साहित्यिक कृतियों में वर्णित भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अनुसार अच्छी शिक्षा में 64 कलाओं की शिक्षा शामिल हैं, जिसमें गायन, चित्रकला, रसायन विज्ञान, गणित, बढ़ईगीरी, बुनकरी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विविध विषयों के साथ-साथ चर्चा तथा वाद-विवाद जैसे व्यावहारिक कौशलों का ज्ञान भी शामिल है.

यहां एमिटी में हमने सावधानी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों को लागू करने की योजना बनाई है कि हम नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाने, पाठ्यक्रम तैयार करने और उसके मूल्यांकन के तरीकों को नया स्वरूप देने और शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था कैसे करें.

पढ़ाई के लिए विषयों में रचनात्मक पुट देने के लिए लचीले पाठ्यक्रम तैयार करने के क्रम में हम पाठ्यक्रमों में दाखिले और उससे बाहर निकलने के कई मौके प्रदान कर रहे हैं. आजीवन सीखते रहने की नई संभावनाएं पैदा करने के लिए हमने अपने स्नातक कार्यक्रमों को नए सिरे से तैयार किया है. इस क्रम में शोध संभावनाओं को जोड़कर चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों पर भी विचार किया जा रहा है.

बहु-विषयक पाठ्यक्रम बनाने के लिए हमने 'तीन विषय पैटर्न' के आधार पर एक न्यूनतम सामान्य पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, ताकि अकादमिक क्रेडिट बैंक तैयार किया जा सके. इसके अलावा सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में लागू होने वाला एकरूप ढांचा भी बनाया है. उदाहरण के लिए, एमिटी लॉ स्कूल बीए, एलएलबी/बीकॉम, एलएलबी/बीबीए, एलएलबी जैसे पंचवर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रमों में पहली और दूसरी दोनों डिग्रियों में ऑनर्स प्रदान करता है. पहली डिग्री के लिए एक प्रमुख विषय के 10 पाठ्यक्रम और दो अनुषंगी विषयों में से प्रत्येक के पांच पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं. दूसरी डिग्री के लिए चार विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है. छात्रों को किसी

टॉप 10 सामान्य यूनिवर्सिटी (प्राइवेट)

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	रैंक 2020	रैंक 2019
1	एमिटी यूनिवर्सिटी, *नोएडा*	1	1
2	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *वेल्लूर*	2	3
3	क्राइस्ट (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *बेंगलूरु*	3	2
4	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *चेन्नै*	5	4
5	एसवीकेएम्स नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मुंबई*	4	एनपी
6	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *गुंटूर*	7	6
7	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, *राजस्थान*	6	5
8	जैन (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *बेंगलूरु*	8	7
9	निरमा यूनिवर्सिटी, *अहमदाबाद*	9	8
10	सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	11	12

एनपीः उपलब्ध नहीं

कतार में आगे
छात्रों के साथ एमिटी की कुलपति प्रो. बलविंदर शुक्ला

राजवंत रावत

गुरु वाणी

“हम विभिन्न विषयों में रचनात्मक का पुट देकर कोर्स में दखिले और उससे बाहर निकलने के कई विकल्प मुहैया कराते हैं”

—प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला
कुलपति, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा

भी शाखा में ऑनर्स/विशेषज्ञता उपाधि प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय समूह में आठ अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरे करने होते हैं. अनिवार्य पाठ्यक्रमों के अलावा क्लिनिकल पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप भी प्रदान की जाती हैं.

विश्वविद्यालय सभी संकाय सदस्यों, शोध छात्रों और अन्य छात्रों को उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल प्रदान करता है, ताकि सामाजिक रूप से उपयोगी नवाचारों के विकास और वैश्विक पहुंच के साथ स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा मिले. अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है. विश्वविद्यालय ने सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है, जो विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए पारिस्थितिक तंत्र तैयार करेगा और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं के साथ नेटवर्क की स्थापना का मंच प्रदान करेगा. कैंसर जीव विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर्बल और प्राकृतिक उत्पाद, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अपशिष्ट प्रबंधन

➤ पांच यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पेटेंट प्रकाशित हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, *मोहाली*	597
2	एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, *नोएडा*	314
3	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *चेन्नै*	263
4	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट साइंसेज, *सोलन*	230
5	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *वेल्लूर*	208

➤ पांच यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पीएचडी प्रदान किए गए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पीएचडी की संख्या
1	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *वेल्लूर*	871
2	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, *राजस्थान*	827
3	महर्षि मार्कंडेश्वर (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), मुलाना, *अंबाला*	538
4	एमिटी यूनिवर्सिटी, *नोएडा*	505
5	श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, *मध्य प्रदेश*	464

➤ पांच यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पेटेंट दाखिल किए गए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, *मोहाली*	1,079
2	एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, *नोएडा*	519
3	चितकारा यूनिवर्सिटी, *पटियाला*	483
4	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट साइंसेज, *सोलन*	358
5	गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, *ग्रेटर नोएडा*	202

➤ पांच यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक पेटेंट मंजूर हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	81
2	एमिटी यूनिवर्सिटी, *नोएडा*	76
3	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, *मोहाली*	73
4	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *गुंटूर*	68
5	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट साइंसेज, *सोलन*	38

➤ पांच यूनिवर्सिटी, जहां सबसे अधिक पीजी कोर्स है

रैंक	यूनिवर्सिटी	पीजी कोर्स की संख्या
1	एमिटी यूनिवर्सिटी, *नोएडा*	129
2	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *चेन्नै*	128
3	पारुल यूनिवर्सिटी, *वडोदरा*	66
4	क्राइस्ट (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *बेंगलूरु*	62
5	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, *राजस्थान*	59

जैसे अनुसंधान के 50 से अधिक क्षेत्रों में अनुसंधान समूह बनाए गए हैं. हमने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबंद्ध क्षेत्रों में 1,530 से अधिक पेटेंट दायर किए हैं.

महामारी के कारण पढ़ाई-लिखाई प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. हमारी घरेलू आइटी टीम और संकाय सदस्यों ने मिलकर युद्धस्तर पर काम किया, ताकि छात्रों को घर की सुरक्षा में रहते हुए पठन-पाठन की व्यवस्था मुहैया हो सके. हम पिछले साल मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने वाले

➤ उभरती यूनिवर्सिटी

संभावना जगाने वाली इन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कुछ न्यूनतम मानदंड पूरी न करने की वजह से नहीं की गई. मसलन, 2020 तक कम से कम तीन बैच निकल चुके हों और नियत समय तक डेटा न मुहैया कराया गया हो

	यूनिवर्सिटी	किस साल यूनिवर्सिटी घोषित
1	सी टी यूनिवर्सिटी, *लुधियाना*	2016
2	डी.वाइ. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, *पुणे*	2017
3	डॉ. विश्वनाथ करण एमआइटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, *पुणे*	2017
4	एरा यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	2016
5	जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी अमरावती, *महाराष्ट्र*	2016
6	जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी, *छिंदवाड़ा*	2016
7	गार्डेन सीटी यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरु*	2016
8	आइआइएलएम यूनिवर्सिटी, *गुरुग्राम*	2018
9	केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, *धारवाड़*	2015
10	केआरईए यूनिवर्सिटी, *चित्तूर*	2018
11	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	2015
12	मेडी-कैप्स यूनिवर्सिटी, *इंदौर*	2015
13	क्वांटम यूनिवर्सिटी, *हरिद्वार*	2017
14	सेज यूनिवर्सिटी, *इंदौर*	2017
15	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर यूनिवर्सिटी, *धारवाड़*	2018
16	श्री बालाजी यूनिवर्सिटी, *पुणे*	2019
17	एसआरएम यूनिवर्सिटी-आंध्र प्रदेश, अमरावती, *गुंटूर*	2017
18	सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	2017
19	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लायड साइंसेज, *इंदौर*	2016
20	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-आंध्र प्रदेश, *गुंटूर*	2017
21	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, *सोनीपत*	2018

➤ पांच यूनिवर्सिटी, जहां फैकल्टी-छात्र अनुपात सबसे बेहतर

रैंक	यूनिवर्सिटी	अनुपात
1	मानव रचना यूनिवर्सिटी, *फरीदाबाद*	1.95
2	मणिपाल यूनिवर्सिटी, *जयपुर*	1.20
3	द नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी, *गुरुग्राम*	1.14
4	मालवांचल यूनिवर्सिटी, *इंदौर*	1.08
5	स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, *मेरठ*	1.01

नोटः अनुपात निकालने में सिर्फ पीजी छात्रों की संख्या ही शामिल की गई. कुल फैकल्टी में स्थायी फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट/अस्थायी फैकल्टी शामिल

मेरा विश्वविद्यालय

"एमिटी ने वर्चुअल पढ़ाई को लजवाब इंटरऐक्टिव और समझने-सीखने में आसान बना दिया है. क्लासरूम की पढ़ाई-लिखाई के साथ कॉर्पोरेट जगत के साथ जुड़ाव भी बेजोड़ है. इससे हम कॉर्पोरेट जगत की कार्यशैली और जरूरतों से वाकिफ हो जाते हैं. यकीनन इसका फायदा हमें अपने करियर में मिलेगा और हमें अपने साथ लेने को तत्पर कॉर्पोरेट जगत के लिए भी यह मुनासिब होगा"

—मन्नत गिल,
तीसरे सेमिस्टर की छात्रा, एमबीए फाइनांस, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा

विश्वविद्यालयों में से एक थे. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म पर आयोजित 15,000 से अधिक ऑनलाइन मेंटर-मेंटी सत्रों के माध्यम से सभी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया. इस तरह हम लगातार हर वह इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि छात्रों को सुविधा हो और उन्हें करियर में मदद मिले. ■

– **शेली आनंद** से बातचीत पर आधारित

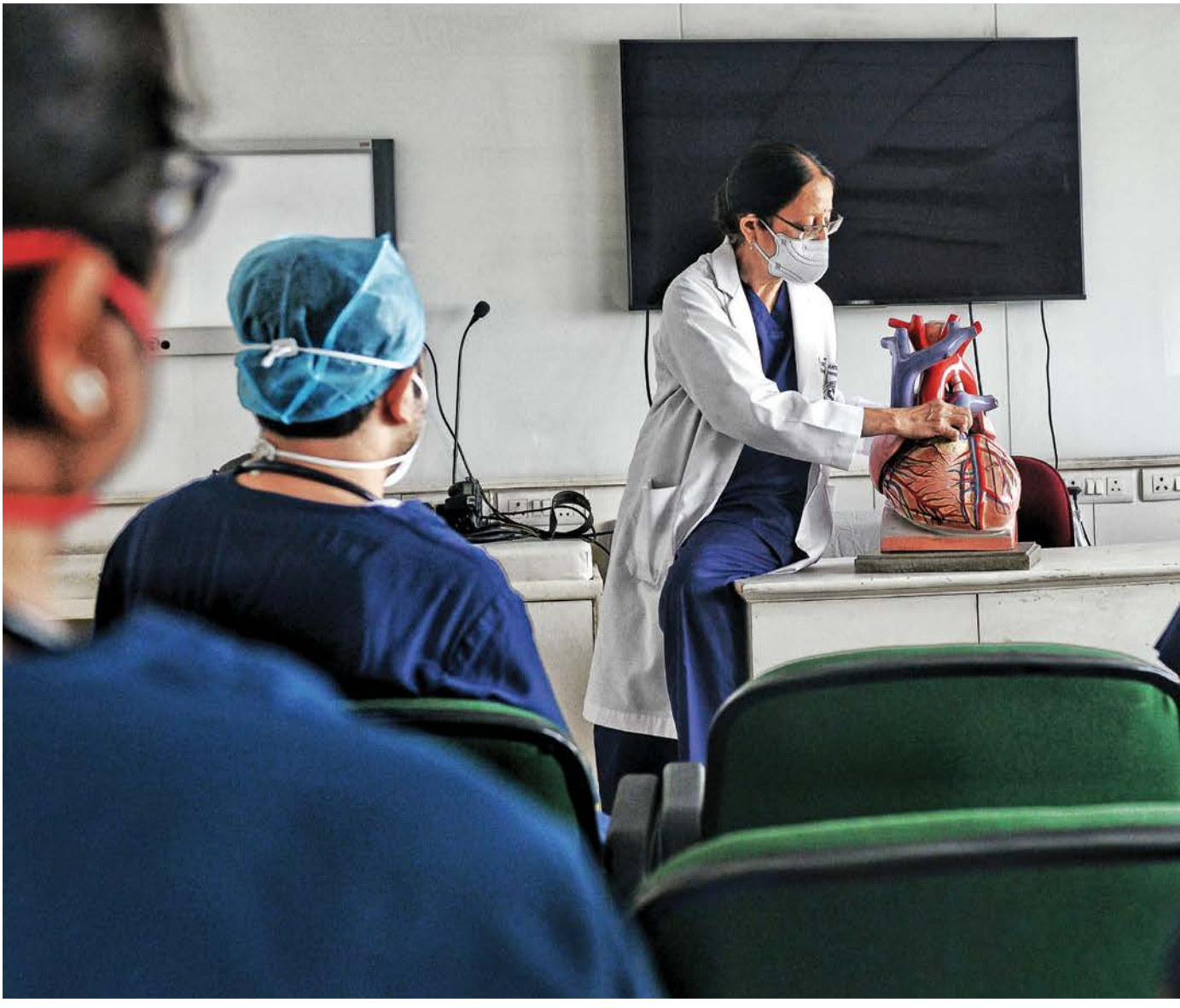

चंद्रदीप कुमार

नं. 1 **भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)**
नई दिल्ली

महामारी की आग में तपकर निखरे

डॉ. अनिता सक्सेना

कोविड ने हर किसी को अस्पताल के माहौल में मुश्किल चुनौतियों से निबटना सिखा दिया. अलबत्ता, डॉक्टर के तौर पर हम कई मुश्किल हालात से मुकाबिल होते हैं, लेकिन कोविड पूरी तरह अलग था और हम लोगों ने जो अब तक देखा है, वह उससे कहीं ज्यादा गंभीर था. जब महामारी शुरू हुई तो हमारे ज्यादातर पीजी स्टुडेंट कोविड वार्ड में काम कर रहे थे, रोज संक्रमण के शिकार रोगियों का इलाज करते थे. शुरू में कई स्टुडेंट अपनी सेहत और सलामती को लेकर फिक्रमंद थे; या उनके परिजन या

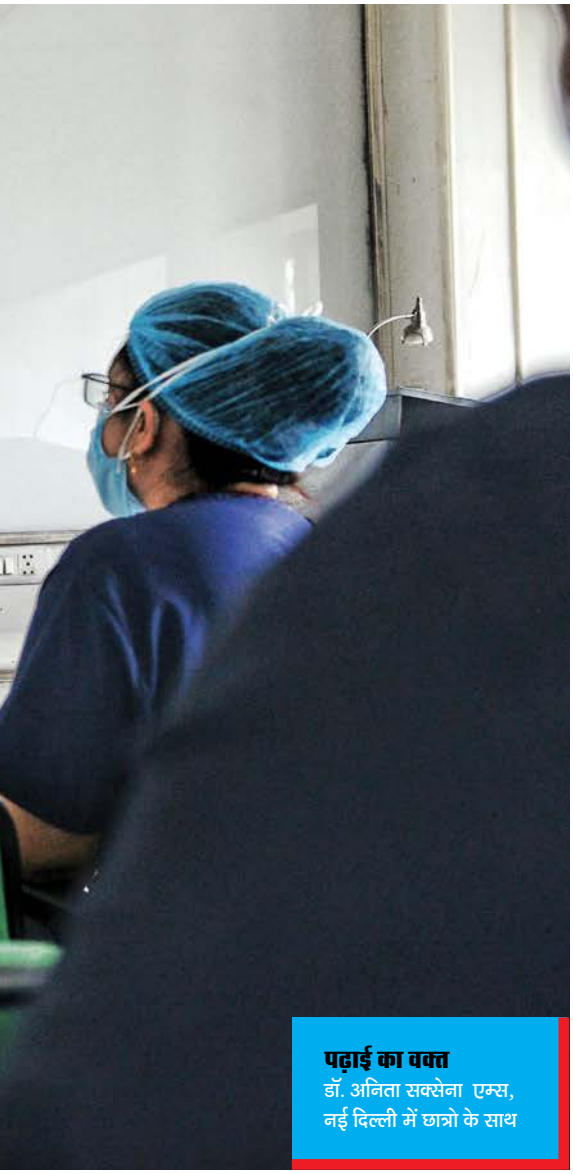

पढ़ाई का वक्त
डॉ. अनिता सक्सेना एम्स, नई दिल्ली में छात्रों के साथ

गुरु वाणी

“पीजी स्टुडेंट को अपने मानसिक तनाव और डॉक्टर के रूप में अपने फर्ज के बीच संतुलन साधना था”

—डॉ. अनिता सक्सेना, डीन ऑफ एकेडमिक्स, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

मेरा विश्वविद्यालय

“शांत बने रहना जरूरी था. यह आसान नहीं था, खासकर जब हमारा अपना अकादमिक वर्ष तबाह हो रहा था क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं मिल पा रहा था. लेकिन हम लोग ने हालात से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का तरीका सीखा’’

—डॉ. साक्षी सचदेव
पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एमडी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

मकान मालिक वार्ड में उनके संक्रमित होने को लेकर आशंकित थे. ऐसे में रेजिडेंट (डॉक्टरों) को अपने मानसिक तनाव और डॉक्टर के रूप में अपने फर्ज की चिंताओं के बीच संतुलन साधना था, और वे इस चुनौती से पार पाने में सफल रहे. उन सबको कोविड प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग और पर्याप्त पीपीई किट दी गई. कार्यक्रम ऐसा बनाया गया कि स्टुडेंट को पीपीई में चार से छह घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पड़े. हमारे यहां की हॉस्पिटल कमिटी नियमित अंतराल पर निरीक्षण करती और कोविड वार्ड के स्टुडेंट को संक्रामक रोग से सुरक्षा की ट्रेनिंग देती थी. खुशकिस्मती की बात यह है कि महामारी के दौरान एम्स में अस्पताल जनित किसी भी संक्रमण का कोई मामला नहीं आया.

पीजी स्टुडेंट अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित हो गए, क्योंकि आने वाले ज्यादातर मरीज कोविड संक्रमण के शिकार ही थे, लिहाजा, हम सबने ऑनलाइन तरीका अपनाना सीख लिया और सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक, दोनों तरह का प्रशिक्षण ऑनलाइन देना शुरू कर दिया. पीजी स्टुडेंट के लिए नियमित अंतराल पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप आयोजित किए गए, और जहां तक संभव हो सका, अंतिम वर्ष के स्टुडेंट को व्यावहारिक अनुभव दिलाया गया, जिनमें सर्जरी शामिल थी.

मेडिकल साइंस के लिए डिजिटल लर्निंग बहुत बड़ा बदलाव है. इसके कुछ पहलुओं के बारे में अब भी ऑफलाइन ही पढ़ाने की जरूरत है. दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही हम अपने पीजी अंतिम वर्ष के स्टुडेंट के व्यावहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यह तीन साल का पाठ्यक्रम है. यह भी एक चुनौती है कि हमारे स्टुडेंट इतने कम समय में जरूरी व्यावहारिक जानकारी हासिल कर लें.

पीजी स्टुडेंट अस्पताल के असली अग्रिम मोर्चे के योद्धा थे, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए, कम है. शिक्षक कंसल्टेंट थे, और हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आ-जा रहे थे. स्टुडेंट ही मरीज के पास लगातार मौजूद रहते थे. लगभग सारे पीजी स्टुडेंट कोविड केयर यूनिट में काम कर रहे थे. उनमें से कुछ को कोविड मरीज की देखभाल का प्रशिक्षण देना पड़ा क्योंकि वे दूसरी विधा के स्टुडेंट थे. उनके लिए अस्पताल के कोविड क्षेत्र में जगह-जगह एसओपी लटकाए गए थे, जिसमें डायबिटीज वाले कोविड रोगियों की देखभाल का तरीका शामिल था. इन स्टुडेंट ने खुद को जोखिम में डालकर कठिन परिस्थितियों में गहन चिकित्सीय देखभाल के नए तरीकों के बारे में सीखा.

—सोनाली अचार्जी से बातचीत पर आधारित

देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी

टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	रैंक 2020	रैंक 2019	रैंक 2018
1	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), *नई दिल्ली*	1	1	1
2	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *पुदुच्चेरी*	2	2	एनपी*
3	किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	3	3	एनपी
4	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरोसांइसेज (निमहांस), *बेंगलूरु*	एनपी	एनपी	एनपी
5	पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, *रोहतक*	4	4	2
6	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *जोधपुर*	एनपी	एनपी	एनपी
7	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *भुवनेश्वर*	एनपी	एनपी	एनपी
8	श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	5	5	3
9	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ऐंड बायलियरी साइंसेज, *नई दिल्ली*	एनपी	एनपी	एनपी
10	जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *मैसूर*	6	7	एनपी

*एनपी: हिस्सा नहीं लिया

5 मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पिछले तीन साल में सबसे अधिक सुपरस्पेशिएलिटी छात्र पास हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	कुल संख्या
1	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *नई दिल्ली*	298
2	किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	111
3	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरोसांइसेज (निमहांस), *बेंगलूरु*	100
4	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *पुदुच्चेरी*	82
5	श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	81

5 मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां छात्र (एमडी/एमएस) सबसे अधिक संख्या में ओपीडी मरीजों को देखते हैं

रैंक	यूनिवर्सिटी	मरीजों की औसत संख्या
1	किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	4,731
2	पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, *रोहतक*	2,500
3	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *नई दिल्ली*	2,000
3	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *पुदुच्चेरी*	2,000
5	एनआइटीटीइ (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मंगलूरु*	1,750

नोटः विभिन्न ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों को देखने वाले अंतिम वर्ष (एमएस/एमडी) के छात्रों की औसत संख्या

5 मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां सबसे कम ट्यूशन फीस (एमएस/एमडी)

रैंक	यूनिवर्सिटी	ट्यूशन फीस (रु.)
1	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *नई दिल्ली*	702
1	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *जोधपुर*	702
1	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *भुवनेश्वर*	702
4	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *पुदुच्चेरी*	11,430
5	पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, *रोहतक*	64,000

5 मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां छात्र-फैकल्टी अनुपात बेहतरीन

अनुपात के मुताबिक रैंक	यूनिवर्सिटी	अनुपात
1	सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, *गंगतोक*	4.56
2	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ऐंड बायलियरी साइंसेज, *नई दिल्ली*	2.60
3	एनआइटीटीइ (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मंगलूरु*	2.32
4	जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *मैसूरु*	2.26
5	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरोसांइसेज (निमहांस), *बेंगलूरु*	2.19

नोटः अनुपात की गणना में एमएस/एमडी छात्रों को ही शामिल किया गया; कुल फैकल्टी=स्थायी फैकल्टी+विजिटिंग फैकल्टी+कॉन्ट्रैक्ट/अस्थायी फैकल्टी

नं. 1 **श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च,** *(डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी)*

वक्त के साथ हर नब्ज पर हाथ

डॉ. पी.वी. विजयराघवन

तमिलनाडु के एक प्रमुख उद्योगपति दूरदर्शी तिरु एन.पी.वी. रामासामी उडयार ने श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च (एसआरआइएचईआर) के विशाल और भव्य परिसर की नींव रखी, जिसे उसके पहले श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था. 1985 में 100 एमबीबीएस छात्रों के दाखिले के साथ शुरू हुआ श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अब चेन्नै के पोरूर में स्थित 150 एकड़ के एक विशाल और हरे-भरे परिसर के रूप में विकसित हो गया है. इसके शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और शोध-अनुसंधान वगैरह को समर्पित 12 संकाय सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं.

चिकित्सा संकाय इसकी मूल इकाई है, जिसके चारों ओर अन्य सभी संकाय कार्य करते हैं. जहां तक स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों के लिए शिक्षा की बात है, दंत चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेज, प्रबंधन अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नैदानिक अनुसंधान

गुरु-शिष्य
डॉ. विजयराघवन श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ

जैसन जी

गुरु वाणी

“प्रैक्टिकल सेशन के लिए सिमुलेशन और कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग की शुरुआत ने कोविड के कारण पैदा व्यवधानों को दूर करने में मदद की”

—डॉ. पी.वी. विजयराघवन

श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एडुकेशन ऐंड रिसर्च (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी)

और खेल तथा व्यायाम विज्ञान संकाय के अंतर्गत 150 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसा होगा, जो यहां उपलब्ध न हों.

हाल ही में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संकाय भी जोड़े गए हैं. एक सुसज्जित और वातानुकूलित केंद्रीय पुस्तकालय, लगभग 400 आइसीटी-सक्षम स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम और नैदानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ विश्वविद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के लिए सीखने का एक आदर्श माहौल प्रदान करता है. श्री रामचंद्र हॉस्पिटल ऐंड मेडिकल सेंटर सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए बड़े पैमाने पर स्थानीय जनता की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है. इससे विभिन्न स्ट्रीम के छात्रों को उपचार का व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है. अस्पताल एनएबीएच से मान्यता प्राप्त है.

अपने अस्तित्व के इन 30 वर्षों में, एसआरआइएचईआर ने उत्कृष्टता के कई मानदंड हासिल किए हैं, जिसमें 2020 के लिए शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) में 28वीं रैंक हासिल करना शामिल है. श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को 13वां, श्री रामचंद्र फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज को सातवां और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी को 26वां स्थान मिला.

कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को बेहाल कर दिया और इस दौरान भारत तथा तमिलनाडु भी कोई अपवाद नहीं थे. कोविड की दूसरी लहर शिक्षा, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन के लिए अधिक विनाशकारी थी. मैं इस महामारी के दौरान अपने कुछ अनुभवों का जिक्र करना चाहूंगा.

एसआरआइएचईआर का श्री रामचंद्र अस्पताल कोविड संक्रमण के संदिग्धों की जांच के लिए नामजद परीक्षण केंद्र था. महामारी के दौरान 24/7 मरीजों की सेवा के लिए एक फीवर क्लिनिक शुरू किया गया था. अस्पताल के एक सर्विस ब्लॉक में हमने कोविड मरीजों की देखभाल के लिए 300 आइसोलेशन बेड और 40 आइसीयू बेड बनाए थे. चिकित्सा केंद्र में गैर-कोविड रोगियों के देखभाल की भी सुविधा प्रदान की जा रही थी.

मेरा विश्वविद्यालय

“ महामारी का दौर सीखने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण और खास समय साबित हुआ. कोविड वार्ड और आइसीयू में अकेले तैनाती ने मुझे साहसी फैसले लेने के लिए बाध्य किया. यकीनन इस वजह से मैं बेहतर इनसान और बेहतर डॉक्टर बन पाई हूं”

—डॉ. स्वर्णा कृष्णमूर्ति

विद्यार्थी एमडी फाइनल ईयर, जनरल मेडिसिन, एसआरआइएचईआर

कोविड-19 ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और व्यक्तिगत संकाय सदस्यों की तरफ से ऑनलाइन शैक्षिक तकनीकों को अपनाने की राह खोली गई. 21वीं सदी के शिक्षार्थी इसके लिए बहुत अधिक तैयार थे. हालांकि सैद्धांतिक जानकारियां वर्चुअल/ऑनलाइन मोड से विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती हैं और उनका आकलन भी ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन चुनौती स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रैक्टिकल के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रदान कराने के क्षेत्र में है. प्रैक्टिकल सेशन की इस बाधा को दूर करने के लिए सिमुलेशन और कंप्यूटर आधारित शिक्षा की शुरुआत की गई. सामान्य नैदानिक प्रक्रियाओं की वीडीयो रिकॉर्डिंग की गई और उसे संस्थान के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (शिक्षण प्रबंधन प्रणाली) में अपलोड किया गया, जिससे विद्यार्थियों को उन्हें देखने और उस पर चर्चा करके सीखने-समझने में मदद मिली.

पेपर केस, वर्चुअल ओआर, ईआर, वार्ड राउंड, क्लिनिको-पैथोलॉजिकल मीट, इंटरैक्टिव सीएमई और वेबिनार के माध्यम से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई गई. कुछ विषयों में विश्वविद्यालय की प्रैक्टिकल परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित की गई थी. प्रैक्टिकल के लिए विद्यार्थियों को छोटे-छोटे बैच में में वास्तविक रोगियों के बीच ले जाया गया. विद्यार्थियों के हर बैच की 8 से 10 कार्य घंटे की पारी होती थी.

हालांकि इस दौरान पोस्टग्रेजुएट (पीजी) प्रशिक्षण काफी हद तक प्रभावित हुआ क्योंकि गैर-कोविड रोगी कम ही आ रहे थे. नैदानिक विषयों में पीजी के विद्यार्थियों और इंटर्न ने कोविड रोगियों के प्रबंधन, फीवर क्लिनिक चलाने और जनता को टीकाकरण के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में बहुत मेहनत की. इस मकसद से संस्था की ओर से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं और घरेलू स्वास्थ्य सेवा सफलतापूर्वक चलाई गई. केस डिसेक्शन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों के बीच उपचार से जुड़े तर्क-वितर्कों और गहन चिंतन पर केंद्रित था. इन्हीं कोशिशों ने हमें दूसरों से दो कदम आगे रखा. ■

–अरविंदन डी.आइ. से बातचीत पर आधारित

नं. 1 **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**
नई दिल्ली

आगे की सोच
प्रो. वी. रामगोपाल राव आइआइटी-दिल्ली के अपने वेंचर क्रिएटारा में विकसित दुपहिया वाहन पर

चंद्रदीप कुमार

नए अनुसंधान का आशियाना

प्रो. वी. रामगोपाल राय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–दिल्ली (आइआइटी–दिल्ली) पारंपरिक तौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाना जाता है. मानविकी की पढ़ाई को मोटे तौर पर सेवा क्षेत्र का माना जाता है. पिछले कुछ बरसों से यह बदल–सा गया है. अब आइआइटी–दिल्ली में हमारे यहां मानविकी विभाग भी है और उसका संकाय भी बढ़ रहा है. मानविकी और इंजीनियरिंग दोनों की पढ़ाई एक साथ होती है और दोनों विभाग मिलकर काम करते हैं. करीब 20 साल पहले, आइआइटी केवल तकनीकी अध्ययन पर केंद्रित थे पर अब ऐसा नहीं है.

बहुविषयी शिक्षा समय की मांग है. हम किसी समस्या का प्रभावशाली समाधान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो बहु–विषयक दृष्टिकोण ही रास्ता है. इसके लिए एक प्रणाली–उन्मुख नजरिया अपनाने की जरूरत है और आइआइटी–दिल्ली इस ओर ध्यान दे रहा है. संस्थान का हर विद्यार्थी उद्यमी बनना चाहता है, लेकिन आप एक स्टार्ट–अप तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपके पास किसी समस्या का पूर्ण समाधान न हो. छात्रों को रोजगार देने वाला बनाने के लिए, उन्हें बहुविषयक शिक्षा दिए जाने की जरूरत है. मसलन, हमारे यहां आइआइटी–दिल्ली में एक स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है. डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, डिपार्टमेंट ऑफ मटीरियल्स साइंस ऐंड

गुरु वाणी

“रोजगार देने वाला बनने के लिए विद्यार्थियों को बहुआयामी शिक्षा की जरूरत है.”

—प्रो. वी.रामगोपाल राव,
निदेशक, आइआइटी-दिल्ली

टॉप 10 टेक्निकल यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	रैंक 2020	रैंक 2019	रैंक 2018
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली, *नई दिल्ली*	1	1	2
2	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-खड़गपुर, *खड़गपुर*	2	2	1
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे, *मुंबई*	3	3	एनपी
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर, *कानपुर*	एनपी	एनपी	3
5	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी, *गुवाहटी*	4	4	4
6	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मंडी, *मंडी*	6	एनपी	एनपी
7	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	5	5	5
8	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंगलोर-*बेंगलूरु*	10	एनपी	एनपी
9	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड साइंस, *पिलानी*	7	एनपी	एनपी
10	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, *हैदराबाद*	9	एनपी	एनपी

*एनपी-हिस्सा नहीं लिया

मेरा विश्वविद्यालय

“हम लैब में कभी भी जा सकते हैं. किसी भी समय काम करने की सुविधा हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है. एक रिसर्च स्कॉलर के लिए लैब तक पहुंच ही उसके आगे के काम और जीवन को आकार देती है”

—सोहम दास
पीएचडी छात्र, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग,
आइआइटी, दिल्ली

इंजीनियरिंग है. असल में, पिछले चार साल में 10 विभाग बनाए गए हैं.

पिछले एक साल से आइआइटी-दिल्ली शोध और नवाचार में अगुआ रहा है. कोविड-19 के लिए एक रैपिड ऐंटीजन टेस्ट किट यहां विकसित की गई. जुलाई, 2020 में, महज 399 रुपए की आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की गई. रमजा जीनोसेंसर, आइआइटी-दिल्ली में पोषित एक स्टार्ट-अप ने बहुद्देश्यीय ऑर्गेनिक हाइब्रिड सरफेस डिसइनफैक्टेंट स्प्रे विकसित किया. नैनोशॉट नामक इस स्प्रे का एक छिड़काव 96 घंटों तक प्रभावी रहता है. यह स्प्रे किट कार के डैशबोर्ड/ सीट, मेज, बटुए, किताबें, सामान, लिफ्ट कंट्रोल पैन, टीवी रिमोट और अन्य सामान को सैनिटाइज कर सकता है. आइआइटी-दिल्ली में पोषित स्टार्ट-अप ई-टीईएक्स और क्लेंस्टा ने मिलकर एक संपूर्ण ऐंटी-वायरल प्रोटेक्शन किट अक्तूबर, 2020 में लॉन्च किया था. इसमें एक नॉवेल क्लेंस्टा प्रोटेक्शन लोशन और हैंड सैनिटाइजर होता है और साथ में ई-टेक्स कवच ऐंटी-वायरल टी-शर्ट और कवच मास्क भी होता है.

एक अन्य उत्पाद कम लागत का चेहरे की सुरक्षा का उपकरण कोवलॉक है. यह प्रभावी रूप से एक इनसान से दूसरे में संक्रामक वायरस के प्रसार को रोक सकता है. जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो इससे संपर्क में आने वाला संक्रमण का शिकार हो जाता है. यह एक प्रभावी एर्गोनॉमिक फेसशील्ड है जिसे चश्मे की तरह लंबे वक्त तक पहना जा सकता है. इन उत्पादों को क्लिफोर्ड चांस बिजनेस सर्विसेज ने वित्तीय सहायता दी. परियोजना क्लिफोर्ड चांस बिजनेस सर्विसेज और आइआइटी-दिल्ली की साझीदारी में पूरी की गई.

—शेली आनंद से बातचीत पर आधारित

➤ पांच बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहां लागत खर्च का अच्छा प्रतिफल मिलता है

रैंक	यूनिवर्सिटी	आरओआइ
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-खड़गपुर*, *खड़गपुर*	102.75
2	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर, *कानपुर*	88.10
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी, *गुवाहाटी*	76.65
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मंडी, *मंडी*	75.70
5	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे*,-*मुंबई*	66.12

नोट- आरओआइ (निवेश का प्रतिफल) की गणना औसत सालाना वेतन (एमटेक)/ट्यूशन फीस (एमटेक के पूरे कोर्स) से की जाती है; *लॉकडाउन के कारण, आइआइटी बांबे और आइआइटी खड़गपुर अपने ताजा आंकड़े नहीं दे सके हैं. लिहाजा उनकी तरफ से 2019 में दिए गए आंकड़ों और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया गया है.

➤ बीते 3 साल में सर्वाधिक पीएचडी देने वाली 5 टेक्निकल यूनिवर्सिटी

रैंक	यूनिवर्सिटी	संख्या
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे-*मुंबई*	1,118
2	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *नागपुर*	1,018
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली, *नई दिल्ली*	1,007
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-खड़गपुर, *खड़गपुर*	915
5	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी, *गुवाहाटी*	752

➤ बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा पेटेंट के आवेदन दाखिल करने वाली पांच टेक्निकल यूनिवर्सिटी

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली, *नई दिल्ली*	410
2	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे-*मुंबई*	403
3	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, *मुंबई*	213
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-खड़गपुर, *खड़गपुर*	196
5	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर, *कानपुर*	178

➤ पांच टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिनके बीते तीन साल मे सबसे ज्यादा पेटेंट प्रकाशित हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे-*मुंबई*	367
2	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली, *नई दिल्ली*	244
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-खड़गपुर, *खड़गपुर*	156
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर, *कानपुर*	151
5	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, *मुंबई*	135

* कोविड लॉकडाउन के कारण, आइआइटी बांबे और आइआइटी खड़गपुर अपने ताजा आंकड़े नहीं दे सके हैं. लिहाजा उनकी तरफ से 2019 में दिए गए आंकड़ों और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया गया है.

➤ पांच टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिनको बीते 3 साल में सबसे ज्यादा पेटेंट हासिल हुए

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, *मुंबई*	157
2	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, *मुंबई*	153
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली, *नई दिल्ली*	96
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर, *कानपुर*	88
5	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, *खड़गपुर*	27

➤ पांच टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिनके बीते 3 साल में सबसे ज्यादा पेटेंटों को लाइसेंस मिले

रैंक	यूनिवर्सिटी	पेटेंट की संख्या
1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, *नई दिल्ली*	22
2	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, *मुंबई*	19
3	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, *मुंबई*	9
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, *कानपुर*	6
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, *गुवाहाटी*	6

* कोविड लॉकडाउन के कारण, आइआइटी बांबे ने ताजा आंकड़े नहीं दिए हैं. लिहाजा उनकी तरफ से 2019 में दिए गए आंकड़ों और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया गया है.

➤ बेहतर शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात वाली पांच टेक्निकल यूनिवर्सिटी

रैंक	यूनिवर्सिटी	औसत
1	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, *सोलन*	4.20
2	सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, *गंगटोक*	2.63
3	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मेरठ*	2.41
4	इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नीकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन (आइजीडीटीयूडब्ल्यू), *नई दिल्ली*	1.47
5	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड मैनेजमेंट, *जयपुर*	1.32

नोट- एमटेक विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए औसत निकाला गया है

नं. 1 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, *बेंगलूरु*

टेक्नोलॉजी में महारत

प्रोफेसर देबब्रत दास

वर्ष 1999 में जब सरकार और निजी क्षेत्र की सहायता से भारत के पहले आइटी-केंद्रित शैक्षिक संस्थान के तौर पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर (आइआइआइटी-बी) बनाया गया, तब इरादा इसे ऐसे ही दूसरे संस्थानों में अव्वल बनाने का था. आज टेक्नोलॉजी की शिक्षा में 20 से ज्यादा साल पूरे करने के बाद आइआइआइटी-बी अपने क्षेत्र में दुनिया का सबसे अव्वल शैक्षणिक संस्थान है और लगातार अपनी प्रतिष्ठा में इजाफा कर रहा है.

हालांकि अपनी स्थापना के पहले दिन से ही इसका फोकस छात्रों को ऊंचे दर्जे की शिक्षा और समृद्ध पेशेवर अनुभव देना रहा है. विद्यार्थियों में लोकप्रिय इसके कोर्स में पांच साल का इंटीग्रेटेड एमटेक, दो साल का एमटेक और रिसर्च प्रोग्राम शामिल हैं. बाद में यही विद्यार्थी ब्लू-चिप कंपनियों और अव्वल टेक फर्म में जगह पाते हैं. इससे आइआइआइटी-बी में हमारी तरफ से दी जा रही अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की झलक मिलती है.

शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा संबंध संकाय की गुणवत्ता से है. हमारे यहां इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन शिक्षक हैं, जिनकी बुनियाद, अकादमिक साख और रिसर्च आउटपुट बहुत प्रभावशाली है. संकाय सदस्यों के चयन में हम कई दौर के इंटरव्यू और समीक्षा की कठोर प्रक्रिया अपनाते हैं, ताकि हमारे नजरिए के मुताबिक श्रेष्ठ का चयन किया जा सके. हमारे संकाय सदस्य मोटिवेटर हैं जो विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम प्रदर्शन में समर्थ बनाते हैं.

अब हम मजबूत अंतर-विषयी नजरिया भी विकसित कर रहे हैं. विद्यार्थियों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी, प्रयोगशालाएं और अध्ययन संसाधन सुलभ हैं. अकादमिक फोकस रिसर्च और इनोवेशन या नवाचार पर है. नए शोध और अनुसंधान कैसे समाज में असर डाल सकते हैं, इस पर भी बहुत जोर दिया जाता है. हम उच्चतर सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए छात्रों को समाज और देश को ध्यान में रखकर सोचना सिखाने की कोशिश करते हैं. आइआइटी-बी में पढ़ने का सबसे लाभदायक पहलू यह है कि हमारे विद्यार्थी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों और कई क्षेत्रों में उथल-पुथल मचाने वाले स्टार्ट-अप के साथ इंटर्नशिप और संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट करने का तर्जुबा हासिल करते हैं.

आइआइआइटी-बी अहम ग्लोबल प्रोग्राम भी चला रहा है. मसलन, एमओएसआइपी (मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म) या मोसिप, जो लागत-प्रभावी डिजिटल फाउंडेशनल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने में सरकारों और दूसरे संगठनों की मदद करता है. बनावट में मॉड्यूलर होने की वजह से

हेमंत मिश्रा

गुरु वाणी

“हम अनेक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को मिलाकर मजबूत अंतर-विषयी नजरिया विकसित कर रहे हैं”

-प्रोफेसर देबब्रत दास, डायरेक्टर,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, बेंगलूरु

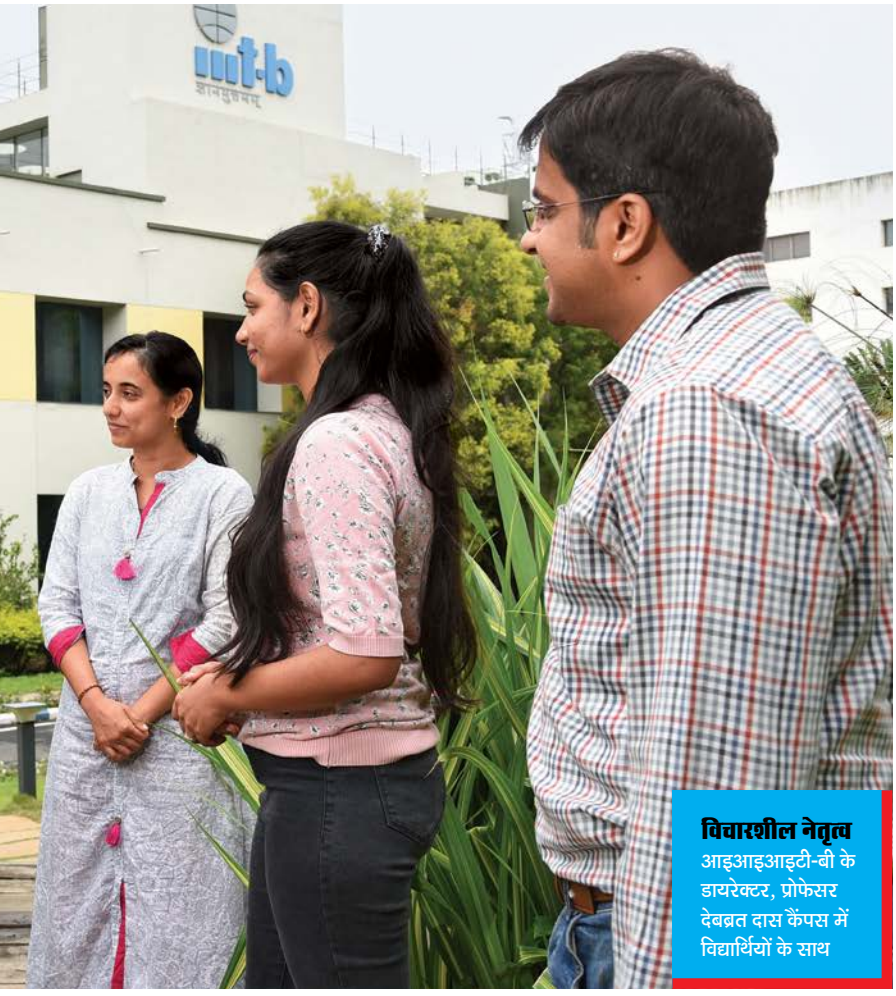

विचारशील नेतृत्व
आइआइआइटी-बी के डायरेक्टर, प्रोफेसर देबब्रत दास कैंपस में विद्यार्थियों के साथ

मेरा विश्वविद्यालय

"यहां का पाठ्यक्रम लचीला और विद्यार्थियों के हितों के अनुकूल और करियर के लिहाज से भी अहम है. यहां पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों और विद्यार्थियों की शारीरिक तथा मानसिक तंदुरुस्ती पर भी समान तरीके से ध्यान दिया जाता है, जो हर किसी के लिए खास अहमियत रखता है "

—कलवा वैष्णवी
आइआइआइटी-बी ग्रेजुएट 2021

मोसिप यूजर को अपने सिस्टम लागू और कनफिगर करने की सहूलत देता है.

हम तमाम विषयों पर अलग-अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के जरिए नई से नई लोकप्रिय टेक्नोलॉजी पर भी जोर दे रहे हैं. इनमें सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐंड पब्लिक पॉलिसी टेक्नोलॉजी के नवाचारों की नीतिगत चुनौतियों और सांगठनिक तकाजों पर ध्यान देता है, ताकि उन्हें स्वीकार्य बनाया जा सके.

ई-हेल्थ रिसर्च सेंटर अंतर-विषयी शोध केंद्र है जो आइआइआइटी-बी के लिए सामयिक अनुसंधान के अनेक क्षेत्रों तक फैला है. मशीन इंटेलिजेंस ऐंड रोबोटिक्स सेंटर अपने विषय में अध्ययन के लिए ''बेस्ट-इन-क्लास'' सीओई है. इसी तरह एमफैसिस कॉग्निटिव कंप्यूटिंग सीओई समाज और उद्यमों के लिए सामयिक एप्लाइड रिसर्च पर ध्यान देता है. सभी केंद्र जानी-मानी टेक्नोलॉजी या

आइआइआइटी-बी में पढ़ने का सबसे लाभदायक पहलू यह है कि विद्यार्थी अग्रणी टेक कंपनियों के साथ इंटर्नशिप और रिसर्च का तजुर्बा हासिल करते हैं

आइटी कंपनियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं जिनमें विद्यार्थियों को नया और ठोस तजुर्बा हासिल होता है. ये सब विद्यार्थियों को बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हमारी कोशिशों के हिस्से हैं.

खास बात यह है कि हाल के दौर में महामारी के दौरान आइआइआइटी-बी ने आम लोगों की भलाई के लिए कई नए कामों की अगुआई की. इनमें एक स्टार्ट-अप के साथ मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोविड-19 की जांच का मॉड्यूल विकसित करना भी शामिल है. हमारा सबसे बड़ा योगदान वेब ऐप 'बेंगलूरू फॉर ह्यूमैनिटी' है, जो कोविड के इलाज की सुविधाओं, ऑक्सीजन, दवाई, प्लाज्मा, ब्लड टाइप की उपलब्धता और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के अलावा कई प्रामाणिक और ताजातरीन जानकारियां मुहैया करता है. वॉलंटियरों से सत्यापित करने के बाद डाली गई जानकारियां भी संबंधित लोगों को मिलती हैं. ■

—अरविंद गौड़ा से बातचीत पर आधारित

नं. 1 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी
बेंगलूरु

वर्चुअल हो रहे फैसले

प्रोफेसर (डॉ.) सुधीर कृष्णास्वामी

हेमंत मिश्रा

कुशल नेतृत्व
प्रो. (डॉ.) सुधीर कृष्णास्वामी एनएलएसआइयू कैंपस में

भारतीय न्यायालय व्यवस्था ने कोविड महामारी के अनुरूप खुद को बखूबी ढाल लिया है. शुरू के कुछ महीनों में विलंब और अनिश्चितता के बाद उच्च न्यायालयों ने वेब आधारित प्लेटफॉर्म और ऐप्लिकेशन को अपना लिया और देश के इतिहास में पहली बार मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई. वकील, मुवक्किल और न्यायाधीश, सब अपने काम को ऑनलाइन ले जाने की अहमियत से वाकिफ थे. आखिरकार, जिस बदलाव का लंबे अरसे से इंतजार था, वह शुरू हो गया. लेकिन निचली अदालतों को अब भी ऑनलाइन करने की जरूरत है. हमें हर कमरे में वीडियो की जरूरत नहीं है, हम ऑडियो से ही काम चला सकते हैं. मिसाल के तौर पर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो सुनवाई बहुत कारगर है. उचित टेक्नोलॉजी से निचली अदालतों को न सिर्फ अभी बल्कि कोविड के बाद के माहौल में भी सुचारू ढंग से काम करने में मदद मिलेगी. ऑनलाइन सुनवाई से अदालतों को मुवक्किल के अनुकूल होने में भी सहायता मिलेगी. जैसे, इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में हमेशा हाजिर नहीं हो सकते.

कानून का पेशा मुख्यत: दो हिस्सों में बंटा है: अदालतों में दर्ज मुकदमे और ट्रैन्जैक्शनल लॉ. आभासी (वर्चुअल) सहयोग और अलग-अलग कार्यस्थलों पर वीडियो और ऑडियो कम्युनिकेशन की बदौलत इन दोनों क्षेत्रों में डिजिटल बदलाव आया है. अब टीम को समय सीमा के भीतर काम करने देने के लिए व्यक्ति को खुद को व्यस्थित करने की जरूरत है.

इस डिजिटल बदलाव का एक पहलू टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, लेकिन दूसरे पहलू का सरोकार कामकाज की बदलती संस्कृति से है. एनएलएसआइयू के विद्यार्थियों को करीब 16 महीने से ऑनलाइन क्लासेज में सीख रहे हैं. यह वर्चुअल शिक्षा उन्हें आने वाले दिनों में बहुत मददगार साबित होगी. सामान्य क्लासेज के अलावा, हमने मूट कोर्ट तैयार करने का ऑनलाइन तरीका निकाला है और ऑनलाइन क्लिनिकल कोर्सेज शुरू की है, जिससे विद्यार्थियों को अपने कामकाज की जगह की कार्यशैली के अनुरूप ढलने में मदद मिलती है. एनएलएसआइयू के विद्यार्थी इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि उन्हें यह अवसर मिल रहा है.

पिछले 14 महीनों से हम एक और क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं और वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल. एनएलएसआइयू में हमारा उद्देश्य न केवल ज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अगुआ बनने का है जिनके पास कंप्यूटर साइंस के इस्तेमाल और कानून की जानकारी से टेक्नोलॉजी और कानून की जानकारी एक सूत्र में पिरो देने वाले नए ऐप्लिकेशन विकसित करने की क्षमता हो बल्कि हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम अपने विद्यार्थियों को इन ऐप्लिकेशंस के नए तरीकों से इस्तेमाल में माहिर बनाएं ताकि वे आने वाले वर्षों में कानून के पेशे में होने वाले सबसे बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें. कानून की शिक्षा में एक और बदलाव यह है कि ऑनलाइन ऑफ-कैंपस और कैंपस के भीतर रहकर शिक्षा हासिल करने के बीच की रेखा धूमिल होती जा रही है. ऑनलाइन क्विज और टेस्ट या सहयोगात्मक सामूहिक गतिविधियां जरूरी हो गई हैं. यह कानून की शिक्षा के नए मॉडल का क्षेत्र है, जिसमें

गुरु वाणी

“डिजिटल ऐप्लिकेशन कानून के पेशे में बड़े पैमाने पर बदलाव करने वाले हैं”

—प्रोफेसर (डॉ.) सुधीर कृष्णास्वामी
वाइस-चांसलर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलूरु

टॉप 5 बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	रैंक 2020	रैंक 2019	रैंक 2018
1	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरु*	1	1	1
2	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, *कोलकाता*	एनपी	एनपी	2
3	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	2	2	एनपी
4	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *गांधीनगर*	3	एनपी	एनपी
5	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	4	7	एनपी

*एनपीः हिस्सा नहीं लिया

सबसे कम ट्यूशन फीस वाली पांच यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	ट्यूशन फीस (रु.)
1	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, *कोलकाता*	68,000
2	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	69,000
3	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, *कटक*	70,000
4	द तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, *चेन्नै*	70,200
5	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *गांधीनगर*	80,000

बेहतर शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात वाली यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	अनुपात *
1	द तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, *चेन्नै*	1.41
2	दामोदरन संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *विशाखापत्तनम*	1.39
3	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	1.33
4	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरु*	1.28
5	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, *कोलकाता*	1.22

नोटः अनुपात निकालने के लिए सिर्फ एलएलएम के विद्यार्थियों की गणना की गई

बीते 3 वर्षों में सर्वाधिक पीएचडी देने वाली 5 यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	संख्या
1	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरु*	26
2	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, *कोलकाता*	24
3	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	18
4	द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, *कोच्चि*	9
5	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	6

सबसे ज्यादा बार इंटर यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीतने वाली 5 यूनिवर्सिटी

रैंक 2021	यूनिवर्सिटी	प्रतियोगिताएं जीतीं
1	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	22
2	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *गांधीनगर*	21
3	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, *कोलकाता*	9
4	द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, *कोच्चि*	5
5	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	4
5	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, *कटक*	4

मेरा विश्वविद्यालय

"आवासीय परिसर होने के कारण यह हमें दिलचस्पी के अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने का अवसर देता है. कैंपस में हमेशा सांस्कृतिक आयोजन और मूट कोर्ट कंपीटिशन जैसी गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं"

—दिव्य कुमार गर्ग

एनएलएसआइयू छात्र, 2021 बैच

हम अग्रणी बनना चाहते हैं. हमारे लिए ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्र खुल रहा है और हमें उम्मीद है कि एक-दो साल में ऑफ-कैंपस शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ ही ऑनलाइन कानूनी शिक्षा में अग्रणी होंगे.

—अरविंद गौड़ा के साथ बातचीत पर आधारित

सर्वेक्षण के पूरे नतीजे

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	प्रतिष्ठा और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
			208	250	175	150	217	1,000	1,000	2,000
1	1	जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	175.4	200.1	159.3	141.8	176.0	852.6	998.1	1,850.7
2	एनपी	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, *नई दिल्ली*	162.3	163.7	138.6	113.1	189.4	767.1	990.2	1,757.3
3	2	यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, *हैदराबाद*	174.3	170.4	152.3	121.1	148.5	766.6	980.6	1,747.2
4	3	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	175.5	185.1	147.0	102.0	164.5	774.1	949.0	1,723.1
5	5	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, *कोलकाता*	167.7	166.7	104.1	92.5	156.2	687.2	955.1	1,642.3
6	8	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, *नई दिल्ली*	149.5	180.7	127.3	122.5	159.0	739.0	901.6	1,640.6
7	6	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, केरल, *कोट्टायम*	160.0	175.1	141.7	122.1	106.0	704.9	908.4	1,613.3
8	9	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, *मुंबई*	168.9	160.7	105.4	111.1	137.8	683.9	916.8	1,600.7
9	10	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, *समस्तीपुर, बिहार*	157.9	157.9	141.0	71.2	138.6	666.6	933.6	1,600.2
10	7	कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *कोच्चि*	160.5	162.1	129.5	114.9	167.3	734.3	860.7	1,595.0
11	12	आंध्र यूनिवर्सिटी, *विशाखापत्तनम*	177.7	164.0	104.7	91.4	125.0	662.8	908.6	1,571.4
12	एनपी	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	134.6	145.8	117.4	83.3	143.7	624.8	945.5	1,570.3
13	11	मंगलौर यूनिवर्सिटी, *मंगलूरु*	150.2	159.0	133.3	97.5	146.3	686.3	882.9	1,569.2
14	14	भारतियर यूनिवर्सिटी, *कोयंबत्तूर*	146.2	172.3	125.1	97.5	136.4	677.5	884.5	1,562.0
15	17	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, *गुंटूर, आंध्र प्रदेश*	135.3	160.0	126.3	109.2	124.3	655.1	845.8	1,500.9
16	16	द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, *बर्धमान, पश्चिम बंगाल*	156.1	151.5	122.7	59.2	154.1	643.6	854.6	1,498.2
17	20	गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, *अमृतसर*	151.9	146.3	111.9	86.0	142.6	638.7	851.1	1,489.8
18	15	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, *तिरुवनंतपुरम*	164.0	166.2	139.3	83.7	81.2	634.4	843.0	1,477.4
19	19	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, *अजमेर*	123.3	153.8	142.8	118.6	98.6	637.1	827.1	1,464.2
20	एनपी	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, *तिरुपति*	150.6	155.3	100.4	76.0	120.7	603.0	850.2	1,453.2
21	22	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, *लखनऊ*	141.3	155.1	102.9	72.4	96.3	568.0	884.1	1,452.1
22	21	द इंग्लिश ऐंड फॉरेन लेंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, *हैदराबाद*	130.7	150.0	118.6	66.3	132.3	597.9	847.9	1,445.8
23	23	गोवा यूनिवर्सिटी, *पणजी*	146.3	138.7	112.8	111.9	110.9	620.6	769.1	1,389.7
24	25	डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर ऐंड फॉरेस्ट्री, *सोलन, हिमाचल प्रदेश*	119.7	151.8	111.7	60.0	147.2	590.4	657.4	1,247.8

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	प्रतिष्ठा और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
			208	250	175	150	217	1,000	1,000	2,000
25	26	मिजोरम यूनिवर्सिटी, *आइजोल*	144.2	145.9	107.4	76.1	113.8	587.4	599.4	1,186.8
26	एनपी	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, *गया*	126.5	116.6	85.1	68.7	100.3	497.2	678.2	1,175.4
27	27	कुमाऊं यूनिवर्सिटी, *नैनीताल*	114.2	115.2	106.6	65.1	106.6	507.7	646.4	1,154.1
28	29	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, *हैदराबाद*	102.1	145.2	129.9	92.3	140.4	609.9	523.2	1,133.1
29	30	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, *मिदनापुर*	132.6	140.4	104.4	65.8	120.1	563.3	559.9	1,123.2
30	एनपी	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, *कोटा*	88.6	60.1	65.3	0.5	10.4	224.9	605.0	829.9
31	एनपी	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, *ग्वालियर*	71.9	103.1	110.8	60.9	15.9	362.6	459.0	821.6
32	एनपी	कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी, *रामटेक, महाराष्ट्र*	144.9	108.4	104.6	92.2	40.9	491.0	196.5	687.5
33	एनपी	श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, *सिद्दीपेट, तेलंगाना*	68.3	148.2	122.2	92.8	160.5	592.0	93.3	685.3
34	एनपी	माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म ऐंड कम्युनिकेशन, *भोपाल*	74.4	82.2	65.0	22.8	64.0	308.4	360.4	668.8
35	34	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, *राजोरी, जम्मू और कश्मीर*	111.5	137.7	112.8	67.1	87.2	516.3	151.6	667.9

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	प्रतिष्ठा और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
			208	250	175	150	217	1,000	1,000	2,000
1	1	एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, *नोएडा*	136.2	150.9	149.5	119.9	144.0	700.5	918.2	1618.7
2	2	वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *वेल्लौर*	139.8	154.2	134.0	83.7	144.2	655.9	909.3	1565.2
3	3	क्राइस्ट (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *बेंगलूरु*	131.5	127.2	142.9	112.4	152.7	666.7	893.9	1560.6
4	5	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *चेन्नै*	145.5	147.2	140.4	116.6	127.4	677.1	879.2	1556.3
5	4	एसवीकेएम'एस नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मुंबई*	139.7	141.7	106.5	119.6	156.2	663.7	888.5	1552.2
6	7	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *गुंटूर*	138.7	150.7	130.7	119.6	136.6	676.3	808.8	1485.1
7	6	बनस्थली विद्यापीठ, *बनस्थली विद्यापीठ*	133.9	135.7	142.1	110.7	141.8	664.2	819.6	1483.8
8	8	जैन (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) *बेंगलूरु*	136.1	138.7	133.8	92.6	144.3	645.5	816.8	1462.3
9	9	निरमा यूनिवर्सिटी, *अहमदाबाद*	137.8	145.5	125.8	111.2	132.3	652.6	756.5	1409.1
10	11	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	135.4	148.5	131.6	105.1	143.8	664.4	742.9	1407.3

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक – जनरल (प्राइवेट)

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	प्रतिष्ठा और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
			208	250	175	150	217	1,000	1,000	2,000
11	10	जेवियर यूनिवर्सिटी, *भुवनेश्वर*	68.0	116.2	114.8	110.8	161.0	570.8	832.4	1403.2
12	एनपी	मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, *जयपुर*	120.2	169.3	149.8	107.5	140.8	687.6	682.1	1369.7
13	14	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऐंड स्टडीज, *फरीदाबाद*	110.1	146.2	136.8	116.5	153.6	663.2	669.1	1332.3
14	16	आइसीएफएआइ फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, *हैदराबाद*	117.9	115.4	142.9	110.5	154.1	640.8	677.0	1317.8
15	17	चितकारा यूनिवर्सिटी, *पटियाला*	108.9	134.0	150.1	111.7	150.8	655.5	609.7	1265.2
16	21	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, *मोहाली*	106.0	141.3	127.0	93.7	153.2	621.2	621.6	1242.8
17	19	गलगोटिया यूनिवर्सिटी, *ग्रेटर नोएडा*	59.5	111.6	92.8	112.5	110.3	486.7	749.2	1235.9
18	20	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट साइंसेज, *सोलन*	116.0	130.5	106.7	110.8	134.2	598.2	616.5	1214.7
19	एनपी	येनेपोया (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मंगलूरू*	128.2	165.4	133.4	107.3	144.6	678.9	529.1	1208.0
20	24	महर्षि मार्कंडेश्वर (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), मुलाना, *अंबाला*	113.6	127.5	111.1	108.8	117.7	578.7	622.8	1201.5
21	एनपी	एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, *गुरुग्राम*	110.0	138.4	124.9	65.1	118.5	556.9	638.2	1195.1
22	18	एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान, *जयपुर*	113.1	140.8	137.8	82.4	112.7	586.8	605.7	1192.5
23	25	जीएलए यूनिवर्सिटी, *मथुरा*	106.5	114.3	108.4	78.0	109.4	516.6	656.9	1173.5
24	23	एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, *ग्वालियर*	83.3	146.0	143.7	85.0	138.1	596.1	560.9	1157.0
25	26	द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, *गुरुग्राम*	100.8	134.7	131.4	110.7	111.0	588.6	517.6	1106.2
26	28	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी ऐंड एडवांस्ड स्टडीज (विस्तास), *चेन्नै*	112.1	150.2	140.2	110.5	90.0	603.0	485.4	1088.4
27	22	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, *जयपुर*	112.1	112.5	114.3	90.2	113.3	542.4	524.4	1066.8
28	एनपी	आइटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, *ग्वालियर*	94.4	101.3	129.6	70.4	130.4	526.1	531.4	1057.5
29	29	डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, *बिलासपुर*	107.0	124.0	94.9	94.3	103.9	524.1	497.3	1021.4
30	33	रेवा यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरू*	66.1	140.3	133.2	111.7	144.0	595.3	422.5	1017.8
31	27	जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी, *जयपुर*	77.6	134.0	112.6	102.0	132.3	558.5	457.3	1015.8
32	32	सीएफएआइ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा, *अगरतला*	110.3	123.3	136.0	92.8	95.0	557.4	396.6	954.0
33	36	स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, *मेरठ*	118.4	124.7	129.2	93.1	98.6	564.0	347.5	911.5
34	एनपी	आइआइएचएमआर यूनिवर्सिटी, *जयपुर*	91.0	86.1	100.5	64.5	150.1	492.2	413.4	905.6
35	एनपी	आइआइएस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *जयपुर*	109.0	115.5	119.2	111.7	79.9	535.3	366.9	902.2
36	31	आइसीएफएआइ यूनिवर्सिटी, *देहरादून*	88.8	114.2	113.0	81.2	131.1	528.3	367.2	895.5
37	35	असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी, *गुवाहाटी*	99.1	109.7	107.9	85.7	78.5	480.9	395.6	876.5
38	34	रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, *रायसेन*	98.3	114.3	130.6	109.8	103.4	556.4	308.0	864.4
39	एनपी	जगन नाथ यूनिवर्सिटी, *जयपुर*	90.3	134.5	146.7	100.0	103.4	574.9	234.8	809.7
40	37	असम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी, *गुवाहाटी*	93.4	115.2	111.3	112.4	83.0	515.3	287.9	803.2
41	एनपी	मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, *राजकोट*	49.8	146.6	122.0	77.3	87.6	483.3	275.5	758.8
42	39	पारुल यूनिवर्सिटी, *वडोदरा*	64.2	100.1	102.6	70.9	113.1	450.9	301.7	752.6
43	40	जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	63.9	119.3	141.6	109.1	97.1	531.0	193.5	724.5

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक – *जनरल (प्राइवेट)*

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	प्रतिष्ठा और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
			208	250	175	150	217	1,000	1,000	2,000
44	41	श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड मेडिकल साइंसेज, *सीहोर*	77.9	108.8	108.0	110.0	124.2	528.9	142.3	671.2
45	एनपी	संस्कृति यूनिवर्सिटी, *मथुरा*	49.6	93.6	102.8	92.3	111.0	449.3	209.4	658.7
46	45	एडमास यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	57.9	119.6	120.6	79.8	82.5	460.4	172.2	632.6
47	एनपी	एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, *मुंबई*	66.3	89.1	82.6	72.9	147.0	457.9	174.6	632.5
48	46	जेआइएस यूनिवर्सिटी, *कोलकाता*	52.1	121.6	118.1	94.2	95.5	481.5	150.0	631.5
49	एनपी	एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, *रायपुर*	64.1	118.7	138.6	105.0	131.2	557.6	73.4	631.0
50	एनपी	आइएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, *देहरादून*	45.5	79.8	108.8	77.0	113.2	424.3	204.7	629.0
51	44	एकेएस यूनिवर्सिटी, *सतना*	60.3	130.9	112.9	85.3	66.5	455.9	171.6	627.5
52	एनपी	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरु*	43.2	89.6	96.7	59.6	97.5	386.6	224.3	610.9
53	एनपी	मानव रचना यूनिवर्सिटी, *फरीदाबाद*	49.2	130.4	146.1	117.2	65.7	508.6	53.5	562.1
54	एनपी	मालवांचल यूनिवर्सिटी, *इंदौर*	49.2	104.1	147.0	53.9	102.2	456.4	98.1	554.5
55	एनपी	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, *बाराबंकी*	63.5	107.1	105.0	57.1	98.5	431.2	113.1	544.3
56	47	पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, *जयपुर*	59.1	118.8	108.6	94.1	97.9	478.5	63.8	542.3
57	48	आइसीएफएआइ यूनिवर्सिटी, झारखंड, *रांची*	64.2	102.8	101.9	76.7	119.4	465.0	52.6	517.6
58	एनपी	आइटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी, *वडोदरा*	41.3	40.2	92.2	44.4	116.7	334.8	172.2	507.0
59	49	मंगलायतन यूनिवर्सिटी, *अलीगढ़*	76.2	97.9	141.3	44.1	57.5	417.0	22.7	439.7
60	50	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, *शिलांग*	51.8	77.3	45.6	45.7	56.4	276.8	138.6	415.4
61	52	सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, *गंगटोक*	62.0	93.6	70.5	66.7	84.6	377.4	32.0	409.4
62	एनपी	आइसेक्ट यूनिवर्सिटी, *हजारीबाग*	21.0	30.7	27.9	12.2	149.9	241.7	117.1	358.8

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक – *मेडिकल*

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	स = सरकारी / प्रा = प्राइवेट	दाखिला गुणवत्ता और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
				225	225	200	150	200	1000	1000	2000
1	1	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *नई दिल्ली*	स	208.1	211.4	193.7	141.5	197.6	952.3	1000.0	1952.3
2	2	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *पुदुच्चेरी*	स	193.8	186.5	188.7	143.1	190.3	902.4	970.1	1872.5
3	3	किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	स	189.1	169.3	163.7	121.6	189.6	833.3	955.2	1788.5
4	एनपी	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऐंड न्यूरोसाइंसेज (एनआइएमएचएएनएस), *बेंगलूरु*	स	193.6	173.9	157.7	109.2	198.5	832.9	952.2	1785.1
5	4	पंडित भागवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, *रोहतक*	स	188.6	166.2	177.7	140.6	181.2	854.3	889.6	1743.9
6	एनपी	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *जोधपुर*	स	184.3	159.4	140.4	114.3	165.9	764.3	871.6	1635.9
7	एनपी	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, *भुवनेश्वर*	स	181.3	163.8	149.6	111.3	151.0	757.0	853.7	1610.7

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक – *जनरल (प्राइवेट)*

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	स = सरकारी / प्रा = प्राइवेट	दाखिला गुणवत्ता और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
				225	225	200	150	200	1000	1000	2000
8	5	श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	प्रा	177.0	165.8	169.1	124.8	162.2	798.9	647.8	1446.7
9	एनपी	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ऐंड बिलिएरी साइंसेज, *नई दिल्ली*	स	172.0	158.5	146.5	110.7	170.3	758.0	686.6	1444.6
10	6	जेएसएस एकेडेमी ऑफ हायर एजुकेशन ऐंड रिसर्च, *मैसूरु*	प्रा	187.0	162.8	114.1	127.3	160.0	751.2	683.6	1434.8
11	12	एनआइटीटीई (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मंगलूरु*	प्रा	154.9	165.4	163.2	118.1	144.9	746.5	677.6	1424.1
12	8	बीएलडीइ (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *विजयपुरा*	प्रा	176.4	145.0	167.8	109.4	145.6	744.2	609.0	1353.2
13	9	सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, *गंगटोक*	प्रा	179.8	151.9	184.6	125.2	135.6	777.1	471.6	1248.7
14	11	डी.वाइ. पाटिल एजुकेशन सोसाइटी (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *कोल्हापुर*	प्रा	170.5	140.7	128.2	105.3	138.0	682.7	483.6	1166.3
15	12	श्री बालाजी विद्यापीठ (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *पुदुच्चेरी*	प्रा	174.4	133.6	150.9	102.5	122.9	684.3	211.9	896.2

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक – *टेक्निकल*

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	स = सरकारी / प्रा = प्राइवेट	दाखिला गुणवत्ता और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
				208	250	175	150	217	1000	1,000	2,000
1	1	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-दिल्ली, *नई दिल्ली*	स	184.6	218.1	156.0	129.0	198.1	885.8	1,000.0	1,885.8
2	2	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-खड़गपुर, *खड़गपुर*	स	181.8	208.5	149.5	125.5	206.5	871.8	992.5	1,864.3
3	3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-बॉम्बे, *मुंबई*	स	184.4	211.2	149.9	137.5	194.1	877.1	981.5	1,858.6
4	एनपी	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर, *कानपुर*	स	170.3	202.2	151.3	122.6	188.9	835.3	981.6	1,816.9
5	4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी, *गुवाहाटी*	स	161.3	189.2	150.5	117.0	203.6	821.6	952.0	1,773.6
6	6	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मंडी, *मंडी*	स	140.0	171.1	144.6	105.6	180.4	741.7	882.0	1,623.7
7	5	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, *नई दिल्ली*	स	151.0	170.2	143.9	101.4	151.2	717.7	900.5	1,618.2
8	10	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बंगलौर, *बेंगलूरु*	प्रा	121.1	161.1	126.5	95.1	173.7	677.5	834.0	1,511.5
9	7	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड साइंस, *पिलानी*	प्रा	136.1	150.8	142.0	110.8	134.0	673.7	830.9	1,504.6
10	9	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, *हैदराबाद*	प्रा	120.5	158.2	127.1	94.9	175.9	676.6	819.7	1,496.3
11	8	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-भुवनेश्वर, *भुवनेश्वर*	स	132.1	184.5	128.4	86.9	123.2	655.1	753.4	1,408.5
12	12	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, *मुंबई*	स	152.3	157.7	116.2	90.1	118.2	634.5	771.4	1,405.9
13	एनपी	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गांधीनगर, *गांधीनगर*	स	138.2	184.7	135.2	88.8	119.2	666.1	737.3	1,403.4
14	एनपी	स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर, *नई दिल्ली*	स	109.4	159.8	85.7	92.5	125.8	573.2	775.0	1,348.2
15	11	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *नागपुर*	स	110.4	152.1	120.8	73.1	115.0	571.4	770.9	1,342.3
16	13	इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, *नई दिल्ली*	स	111.5	138.8	126.3	99.4	117.8	593.8	745.9	1,339.7

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक - **टेक्निकल**

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	स = सरकारी / प्रा = प्राइवेट	दाखिला गुणवत्ता और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
				208	250	175	150	217	1000	1,000	2,000
17	15	स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर, *विजयवाड़ा*	स	110.2	134.7	101.8	92.1	117.6	556.4	665.4	1,221.8
18	14	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *सिलचर*	स	119.5	133.8	120.6	82.6	117.0	573.5	642.6	1,216.1
19	17	स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर, *भोपाल*	स	114.3	131.3	96.6	88.4	120.5	551.1	650.1	1,201.2
20	16	सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, *गंगटोक*	प्रा	140.1	142.5	129.0	112.5	112.7	636.8	547.2	1,184.0
21	एनपी	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, *श्रीनगर*	स	104.8	152.9	145.0	98.0	90.9	591.6	548.6	1,140.2
22	19	हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड साइंस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *चेन्नै*	प्रा	92.8	131.5	119.4	103.5	112.8	560.0	576.0	1,136.0
23	18	मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, *गोरखपुर*	स	128.6	139.0	123.4	90.3	78.3	559.6	564.9	1,124.5
24	20	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, *सोलन*	प्रा	111.2	136.2	122.9	124.4	96.6	591.3	498.0	1,089.3
25	23	विज्ञान'स फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी ऐंड रिसर्च (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *गुंटूर*	प्रा	112.6	132.9	111.3	90.8	89.4	537.0	520.2	1,057.2
26	21	गुरु जांबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, *हिसार*	स	133.2	132.5	108.7	93.0	53.4	520.8	527.7	1,048.5
27	22	सोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), *मेरठ*	प्रा	90.3	117.8	145.7	88.2	91.9	533.9	498.1	1,032.0
28	एनपी	जेएसएस साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, *मैसूरू*	प्रा	77.9	130.5	92.5	100.7	115.0	516.6	477.0	993.6
29	एनपी	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड मैनेजमेंट, *जयपुर*	प्रा	70.8	129.4	121.7	118.4	120.0	560.3	177.8	738.1

भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी

स्कोर और रैंक - **लॉ**

ओवर-ऑल रैंक 2021	ओवर-ऑल रैंक 2020	यूनिवर्सिटी	दाखिला गुणवत्ता और गवर्नेंस	अकादमिक और शोध गुणवत्ता	इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल	व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास	करियर संभावना और प्लेसमेंट	ऑब्जेक्टिव स्कोर	धारणात्मक स्कोर	ओवरऑल स्कोर
			175	250	150	200	225	1000	1000	2000
1	1	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, *बेंगलूरु*	149.0	220.1	136.6	182.2	192.6	880.5	1000.0	1880.5
2	एनपी	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज, *कोलकाता*	143.0	214.4	137.5	176.6	191.1	862.6	961.9	1824.5
3	2	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, *भोपाल*	141.9	220.1	136.2	166.9	170.4	835.5	896.5	1732.0
4	3	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *गांधीनगर*	148.6	219.4	136.5	177.7	157.1	839.3	888.3	1727.6
5	4	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *लखनऊ*	141.3	193.2	142.1	153.0	187.7	817.3	852.8	1670.1
6	5	द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, *कोच्चि*	132.3	190.1	128.8	164.8	191.9	807.9	738.5	1546.4
7	6	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, *कटक*	132.1	193.6	135.0	180.2	174.3	815.2	602.2	1417.4
8	9	दामोदरम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, *विशाखापत्तनम*	132.0	139.7	128.3	150.1	136.7	686.8	487.9	1174.7
9	8	द तमिलनाडु डॉ. आंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, *चेन्नै*	131.5	111.2	123.6	55.0	139.8	561.1	561.5	1122.6

नोटः 1. रैंकिंग ऑब्जेक्टिव डेटा और धारणात्मक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं. 2.केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव डेटा जमा किए. आइआइएससी बैंगलोर, बीएचयू, आदि जैसे जिन विश्वविद्यालयों ने अपने ऑब्जेक्टिव डेटा समय पर जमा नहीं कराए या इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, उनकी रैंकिंग नहीं की गई. 3. केवल उन विश्वविद्यालयों को ही इसमें हिस्सा लेने के योग्य माना गया जिन्होंने निम्नलिखित मानकों को पूरा कियाः क. कम से कम तीन बैच उत्तीर्ण होकर निकल चुके हों. ख. जो पूर्णकालिक पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करते हों. 4. 4. सभी स्कोर की गणना दशमलव के एक अंक तक ही की गई है, मानकवार स्कोर जोड़ने में हो सकता है कि त्रुटियां दिख जाएं 5. जिन विश्वविद्यालयों की धारणात्मक सर्वे में रैंकिंग नहीं की गई है उनका धारणात्मक स्कोर शून्य है; एनपीः नॉट पार्टिसिपेटेड (भाग नहीं लिया)

डर्टी पिक्चर

अश्लील फिल्म निर्माण के रैकेट में कथित तौर पर शामिल व्यवसायी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी ने अश्लीलता पर भारतीय कानूनों को चर्चा में ला दिया है और अश्लीलता तथा कामोत्तेजकता की परिभाषाओं पर गरमा-गरम बहस छिड़ गई है

किरण डी. तारे
इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

मुंबई पुलिस 4 फरवरी को शहर के उत्तरी छोर पर स्थित मड आइलैंड इलाके में एकांत में बने एक बंगले में पहुंची, जहां पांच लोगों की एक टीम, दो लोगों की अंतरंग मुद्रा फिल्मा रही थी. कलाकारों और शूटिंग दल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. छह युवा अभिनेत्रियों ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच में जुटी पुलिस को इस शूटिंग की एक गुप्त सूचना मिली थी. अभिनेत्रियों ने निर्माताओं पर आरोप लगाया था कि वे उन पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए दबाव डाल रहे थे. पुलिस ने पाया कि छह छोटे कमरों, एक किचन और एक बगीचे वाले इस बंगले में शूट हुए वीडियो कुछ वेबसाइटों और हॉटशॉट्स, हॉटहिट और न्यूफ्लिक्स जैसे मोबाइल ऐप पर भुगतान करके देखने के लिए अपलोड किए जा रहे थे.

इसके छह महीने बाद, विभिन्न कंपनियों के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले करोड़पति व्यवसायी तथा बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति, राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को कुंद्रा को एक पेड स्ट्रीमिंग ऐप 'हॉटशॉट्स' के मालिक ब्रिटेन स्थित केनरिन प्रोडक्शन हाउस के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया. 'हॉटशॉट्स' के ऐप स्टोर पर विवरण के अनुसार, यह ''हॉट फोटोशूट, शॉर्ट फिल्मों और दुनिया भर की मशहूर हस्तियों की जीवनशैली से जुड़ी निजी सामग्रियां दिखाने का वादा करता है.'' हालांकि

पर्दाफाश!
राज कुंद्रा (बीच में) को 23 जुलाई को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया

अंशुमान पोयरेकर/गेट्टी इमेजेज

पोर्नोग्राफी—क्या कहता है भारत का कानून

- निजी स्थल पर अश्लील सामग्री देखना भारत में गैर-कानूनी नहीं है. हालांकि यौन अपराध बाल संरक्षण कानून, 2012 के मुताबिक बाल पोर्नोग्राफी को 'देखना, रखना या डाउनलोड' करना गुनाह है
- आइटी कानून, 2000 की धारा 67, 'अश्लील सामग्री' के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, वितरण को प्रतिबंधित करती है. इसमें तीन साल तक की कैद और/या 5 लाख रु. जुर्माना हो सकता है
- आइटी ऐक्ट की धारा 66ई निजता के उल्लंघन के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान करती है. कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी व्यक्ति के निजी हिस्से की छवि को उसकी सहमति के बिना कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करता है, वह दंड का भागी है
- भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 293 के अनुसार, 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को अश्लील सामग्री बेचना, वितरित करना, प्रदर्शित करना या प्रसारित करना गैर-कानूनी है. धारा 294 के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाने गाना अपराध की श्रेणी में आता है
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986, विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं की अशिष्ट रूप से प्रस्तुति को प्रतिबंधित करता है

इस घटना के बाद ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया गया है. केनरिन का स्वामित्व कुंद्रा के बिजनेस पार्टनर और बहनोई प्रदीप बख्शी के पास है, और हॉटशॉट्स ऐप को कुंद्रा की कंपनी आर्म्सप्राइम मीडिया ने बनाया है.

कुंद्रा के अलावा 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि वे बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े रोल दिलाने का लालच देकर युवतियों को इन वीडियो में काम करने के लिए तैयार करते थे. कुंद्रा और अन्य सभी पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (अश्लील इरादा), 292 और 293 (अभद्र और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के अलावा आइटी अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कुंद्रा पर वियान इंडस्ट्रीज के दफ्तर का उपयोग करके केनरिन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अच्छी सामग्री भेजने के भी आरोप हैं. कुंद्रा ही वियान इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जिसका नाम उनके बेटे के नाम पर रखा गया है. 22 जुलाई को पुलिस को दिए एक बयान में, वियान इंडस्ट्रीज के सीईओ रयान थोर्पे ने कहा कि फरवरी में अभिनेत्रियों की शिकायतें सार्वजनिक होने के बाद उन्हें कंपनी के सर्वर से कई वीडियो क्लिप डिलिट करने के लिए कहा गया था.

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारम्बे के अनुसार, कुंद्रा के साथ बख्शी और उमेश कामत के संबंध जगजाहिर हैं, जो कुंद्रा के पूर्व सहायक और मामले का एक अन्य आरोपी है. भारम्बे का कहना है कि कामत भारत में केनरिन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था. प्रोडक्शन कंपनी केनरिन, कथित तौर पर कई एजेंटों से अनुबंध के तहत वयस्क फिल्में बनवाती थी. पुलिस अधिकारी कहते हैं कि कामत और मॉडल-अभिनेत्री गहना वशिष्ठ वीडियो शूट करने के बाद उसे डिजिटल रूप में केनरिन को भेजा करते थे.

'अश्लील नहीं, कामोत्तेजक'

वैसे, राज कुंद्रा और गहना वशिष्ठ दोनों ने दावा किया है कि हॉटशॉट्स की सामग्री को 'अश्लील' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. वशिष्ठ कहती हैं, ''मैंने राज के साथ तीन फिल्मों में काम किया. हमने कामोत्तेजक, बोल्ड फिल्में बनाईं लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म 'पोर्न या अश्लील' की श्रेणी में नहीं आती.'' वशिष्ठ ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ''अगर आप देखें, तो नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे ऐप पर इससे कहीं अधिक बोल्ड सामग्री है... पुलिस ने गलत व्याख्या की है.'' कुंद्रा के वकील अबाद पोंडा कहते हैं, ''फिल्म के किसी भी दृश्य में दो व्यक्तियों को संभोग में लिप्त नहीं दर्शाया गया है.''

इससे इरोटिका (कामोत्तेजक) बनाम पोर्नोग्राफी (अश्लीलता) पर एक अदद बहस छिड़ गई है. दोनों के बीच फर्क क्या है और कुंद्रा की फिल्में इनमें से दरअसल किस श्रेणी में रखी जा सकती हैं?

निजी स्थलों पर अश्लील सामग्री देखना गैर-कानूनी नहीं है. हालांकि, यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो कानून) के अनुसार, ऐसी अश्लील फिल्में देखना, रखना या डाउनलोड करना अपराध है जिनमें बच्चों को फिल्माया गया हो. साथ ही, आइपीसी की धारा 354सी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ई

में बलात्कार का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के लिए सजा का प्रावधान है. आइटी अधिनियम की धारा 67 भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में 'अश्लील सामग्री' के उत्पादन, वितरण, प्रसारण और प्रकाशन को प्रतिबंधित करती है. इस अपराध में तीन साल तक की कैद और/या 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. विदेशों में पंजीकृत पोर्नहब जैसी वेबसाइट भारतीय कानून के दायरे में नहीं आती हैं.

तीन महिला कलाकार कुंद्रा के खिलाफ, खुलकर सामने आई हैं. मॉडल सागरिका सुमन का कहना है कि उन्हें नग्न ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया था. सुमन कहती हैं, ''जब मैंने पूछा कि निर्माता कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह राज कुंद्रा की कंपनी है.'' पूनम पांडे ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि 2019 में कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार के बाद उन्हें बहुत परेशान किया गया था. पांडे ने बताया, ''किसी ने मेरा फोन नंबर सोशल मीडिया पर यह बताते हुए डाल दिया कि अगर वे मुझे फोन करेंगे तो मैं उनके लिए कपड़े उतार दूंगी.'' अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने इस साल 21 जुलाई को एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कुंद्रा के आर्म्सप्राइम के खिलाफ सबसे पहले उन्होंने शिकायत की थी.

अदालत में मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए कुंद्रा की हिरासत की मांग की और दावा किया कि हॉटशॉट्स और हॉटहिट पर कई वीडियो में दो व्यक्ति रति-क्रिया में लिप्त हैं. इससे यह दलील खारिज होती है कि ये कामोत्तेजक हैं, अश्लील या पोर्न नहीं.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अन्य महिलाओं ने कहा कि निर्माता उनसे कहा करते थे कि अगर वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और इन फिल्मों में अभिनय करने से इनकार करती हैं, तो उन्हें फिल्म उद्योग में काम का कभी मौका नहीं मिल पाएगा. छह महिला शिकायतकर्ताओं ने हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रतियां पेश की थीं, जो उन्होंने वशिष्ठ और अन्य आरोपियों के लिए साइन की थीं. इन सहमति पत्रों में कहा गया है कि महिलाओं ने ''अंतरंग, कामुक, बोल्ड सीन, लिप लॉक, स्मूच सीन, टॉपलेस/न्यूड सीन'' करने के लिए ''अपनी इच्छा से और बिना प्रोडक्शन हाउस के किसी दबाव में'' सहमति जताई थी. महिलाओं के अनुसार, उन्हें कथित तौर पर 12 से 20 मिनट की अवधि के अंतरंग दृश्य करने के लिए 10,000 रुपए का भुगतान किया गया था. सहमति फॉर्म में प्रोडक्शन हाउस का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वेब सिरीज का नाम या सामग्री के रिलीज का विवरण वगैरह नहीं लिखा था.

महामारी के दौरान लोगों के अपने घरों तक सीमित रहने के कारण, आकर्षक पोर्न उद्योग आश्चर्यजनक रूप से फला-फूला है. दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली वयस्क फिल्म वेबसाइट पोर्नहब के अनुसार, मार्च 2020 में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से भारत में पोर्न की खपत में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें से ज्यादातर दर्शक 28-34 आयु वर्ग के बीच के हैं. उसी दौरान पूरी दुनिया में पोर्न की खपत में औसतन वृद्धि भारत के मुकाबले एक-तिहाई, मात्र 10.5 प्रतिशत ही रही. 2020 में, भारत ने सबसे अधिक पोर्न देखने वाले देशों की वैश्विक सूची में कनाडा को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. इस सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्रिटेन है. पोर्नहब डेटा देसी पोर्न की मांग में तेज वृद्धि के ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है.

पैसा कैसे बनता है

पुलिस ने यह भी पाया है कि इन फिल्मों के निर्माण में अर्जित मुनाफा बहुत ज्यादा है. उदाहरण के लिए, 20 मिनट का वीडियो केवल 3 लाख रुपए में बनाया जा सकता है जिसमें शूटिंग की जगह की लागत और कलाकारों तथा कैमरामैन को किया गया भुगतान, सब शामिल है. लेकिन इसे बेचकर निर्माता एक महीने में 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं.

प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने दावा किया है कि हॉटशॉट्स के 20 लाख ग्राहक थे जो ऐप पर मौजूद वीडियो सामग्री देखने के लिए प्रति माह 100 रुपए के सदस्यता शुल्क का भुगतान कर रहे थे. पुलिस को कुंद्रा के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सऐप ग्रुप चैट भी मिली जिसमें वह कथित तौर पर इन फिल्मों के निर्माण के जरिए हो रही अपनी कमाई की चर्चा की है. एक जांच अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''व्हाट्सऐप ग्रुप चैट से पता चलता है कि कुंद्रा ने किसी व्यक्ति को 12 लाख डॉलर में 119 वीडियो बेचने की योजना बनाई थी. यह सौदा हुआ या नहीं, हम इसका पता लगा रहे हैं.''

23 जुलाई को कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि कुंद्रा बॉलीफेम मीडिया लिमिटेड नाम से एक और कंपनी चलाता है. कुंद्रा ने हॉटशॉट के कंटेंट को इसी कंपनी में शिफ्ट करने की योजना बनाई थी. चार्जशीट में कुंद्रा का एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि बॉलीफेम 2023-24 तक 30 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ 146 करोड़ रुपए की कमाई कर सकता है.

मुंबई पुलिस का दावा है कि कुंद्रा को 3 फरवरी को मोबाइल ऐप हॉटहिट से 2.7 लाख रु. मिले. यह ऐप गूगल प्लेस्टोर पर 'मैच्योर' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत है. उन्हें इसी ऐप से 23 जनवरी को 95,000 रु., 20 जनवरी को 1 लाख रु., 13 जनवरी को 2 लाख रु. और 10 जनवरी को 3 लाख रु. मिले.

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से अश्लील सामग्री के धंधे पर सुर्खियां हैं. कुंद्रा मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. पुलिस की जांच से लगता है कि कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन इसे अदालत में साबित करना होगा. ■

अश्लील फिल्मों का वैश्विक जाल

90 अरब डॉलर
मूल्य का अश्लील फिल्मों का कारोबार विश्वस्तर पर होता है

28 करोड़
वेबसाइटें पोर्न की दुनिया भर में

25%
इंटरनेट ट्रैफिक, भारत में अश्लील फिल्मों को खोजने से आता है

28,258
व्यक्ति दुनियाभर में हर सेकंड अश्लील फिल्में देख रहे होते हैं

89%
अश्लील फिल्मों के भारतीय उपभोक्ता, इन फिल्मों को देखने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं

10%
हिस्सा कुल वैश्विक अश्लील फिल्म कारोबार में, अमेरिका का है.

68 करोड़
बार इंटरनेट पर वैश्विक स्तर पर प्रति दिन अश्लील फिल्में सर्च की जाती हैं

स्रोतः वेबरूट, पोर्नहब

अनसुनी कहानियां सुनाएंगी निर्माता बनीं अभिनेत्रियां

नवीन कुमार

तापसी पन्नू और ऋचा चड्ढा सरीखी एक्ट्रेस ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्में बनाने की घोषणा की तो सिने जगत की इनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं. उम्मीद है कि अब ये अपनी फिल्मों में नई कहानी कहेंगी. युवा लेखक-निर्देशक राजीव उपाध्याय के शब्दों में, ''इंडस्ट्री में तापसी और ऋचा जैसी महिला प्रोड्यूसर के आने से सबसे बड़ा बदलाव कहानी में होगा. कहानियां जो समाज ने पहले नहीं देखी हैं, वे इनकी फिल्मों में दिखाई जाएंगी. बॉलीवुड पुरूष प्रधान फिल्में बनाता है. जब ये महिलाएं प्रोड्यूसर बनकर आ रही हैं तो इनकी कहानियों में औरत की एक अहम भूमिका होगी.'' तापसी और ऋचा जैसी एक्ट्रेस का ताल्लुक फिल्मी घराने से नहीं है और वे अभिनय के दम पर अपना खास मुकाम बना चुकी हैं. निश्चित रूप से उनके सामने बाहरी होने और फाइनेंसर तलाशने की भी चुनौतियां रहेंगी. फिल्म व्यवसाय विशेषज्ञ नरेंद्र गुप्ता का नजरिया कुछ ऐसा है, ''इनको इंडस्ट्री में काम करते हुए 10-15 साल हो गए हैं. इसलिए फाइनेंस मिलने में दिक्कत नहीं है.'' फिल्म व्यवसाय विशेषज्ञ अतुल मोहन कहते हैं, ''अब फाइनेंस कोई बड़ी समस्या नहीं है यहां. ऐक्टर या ऐक्ट्रेस जब बताते हैं कि वे खुद ही प्रोड्यूसर हैं तो फाइनेंसर आगे आता है. इस समय सबको स्टूडियो ही फाइनेंस करता है.'' उपाध्याय की राय में, ''तापसी और ऋचा के नाम पर फिल्में चलती हैं इसलिए इनके नाम पर पैसे लगाने वाले हैं.''

लगभग डेढ़ साल के महामारी के दौर में ज्यादातर प्रोड्यूसर नई फिल्म शुरू करने से बच रहे हैं. लिहाजा, सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे वक्त में तापसी और ऋचा का प्रोड्यूसर बनना क्या मौके का फायदा उठाने वाली बात है? इस पर अतुल दो टूक कहते हैं, ''यह मौके की ही बात है. थिएटर भले ही बंद हो लेकिन डिजिटल बाजार तो खुला है.'' गुप्ता कहते हैं, ''बड़े स्टार के लिए समस्या नहीं है. छोटे और मझोले ऐक्टर को परेशानी हो सकती है. तापसी और ऋचा से इंडस्ट्री को ही फायदा होगा. लोगों को काम मिलेगा.''

लेकिन उपाध्याय के विचार थोड़े अलग हैं, ''मौके पर प्रोड्यूसर बनने वाली बात नहीं है. मुझे लगता है कि तापसी अब स्टार हैं. हम अक्षय कुमार की तरह उनको नहीं देख सकते. मगर यह सच है कि वे कामयाब हैं, उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करना बड़ी बात नहीं है. उसी तरह ऋचा के बारे में भी कहा जा सकता है.'' वैसे, इसी महामारी में भट्ट परिवार की बेटी आलिया भट्ट भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोलकर *डार्लिंग्स* फिल्म बनाने की घोषणा कर चुकी हैं. यह दीगर बात है कि उन्हें तापसी या ऋचा की तरह फिल्म बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. उनका परिवार फिल्म निर्माण के में लंबे अर्से से है. भट्ट परिवार की पूजा भट्ट भी सफल प्रोड्यूसर रह चुकी हैं.

इंडस्ट्री में तापसी खुद आउटसाइडर हैं इसलिए उनके प्रोडक्शन हाउस के नाम आउटसाइडर्स फिल्म्स पर चर्चा भी हो रही है. लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी फिल्म में प्रतिभाशाली ऐक्टरों को ही मौका मिलेगा. अपने प्रोडक्शन की पहली थ्रिलर फिल्म *ब्लर* में तापसी खुद काम कर रही हैं. उनकी फिल्म को ज़ी स्टूडियो प्रमोट कर रहा है, जिससे उन्हें फाइनेंस की समस्या नहीं होगी. ऋचा को एक पंजाबी शॉर्ट फिल्म *खून आली चिट्ठी* प्रोड्यूस करने का भी अनुभव है. अब वह पुश बटन स्टूडियो नामक अपने बैनर तले हिंदी फिल्म *गर्ल्स विल बी गर्ल्स* बनाने में जुट गई हैं. अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने

तापसी पन्नू
कंपनी:
आउटसाइडर्स फिल्म्स
बैनर की पहली फिल्म : ब्लर

ऋचा चड्ढा
कंपनी:
पुश बटन स्टूडियो
बैनर की पहली फिल्म:
गर्ल्स विल बी गर्ल्स

अनुष्का शर्मा
कंपनी : क्लीन स्लेट फिल्म्स
आने वाले प्रोजेक्ट: माई (वेब सिरीज), काला (डिजिटल फिल्म)

दीपिका पादुकोण
कंपनी: का प्रोडक्शंस
आने वाली फिल्म:
'83 (को प्रोड्यूसर)

गुनीत मोंगा
कंपनी : सिख्या एंटरटेनमेंट
आने वाली फिल्म:
यू टर्न (बालाजी फिल्म्स के साथ)

फिल्म के लिए स्क्रिप्ट बर्लिनले स्क्रिप्ट स्टेशन लैब से लिया है. लैब दुनियाभर से 10 चुनिंदा स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को देती है. ऋचा की इस फिल्म से कुछ और को-प्रोड्यूसर जुड़ गए हैं. स्पष्ट है कि तापसी और ऋचा ने प्रोड्यूसर बनने से पहले फिल्म निर्माण बाजार को अच्छे से खंगाल लिया है. उपाध्याय के शब्दों में, ''ऋचा जिस तरह की फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं और उन्होंने अपनी फिल्म का जो नाम रखा है *गर्ल्स विल बी गर्ल्स*, यह किसी फीमेल प्रोड्यूसर के ही बस की बात है. तापसी और ऋचा से पहले भी कथित बाहरी अभिनेत्रियों ने भी फिल्में बनाई हैं. मगर उनमें से कई एक या दो फिल्मों के बाद और फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं. मसलन, प्रियंका चोपड़ा ने *द स्काइ इज पिंक* और *बम बम बोल रहा है काशी* (भोजपुरी), लारा दत्ता ने *चलो दिल्ली*, दिया मिर्जा ने *लव ब्रेकअप्स जिंदगी*, विद्या बालन ने *नटखट*, हिना खान ने *लाइंस*, नीतू चंद्रा ने *वन्स अपॉन ए टाइम इन बिहार*, ऐश्वर्या राय ने *दिल का रिश्ता*, प्रीति जिंटा ने *इश्क इन पेरिस* और अमीषा पटेल ने *देसी मैजिक* बनाई थी. लेकिन दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा अब भी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं. दीपिका फिल्म '83 की को-प्रोड्यूसर हैं और अनुष्का वेब सिरीज बना रही हैं.

हाल के वर्षों में महिला प्रोड्यूसर के रूप में अलग पहचान बनाने वालों में गुनीत मोंगा, अनुष्का और दीपिका के नाम हैं. वे भी इंडस्ट्री की बेटियां नहीं हैं. लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वे सफल प्रोड्यूसर हैं और उन्हें फिल्में बनाकर दर्शकों के दिलों में बसाना भी आता है. अतुल बताते हैं, ''महिला प्रोड्यूसर की फिल्में हीरोइन ओरिएंटेड होती हैं. पुरुष निर्माता मसाला फिल्मों में पैसे लगाते हैं. ऐक्ट्रेस प्रोड्यूसर के दिमाग में यह जरूर रहता है कि करियर में एकाध फिल्म ऐसी करें जिसके लिए उन्हें याद किया जाए. दीपिका की बात होगी तो *छपाक* जरूर याद आएगी. अनुष्का *एनएच 10* से याद आती हैं. जब ऐक्ट्रेस अपनी फिल्म में ऐक्टिंग करेंगी तो उन्हें अपनी अदाकारी दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा.'' उपाध्याय की राय में, ''जब ये अभिनेत्रियां निर्माता बनती हैं तो इनकी कहानियों में औरत की अहम भूमिका होगी. अनुष्का ने जो फिल्में बनाईं उनमें अभिनय किया जैसे, *एनएच 10* और *परी*. इसके अलावा *बुलबुल* जो डिजिटल पर आई. ये सब फीमेल सेंट्रिक कहानियां हैं.''

आने वाले सालों में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां गुनीत मोंगा जैसी सफल प्रोड्यूसर भी हैं जो अभिनेत्री नहीं हैं. लेकिन उनका फोकस हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों के निर्माण पर ज्यादा रहता है. *गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंचबॉक्स, मसान, जुबान, 1232 केएमएस* जैसी फिल्में भी गुनीत ने प्रोड्यूस की हैं. गुनीत डॉक्यूमेंटरी फिल्म *पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस* की कार्यकारी निर्माता भी हैं. फिल्म को 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला. दूसरी ओर जो एक्ट्रेस प्रोड्यूसर बनकर दोहरी भूमिका निभा रही हैं वे अक्षय कुमार, सलमान खान या शाहरुख खान की तरह महंगे बजट की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उनका मकसद अच्छी कहानी वाली महिला प्रधान फिल्म बनाना है. बड़ी फिल्में कौन बनाएंगी, दीपिका पादुकोण जो स्टार हैं. अनुष्का बना सकती हैं. तापसी भी बना सकती हैं अगर वे चाह लें तो. ऐक्ट्रेस-प्रोड्यूसर की वकालत करते हुए उपाध्याय कहते हैं, ''वे पैसे कमाने के लिए प्रोड्यूसर नहीं बनी हैं. उनको वे कहानियां कहनी है जो नहीं कह पाई हैं.'' ■

किताबें

विवादास्पद युग का संपूर्ण विश्लेषण

हेमंत शर्मा

मैकियावेली ने कहा था कि राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती. ख्रुश्चेव मानते थे कि नेता दुनिया भर में एक जैसे होते हैं. वे वहां भी पुल बनाने का वादा कर देते हैं जहां नदी न हो. जॉर्ज ऑरवेल का मानना था कि राजनीति की भाषा में झूठ, सच की तरह और हत्यारा इज्जतदार दिखता है. आज की राजनीति भी झूठ और आभासी चर्चाओं पर आधारित है. इसे आप उत्तर सचाई (पोस्ट ट्रुथ) का जमाना भी कह सकते हैं.

राजनीति की इसी उत्तर सचाई की परतें खोलती संतोष भारतीय की यह किताब सामने आई है *वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं*. किताब 1989 से 2009 के बीच भारतीय राजनीति के हाहाकारी कालखंड का उत्तर सच बताती है. हमें अनेक राजनैतिक षड्यंत्रों की अंधी सुरंग से निकाल दबी-छुपी सूचनाओं के हाइवे पर ले जाती है. ऐसे में यह 'उत्तर सच', 'उत्तरोत्तर सच' बनता जाता है. यह उस दौर की राजनैतिक कथाओं का खुलासा है जब संतोष भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के इर्दगिर्द या भीतर पाए जाते थे. उससे पहले उनकी गिनती देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में होती थी जिनमें अपने समय और समाज को पढ़ने का माद्दा था. कबीर आंखन की देखी को मानते थे, कागद की लेखी को नही. संतोष भारतीय की यह किताब उनकी आंखन देखी और कानन सुनी है.

किताब भारतीय राजनीति के उस 'ग्रे एरिया' पर रोशनी डालती है, 1989 से 2004 के बीच जो सबसे ज्यादा हलचल भरे थे. भारत के राजनैतिक इतिहास की कई 'बीज प्रवृत्तियां' इसी दौर में पड़ीं. आजादी के बाद भारतीय राजनीति के तीन प्रस्थान बिंदु, 1969 में कांग्रेस की टूट, 1977 का गैर-कांग्रेसी प्रयोग और फिर 1989 में बोफोर्स तोप से निकली बवंडरी राजनीति, माने जा सकते हैं. राजनीति के इस युग में कुछ हैरान करने वाली साजिशें थीं, विरोधियों के बीच रहस्यमय समझदारियां थीं, कुछ अनसुलझे रहस्य थे, कुछ अनिर्मित पुल थे. किताब 1989 से 2004 तक की राजनीति की इन्हीं अनकही कहानियों का खुलासा करती है.

वह दौर था जब 'मंडल' का मुकाबला 'कमंडल' कर रहा था. एक से समाज बंट रहा था, दूसरे से संप्रदाय. आर्थिक फिसलन बेकाबू थी. जाति राजनीति की कटुता में समाज टूट रहा था. कुर्सी के लिए सांप्रदायिक राजनीति पूरी नंगई पर थी. राजनैतिक समाज घोटालों में उलझा था. यह किताब इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाती है.

शीर्ष पत्रकार और बाद में सांसद के नाते संतोष भारतीय इस इतिहास का हिस्सा रहे हैं. वे घटते इतिहास के चश्मदीद थे. कहीं-कहीं किरदार थे. सहभागी थे. कुछ अभियान में शामिल थे, तो कुछ के सूत्रधार थे. संतोष की इन भूमिकाओं की विलक्षणता ही इस किताब की प्रमाणिकता है. राजीव गांधी, वी.पी.सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी उस कालखंड की राजनीति के केंद्र में थे. इनकी राजनीति आपस में कितनी गुथी हुई थी, कैसे ये पांचों एक दूसरे के आमने-सामने खड़े रह कर एक दूसरे से ताकत पाते थे और जाहिर तौर पर एक-दूसरे के मुखालिफ भी थे. इनके अंतर्संबंध क्या थे? इस पर भी किताब में रोशनी डाली गई है.

यह किताब उन घटनाओं को भी बेपर्दा करती है जिसके कारण राजीव गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा. जिन वी.पी. सिंह की वजह से राजीव गांधी की सत्ता गई, उन्हीं वी.पी. सिंह ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैसे एड़ी-चोटी एक कर घटनाओं का रुख मोड़ दिया. जिन चंद्रशेखर से मिलकर वी.पी.सिंह ने राजीव गांधी की सत्ता उखाड़ने की मुहिम छेड़ी, वही चंद्रशेखर वी.पी. सिंह की जड़ क्यों खोदने लगे? वी.पी. सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी प्रधानमंत्री की पसंद जानने के बाद क्यों हो गए सोनिया गांधी के साथ? किताब में इस समूचे घटनाक्रम की पटकथा है जिसमें दृश्य साथ-साथ चलते हैं. *वी.पी. सिंह, सोनिया गांधी और मैं*—में इतिहास की नीरसता नहीं है. कथा की रोचकता है. आप इसे 'इतिहास कथा' भी कह सकते हैं. किताब कहीं से पढ़ना शुरू करें, आप फिर लगातार पढ़ने लगेंगे, क्योंकि किताब का हर पन्ना नई कहानी सुनाता है.

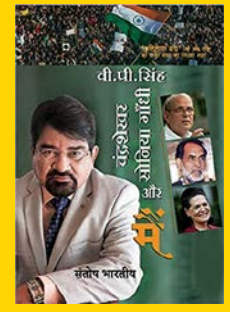

वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं
प्रकाशक: वारियर्स विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस
मूल्य: 999 रुपए

यह किताब 1989 से 2004 तक की राजनीति की कई अनकही कहानियों का खुलासा करती है

सैंतीस अध्यायों में बंटी किताब भविष्य के दो प्रधानमंत्रियों की अंतरंग मुलाकात से शुरू होकर बोफोर्स, अमिताभ बच्चन, रेखा, इलाहाबाद उपचुनाव, वी.पी. सिंह की बनती-गिरती सरकार, चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री बनना, राम जन्मभूमि आंदोलन, आरक्षण की आग से लेकर सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद से इनकार की कथाओं को समेटे हुए है. किताब में इससे निकलती दर्जनों अंतर्कथाएं भी हैं.

किताब में लेखक का वी.पी.सिंह और चंद्रशेखर के प्रति आग्रह दिखता है. वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर को लेकर किताब लगातार नरम है. दोनों की राजनैतिक नाकामियों, विफलताओं और राजनैतिक कमजोरियों को नहीं उकेरा गया है. दोनों के राजनैतिक सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को संतोष भारतीय इंगित नहीं करते.

संतोष जे.पी. आंदोलन की उपज रहे हैं. मैंने उन्हें जे.पी. के जुलूस में ''जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है'' गाते सुना है. पर उन्होंने उस आंदोलन और उसके बाद की राजनीति पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली है.

यह किताब भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद युग का संपूर्ण विश्लेषण है जो रोचकता, बेबाकी और भाषा के प्रवाह से लबालब है. उत्तर मंडल राजनीति की जटिलताओं को समझने और सर्वाधिक उथल-पुथल वाले उस दौर को जानने के लिए यह जरूरी किताब होगी. ■

एक लेखक दो तरह के नाटक

संगम पांडेय

नाटककार जयवर्धन ने अपने नए नाटक 'एक और मीटिंग' को व्यंग्य-नाटक लिखा है, जबकि बेहतर होता इसे प्रहसनात्मक व्यंग्य लिखा जाता. इसमें नुक्कड़ नाटकों जैसी लाउडनेस है जिसमें पात्र दुनियादारी के शिष्टाचार का ज्यादा दिखावा नहीं करते. नेताजी यहां मीटिंग के मिनट्स पहले से ही लिखकर लाए हुए हैं और एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जो सरकार की तरफ से प्रस्तावित चार करोड़ के नाटक को दो करोड़ में करने को तैयार हैं. उनके नाटक का नाम है 'साजन सीनियर सिटिजन, सजनी ट्वेंटी वन.' ऐसे में स्वागत-संबोधन जैसी औपचारिकता यहां खुद ही हास्य की एक तरकीब हो गई है, क्योंकि चपरासी भी यहां मीटिंग के बहाने पत्रकार मैडम से हाथ मिला लेने की अपनी मंशा सबको बता रहा है. इस तरह पात्रों का रवैया हकीकत पर चढ़ी झूठमूठ की कलई भी उतार देता है और इससे जो सिचुएशन पैदा होती है उसमें हास्य उतना नहीं है, जितना चमत्कार है.

यह नाटक जयवर्धन के पिछले नाटक 'अर्जेंट मीटिंग' का एक्स्टेंशन है, जिसमें संस्कृति की दुनिया में होने वाली बंदरबांट को उजागर किया गया है. मीटिंग का नायक एक सीनियर और बोहेमियन थिएटर डायरेक्टर नारंग है, जो झोले में दारू रखे हुए है और जो मन में आता है वह दोटूक बोलता है. उसकी एंट्री नाटक में थोड़ी देर से लेकिन धमाकेदार है. उसका नायकत्व इतना जाहिर है कि किसी अर्थ में वही नाटक की कमजोरी बन गया है. उसकी कही बातें इतनी स्पष्ट हैं कि सपाट हो गई हैं, जबकि व्यंग्य में वक्रता होनी जरूरी है. नाटक में ऐसी वक्रताएं जुगनुओं के रूप में हैं, जो रह-रह कर कौंधती हैं-जैसे कि मंत्री महोदय पूछते हैं, 'मैकबेथ निर्देशक का नाम है?' या नाटक 'साजन सीनियर सिटिजन, सजनी ट्वेंटी वन' को प्रेरक मानकउसे सीनियर सिटिजन डे पर कराने का सुझाव देते हैं.

बाकी दुनियाओं की तरह कला-संस्कृति की दुनिया का भी एक अंदरूनी सच है, जहां झूठी महानताएं, जोड़-तोड़ से हासिल किए फायदे आदि तत्व काम करते हैं. जयवर्धन इस नाटक में उन्हें खटाक से तोड़ देने की कोशिश करते हैं. इस लिहाज से नाटक काफी डिटेलिंग में जाता है. उसमें अनुवादक, अभिनेता, क्रिटिक आदि कई तरह के किरदार हैं. और इन किरदारों के बरक्स नेता है, जिसका इस गोरखधंधे को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है. नाटककार ने इन सारे पहलुओं को नाटक में बुन दिया है. जाहिर है, आगे का काम नाटक निर्देशक का है कि वह इन पहलुओं और किरदारों को कितना रोचक और उपयोगी बना पाता है.

ज्यादातर कॉमिक फ्लेवर में लिखने वाले जयवर्धन का इसके अलावा एक सीरियस ढंग से लिखा गया नाटक 'कालपुरुष' भी हाल में छपकर आया है, जो कि वीर सावरकर के जीवन पर केंद्रित है. देशभक्ति से ओतप्रोत इस नाटक के 15 दृश्यों में उनका जीवनवृत्त पेश किया गया है. सावरकर की शुरुआती क्रांतिकारी गतिविधियों से शुरू होकर गांधी की हत्या के वक्त तक उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं यहां एक सिलसिले में पेश आती हैं. गोडसे के बारे में सावरकर कहते हैं- 'गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की शारीरिक हत्या नहीं की, बल्कि मेरी राजनीतिक-सामाजिक हत्या की है.' लेकिन इस हत्याकांड की साजिश में अपना नाम आने से वे दुखी हैं, और कहते हैं-'क्या लोगों को नहीं पता कि इसकी पृष्ठभूमि में कौन है? कौन मेरे नाम और काम से भयभीत है?... लंदन में जब मैं घूम-घूमकर हिंदुस्तानी छात्रों को संगठित कर रहा था तो ये जनाब संगीत-नृत्य का आनंद उठा रहे थे. इनको इंडिया हाउस आने की मनाही थी.' जाहिर है, 'ये जनाब' यहां नेहरू के लिए कहा गया है. नाटक यूं तो काफी आसान तरह से लिखा गया है, पर इतना आसान भी नहीं कि उलझे प्रसंगों को उसमें छोड़ दिया गया हो. इसके लिए गोडसे-सावरकर संवाद का एक पूरा दृश्य नाटक में है. इसी तरह एक पूरा दृश्य गांधी-सावरकर संवाद का भी है, जिसमें दोनों के मतांतर के तीखेपन को नरम शैली में सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है. लेकिन जहाज से भागने, मुकदमे और अंडमान की सेलुलर जेल के दृश्यों के विवरण निश्चय ही ज्यादा बारीकी से पिरोए गए हैं.

इस नाटक को हम सावरकर के जीवन का एक मॉडरेट पाठ कह सकते हैं, जिसमें उनकी देशभक्ति तो पूरे तौर पर है पर उनके हिंदुत्ववादी विचार वास्तविक से कहीं ज्यादा संयमित रूप में दिखाई देते हैं. कुल मिलाकर सावरकर का वैचारिक पक्ष इसमें किंचित स्थूल रूप से ही आ पाया है, जिसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि नाटककार ने विषय की गहराई से जुड़े जोखिम से बचने की कोशिश की है; और दूसरी यह कि आम दर्शक के लिहाज से आसान कलेवर लेखक को ठीक लगा हो. फिर भी, यह एक पात्र बहुल और दृश्यों की विविधता वाला नाटक है. कई जगह स्थितियों के ब्योरों को उद्घोष के जरिए समेटा गया है, जिससे किंचित डॉकु-ड्रामा का पुट भी है. ■

एक और मीटिंग जयवर्धन; संजना बुक्स, डी 70/4, अंकुर एन्क्लेव, करावल नगर, दिल्ली-90; 295 रुपए.

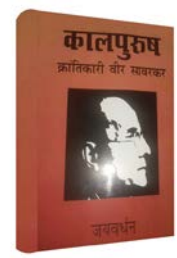

कालपुरुष जयवर्धन; किताबघर प्रकाशन, 48 55-56/24 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2

'एक और मीटिंग' नाटक जयवर्धन के पिछले नाटक 'अर्जेंट मीटिंग' का एक्सटेंशन है, जिसमें संस्कृति की दुनिया की बंदरबाट को उजागर किया गया है. 'काल पुरुष' में सावरकर का किंचित स्थूल रूप उभरता है

सवाल+जवाब

हिंदुस्तान की कहानी

बहुत कुछ उनकी फिल्मों की तरह जबरदस्त है **राकेश ओमप्रकाश मेहरा** की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा *द स्ट्रेंजर इन द मिरर*

आमाद केपरस/गेट्टी इमेजेज

● अपनी किताब में आपने कहानियां बयान की हैं कि किस तरह अमिताभ बच्चन, आमिर खान, गुलजार, हर कोई आपके साथ काम करने को तुरंत राजी हो गए. इसकी क्या वजह थी, आपकी शख्सियत या आपकी प्रतिभा?

ये सब कामयाब शख्सियतें हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया. उनमें से हरेक सिनेमा से प्रेम करता है. मुझे लगता है, उन्होंने मुझमें कुछ ऐसा देखा जो सिनेमा के लिए कुछ करना चाहता था तो उन्होंने मुझे तवज्जो दी, मुझे मौका दिया. मैं भूखा था जब सालों पहले मैं गुलजार भाई के दफ्तर गया, जब मैं अमित जी से मिला और उन्हें *अक्स* की पेशकश की या जब मैंने आमिर खान को *रंग दे बसंती* के लिए टेक्स्ट भेजा. वह भूख वक्त के साथ कई गुना बढ़ी है.

● यह कहना सही होगा कि *रंग दे बसंती* ने 21वीं सदी के भारत को विरोध का एक सांचा दिया? इसे बनाने के 16 साल बाद देशभक्ति का आपका विचार बदला है?

आरडीबी एक ट्रिगर, कैटेलिस्ट, एक तार था जिसके जरिए बिजली दौड़ती थी. सांचा कहना तो ऊंची बात हो सकती है. सही वक्त पर रिलीज करने के लिए वह सही फिल्म थी. फिल्म ने आपको अपने हाथ काले करके राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बनने को प्रोत्साहित किया. सोलह साल बाद मुझे लगता है कि हमारी देशभक्ति में इंसानियत और कायनात भी होनी चाहिए. भारत राष्ट्र के तौर पर अकेला नहीं चमक सकता. हम अब ग्लोबल सिटिजन हैं.

● *आरडीबी* और *दिल्ली-6* में कई प्रमुख किरदार थे. *भाग मिल्खा भाग* और *तूफान* व्यक्तियों के बारे में हैं. बहुत सारे प्रमुख किरदारों वाली फिल्मों से एक हीरो वाली फिल्मों का यह सफर कैसे तय किया?

जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको एहसास होता है कि एक दूसरे से, समाज से और कायनात से जुड़ने की जरूरत है. मगर आपको जिम्मेदार शख्स भी होना होता है. मसलन, *भाग मिल्खा भाग* को लीजिए, इसमें भारत का जन्म भी हुआ और विभाजन भी. दूसरे ढंग से कहें, तो हीरो का सफर देश का सफर बन जाता है.

● *तूफान* गिरकर फिर उठने की कहानी है. आपकी किताब से इशारा मिलता है कि आपकी कहानी भी...

बॉक्सिंग मेरे लिए हमेशा रूपक रही है. जिंदगी की तरह यह आपको मारकर गिरा देती है, फिर बार-बार उठ खड़े होने और पूरी ताकत से वापस आने के लिए मजबूर करती है.

–श्रीवत्स नेवतिया

AKS UNIVERSITY
SATNA

www.aksuniversity.ac.in

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों
का विदेशों में एजुकेशनल टूर
● अमेरिका ● इजरायल ● हांगकांग ● चीन
● मलेशिया ● थाईलैंड ● इंडोनेशिया ● जापान

India's Best Private Universities
India Today Survey-2018
27th Rank in INDIA

Leading University in Central India 2018

University Also Awarded as
- Best Innovative University in Madhya Pradesh 2019
- Best University in Central India 2019
- Best University in IT Infrastructure - 2018

...and Many More Prestegious Awards

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान
(मुख्यमंत्री म.प्र. शासन) द्वारा सम्मानित

ADMISSIONS OPEN
Session : 2021-22
Apply Now : Online/Offline

DGMS द्वारा APPROVED गैस टेस्टिंग Examination Center

COURSES OFFERED

Engineering

Polytechnic / B.Tech.
- Mining ● ME ● CE ● EE ● CSE
- Mining and Mine Surveying
- Mechanical with Mechatronics
- Food Tech. ● Cement Technology
- Agril. Engineering ● Biotech.*
- AI & Data Science

*Eligibility - 12th (Bio/Maths)

M.Tech.
- Mining ● ME ● Biotech. ● CSE

Food Tech.
- Diploma (Food Tech.) (After 10th)
- B.Tech. (Food Tech.) (After 12th - Bio/Maths)

Agriculture
- B.Sc. (Hons.) Ag. ● Diploma Agril Engg.
- B.Tech. (Agril. Engg.)
- M.Sc. (Ag.) - Agronomy / Horticulture / Genetics & Plant Breeding / Plant Pathology/ Soil Science and Agriculture Chemistry/ Agricultural Economics

Computer
- Diploma (CSE) ● B.Sc. IT (Hons.)
- BCA (Hons.) ● DCA ● PGDCA
- B.Sc. CS (Hons.) ● B.Tech.(CSE)
- B.Tech.(CSE) AI & Data Science
- Diploma in Cyber Security & Digital Forensic
- MCA ● M.Tech.(CSE)

Other Faculties & Courses

Management
- BBA (Hons.) ● PGDM
- MBA

Basic Science
- B.Sc. ● M.Sc.

Design
- B.Design

Social Work
- MSW

Humanities
- PG Diploma in Yoga
- B.A. ● M.A. ● M.Sc.

Biotechnology
- B.Sc. ● M.Sc.
- B.Tech. ● M.Tech.

Paramedical
- DMLT

Ph.D.

Pharmacy
- D.Pharm ● B.Pharm
- M.Pharm

Environment
- M.Sc. ● PG Diploma
- Certificate

Commerce
- B.Com. ● M.Com.

Education
- B.Ed. ● D.El.Ed. ● M.A.

LIVE
Recorded Lectures
कोरोना महामारी के कारण
विश्वविद्यालय द्वारा
ऑनलाइन क्लासेस एवं ऑनलाइन परीक्षा

100+ Acres of Campus

100% Placement Assistance

Faculties from IITs/NITs and Reputed Universities

MoUs With Industries & Foreign Universities

Pkg. :₹12 Lac
Pushpendra Kushwaha
(B.Tech. - Cement Tech.)
Abu Dhabi National Cement

Pkg. :₹12 Lac
Er. Anurag Tamrakar
(B.Tech. - CSE)
Syncsort India LLP Hyderabad

Pkg. :₹10 Lac
Sanjay Yadav
(B.Tech. - ME)
Johnson & Johnson, Malaysia

Assistant Director
Directorate of Env., Govt.of UP
Mohd. Rahib
(B.Tech. - Mining)

Our Students have been Placed in Top Notch Companies

...and many more

8889737776
Toll Free : 1800 2700 776

Sherganj, Panna Road, SATNA (M.P.) 8889207776, 8889237776

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE